चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 14 अप्रैल–20 अप्रैल 2014 | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

बीजेपी का अंतर्विरोध

सभी फोटो– *प्रभात पाण्डेय*

संतोष भारतीय

मा न लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे. जिस तरह उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है और जिस तरह का उनका प्रचार चल रहा है, वह दर्शाता है कि सारा देश उनके साथ है. बस, थोड़ी-सी कसर सर्वे रिपोर्ट्स बता रही हैं. भारतीय जनता पार्टी को अकेले 170 से 180 सीटें और सहयोगियों के साथ एनडीए की कुल सीटें 220 से 230. कोई भी सर्वे 230 से आगे नरेंद्र मोदी के एनडीए को नहीं ले जा पा रहा है. दरअसल, यह एनडीए भाजपा का नहीं है, यह एनडीए नरेंद्र मोदी का है और एनडीए की सीटों की संख्या बढ़ती नहीं दिखाई दे रही है. जो दल एनडीए के साथ जुड़े हैं, उनके पास शिवसेना और अकाली दल को छोड़ दें, तो एक या दो सीटें भी शायद ही उन्हें मिल पाएं. अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, तो देश क्या दृश्य देखेगा, इस पर बात करनी चाहिए. सबसे पहला सवाल कि यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है.

सबसे पहले, यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं. इस चुनाव की एक बड़ी विशेषता है कि देश में दो व्यक्तित्व सामने दिखाई दे रहे हैं. नरेंद्र मोदी ने भाजपा की साख शून्य कर दी है और देश के लोगों को यह बता दिया है कि अगर भाजपा चुनाव लड़ती, तो उसकी सीटें 100 से 125 तक होती. नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें 170 से 180 तक जा सकती हैं. अब तक भाजपा के पास सबसे ज़्यादा सीटें 182 रही हैं. यह अफ़सोस की बात है कि नरेंद्र मोदी सब कुछ करने के बाद यह विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं कि अकेली भारतीय जनता पार्टी 182 की संख्या पार कर पाएगी या नहीं. हम अगर इस बात पर विश्वास करें कि भाजपा 200 सीटें ले आती है और उसके सहयोगी 30 या 35 सीटें ले आते हैं, तो भी उसके कुल साथियों की संख्या 235 या 240 से आगे नहीं होती है. बची हुई 40 सीटें भाजपा के लिए प्राप्त करना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर नहीं है, लेकिन टेढ़ी खीर ज़रूर है, क्योंकि वहां पर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर अभी थोड़ा संशय पैदा हो सकता है.

पहला तथ्य, भारतीय जनता पार्टी की जगह नरेंद्र मोदी नामक शख़्स, जो अपने आप में एक बड़ी पार्टी बन गया है, चुनाव लड़ रहा है और यह सारा काम नरेंद्र मोदी के प्रचारतंत्र ने किया है. नरेंद्र मोदी का प्रचार तंत्र अबकी बार भाजपा सरकार का नारा नहीं दे रहा, बल्कि अबकी बार मोदी सरकार, इसका नारा दे रहा है. इसका मतलब है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में सीटों की किसी भी कमी को लेकर यह चर्चा चलती है कि नरेंद्र मोदी की जगह कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन जाए, जो मौजूदा एनडीए के साथियों के अलावा अनिवार्य सहयोगियों की शर्त के मुताबिक़ हो, तो किसी दूसरे का नाम भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करेगी.

संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत ने यह बात भाजपा के सभी नेताओं को बता दी है कि अगर बहुमत एनडीए का नहीं आता है, तो वह बहुमत लाने के लिए नरेंद्र मोदी की जगह किसी दूसरे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं स्वीकार करेंगे. उन्होंने यह साफ़ कर दिया है कि उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठना पसंद करेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी को बदलने के बारे में नहीं सोचेगी. दरअसल, इसके पीछे संघ की एक पुरानी मान्यता है, जिसके बारे में हम लगातार लिखते रहे हैं. संघ यह मानता है कि भारतीय जनता पार्टी को लालकृष्ण आडवाणी, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी जैसों से मुक्त होना होगा और एक नई भाजपा गढ़नी होगी. पहले उसने इसके लिए बीस साला कार्यक्रम बनाया था, जिसमें उसका मानना था कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अगर हार जाती है, तो इन सारे लोगों को नेतृत्व की कतार से बाहर धकेल दिया जा सकता है. अब उसकी दूसरी रणनीति है कि नरेंद्र मोदी को सामने रखकर इन बाकी लोगों को भारतीय जनता पार्टी से अलग करके नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नया नेतृत्व वर्ग पैदा किया जा सकता है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ख़ालिस सिद्धांतों में भरोसा करता हो. संघ के इस फ़ैसले के पीछे यह सत्य छिपा हुआ है कि अगर नरेंद्र मोदी की जगह किसी दूसरे को स्वीकार्यता के सिद्धांत पर चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए लाया गया, तो पार्टी टूट जाएगी और पार्टी का बड़ा वर्ग, चुने हुए सांसदों का बड़ा वर्ग नरेंद्र मोदी के साथ चला जाएगा, क्योंकि भारत के चुनाव के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ऐसे चुनाव लड़ रही है, मानों उसे ईश्वरीय संकेत मिल गया हो कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे.

नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की एक बुनियादी शर्त है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले 215 सीटों के आसपास जीते और उसके सहयोगी कम-से-कम 30-35 सीटें जीतें, तब बचे हुए निर्दलीय या छोटी पार्टियां, जो 15, 20, 30 सीटें लाती हैं, उसका समर्थन करें, तब भी उसे सामान्य बहुमत ही मिलता है. यहां यह ध्यान देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी ने कभी भी यह अभियान ही नहीं चलाया कि उन्हें दो तिहाई सीटें मिलेंगी. इस अभियान के न चलाने के पीछे मुझे एक आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती है, जो यह कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को 272 सीटें सहयोगियों के साथ लाने में भी शंका है. इसीलिए उन्होंने सामान्य बहुमत का आंकड़ा 272 का नारा दिया है. अब 272 से एक ज़्यादा पर सरकार बनती है, तो 272 से 100 ज़्यादा पर भी सरकार बनती है. लेकिन, भारतीय जनता पार्टी इस नारे का इस्तेमाल नहीं कर पाई. शायद अपनी उसी संगठन और आत्मविश्वास की कमी की वजह से वह यह दावा नहीं कर सकती कि उसे दो तिहाई बहुमत इस बार मिलेगा ही मिलेगा. जब यह दावा नहीं है, तो कैसी मोदी की लहर है, यह सवाल दिमाग में घुमड़ता है. यह सवाल नीतीश कुमार की तरह का सवाल नहीं है, न यह सवाल केजरीवाल की तरह का सवाल है. यह सवाल एक ख़ालिस भारतीय राजनीति की स्थितियों के भीतर से उपजा हुआ सवाल है.

नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो देश में विकास होगा, यह विकास अच्छा ही होना चाहिए. गुजरात में जिन लोगों को विकास नहीं चाहिए, उन्हें विकास के दायरे से बाहर छोड़ दिया गया है. इसकी बात देश के सामने न मीडिया लेकर आया है और न अन्य लोग, लेकिन मैं इसे इस तरह से देखता हूं कि देश का विकास भी गुजरात के विकास की तरह होगा. जब हम नरेंद्र मोदी के साथियों से मिलते हैं, तो उनका यह कहना है कि नरेंद्र मोदी 6 महीने के भीतर कुछ इस तरह की घोषणा करेंगे, जिससे देश का मुस्लिम समाज, जो आज उनके साथ नहीं जाना चाहता या एक बड़ा वर्ग, जो नरेंद्र मोदी से पूर्वाग्रह रखता है या घृणा करता है, वे सारे लोग नरेंद्र मोदी के कायल हो जाएंगे और उनका साथ देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे.

नरेंद्र मोदी के साथियों का यह कथन या उनका यह विश्वास इस देश के भविष्य

(शेष पृष्ठ 2 पर)

घर का डॉक्टर

प्रकृति के अनमोल तत्वों द्वारा तैयार किया गया आयुर्वेदिक तेल
राहत रूह औषधियुक्त जड़ी-बूटियों का सशक्त मिश्रण है।

- सर दर्द
- बदन दर्द
- जोड़ों के दर्द
- सर्दी जुकाम
- जले कटे एवं चर्म रोग
- चक्कर आना (समलवाई)
- दिमाग की कमजोरी
- अनिद्रा में लाभकारी

वर्ष 1881 से निरन्तर सेवा में

हरबंशराम का आयुर्वेदिक तेल
तेल राहत रूह

तिल के तेल से निर्मित

अब पाउच Packing में भी

अन्य उत्कृष्ट उत्पाद

आयुर्वेद रत्न सुपर ठंडा तेल | सुकून शुद्धता और गुणवत्ता कलौंजी की | Herbal Shampoo Anti Hair Fall | Rahat Rooh 100% PURE COCONUT OIL

हरबंशराम भगवानदास आयुर्वेदिक संस्थान प्रा.लि.
website:www.harbanshram.com Customer Care No.- 08447 427 621
जनरल मर्चेन्ट एवं केमिस्ट शॉप में भी उपलब्ध

कांग्रेस ख़त्म होने की कगार पर 03

मुलायम की मुश्किल 05

भारतीय मुसलमान और 2014 का आम चुनाव 10

साई की महिमा 12

बीजेपी का अंतर्विरोध

पृष्ठ एक का शेष

के लिए अच्छा संकेत है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो क्या होगा? अभी तक नरेंद्र मोदी, उनके स्पोक पर्सन अमित शाह या अरुण जेटली या रविशंकर प्रसाद, कोई यह नहीं कहता है कि वे हिंदुस्तान के दबे-कुचले, पिछड़े लोगों, जिनमें मुसलमानों की एक बड़ी संख्या है, के लिए कोई विशेष कार्यक्रम बनाएंगे. वे यह मानकर चल रहे हैं कि वे देश के ग़रीबों के लिए जो कार्यक्रम बनाएंगे, उसी में उनका भी हिस्सा होगा. इसका उदाहरण रविशंकर प्रसाद देते हैं कि गुजरात के गांवों में बिजली आती है, तो मुसलमानों को भी बिजली मिलती है और जब पीने के पानी का सवाल आता है, तो नर्मदा के पानी की वजह से जितना जलस्तर ऊपर उठा है, उससे मुसलमान भी पानी पीते हैं. यह बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन इसे एक दूसरी तरीक़े से देखें. एक घर में एक स्वस्थ बच्चा है और एक मालन्यूट्रीशन से ग्रस्त है, तो क्या दोनों को एक ही तरह का खाना देंगे, एक ही तरह के रहन-सहन का स्तर देंगे? या किसी को टीबी हो गई है, उसकी बीमारी दूर करने के लिए क्या उसकी तरफ़ विशेष ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रमुख नहीं हैं.

मोदी के प्रधानमंत्री न बनने के पीछे कुछ कारण हैं, जो महत्वपूर्ण हैं. पहला कारण पार्टी का अंतर्विरोध है. पार्टी के नेता यह मानते हैं कि पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं और उनमें और नरेंद्र मोदी में एक समझौता हो गया है कि इस बार प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह बनेंगे, नरेंद्र मोदी गुजरात को संभालेंगे और अगली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, राजनाथ सिंह राजनीति से संन्यास ले लेंगे. यह शुद्ध अफवाह हो सकती है, लेकिन जिस तरह का स्वभाव राजनाथ सिंह का है और जिस तरह से वह स्थितियां पैदा करते हैं, उसके अनुसार भाजपा मित्रों का कहना है कि यह अफवाह सत्यता में भी बदल सकती है. लेकिन अंतर्विरोध सिर्फ़ राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी का नहीं, अंतर्विरोध पार्टी के उन सभी लोगों का है, जो सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं. अभी तक भारतीय जनता पार्टी में 2009 तक अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और जोशी जी का सामूहिक नेतृत्व चला था. धीरे-धीरे इन तीन लोगों से बढ़कर नौ लोगों की संख्या हुई, जिनमें अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जसवंत सिंह, वेंकैया नायडू, अनंत कुमार जैसे लोग शामिल थे. इसके नीचे भी एक सीढ़ी तैयार हुई थी, जिसे हम तीसरे दर्जे का नेतृत्व कह सकते हैं, पर अब नरेंद्र मोदी के आने से ऊपर की सारी सीढ़ियां अप्रासंगिक हो गई हैं और नरेंद्र मोदी अकेले पहली, दूसरी, तीसरी कतार के नेता बन गए हैं. दूसरी कतार का भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई नेता है, तो वह अमित शाह हैं. अमित शाह नरेंद्र मोदी के गृहमंत्री बनने वाले हैं. इसलिए मुझे यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो पीढ़ी नेतृत्व की कतार से बाहर जा रही है, वह पीढ़ी अपना आख़िरी दांव आजमाएगी और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने में रोड़ा पैदा करेगी.

दूसरी चीज, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास सहयोगियों के साथ 200 या 220 या 230 सीटें आती हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का भावी सहयोग कहां से आएगा? हालांकि सहयोग मिलने में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी रहेगी, वहां बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं रहेगी. तमिलनाडु में जहां करुणानिधि रहेंगे, वहां जयललिता नहीं रहेंगी. आंध्र में जहां चंद्रबाबू रहेंगे, वहां जगन रेड्डी नहीं रहेंगे. बंगाल में जहां कम्युनिस्ट रहेंगे, वहां ममता नहीं रहेंगी. बिहार में जहां लालू रहेंगे, वहां नीतीश नहीं रहेंगे. हालांकि जिनके मैं नाम ले रहा हूं, इनमें किसे कितनी सीटें मिलेंगी, अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज की स्थिति में ये परस्पर बैरी दिखाई देते हैं. इस स्थिति में नरेंद्र मोदी को सहयोगी मिलना मुश्किल नहीं नज़र आता, लेकिन इन सबमें अगर मुस्लिम वोट कोई फैक्टर है, तो ममता बनर्जी के सामने एक बड़ा सवालिया निशान है कि वह नरेंद्र मोदी का कैसे समर्थन करेंगी या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का कैसे समर्थन करेंगे. उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह नरेंद्र मोदी का कैसे समर्थन करेंगे, पर बची हुई सीटों को लेकर भी नरेंद्र मोदी सरकार बना सकते हैं और इन सारे अंतर्विरोधों पर विजय पा सकते हैं. इसमें कोई संशय मुझे दिखाई नहीं देता है.

नरेंद्र मोदी के पक्ष में 18 से 24 साल की उम्र के नौजवान हैं, वे हर जगह मोदी-मोदी चिल्ला रहे हैं. मोदी ने भी अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से की और उनके उस भाषण से नौजवानों का उनके प्रति आकर्षण बढ़ा. हालांकि, यह आकर्षण राहुल गांधी की तरफ़ होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी अपने भाषण से नौजवानों के मन में कोई आशा नहीं जगा पा रहे हैं. हालांकि आशा नरेंद्र मोदी भी नहीं जगा पा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक चीज स्टैबलिश की है कि वह प्रशासनिक स्तर पर, व्यवस्था संचालन के स्तर पर जितनी गड़बड़ियां हुई हैं, उनको ठीक कर सकते हैं. इसीलिए हिंदुस्तान के गांव में मोदी-मोदी-मोदी और खासकर 18 से 24 साल के लड़के इस चुनाव को बिल्कुल वैसे ही ले रहे हैं, जैसे कॉलेज यूनियन का इलेक्शन होता है. यह नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी आशा है. हालांकि, सरकार बनाने की स्थिति में शायद नरेंद्र मोदी की सहमति से राजनाथ सिंह ने यह फ़ैसला किया कि जो भी दोषी पार्टी छोड़कर आता है, उसे भाजपा में शामिल कर लो. कांग्रेस से आए हुए, आरजेडी से आए हुए लोगों को उन्होंने रखा भी और कुछ लोगों को रखा और निकाला भी. यह स्थिति बताती है कि भाजपा अपने प्रचार अभियान को लेकर, उसके नतीजे को लेकर, बहुत निश्चित नहीं समझती, अन्यथा वह ऐसे किसी शख़्स को अपनी पार्टी में नहीं लेती, जो उनकी पार्टी का नहीं है या कम से कम उस पार्टी का है, जो वैचारिक रूप या राजनीतिक रूप से उसकी प्रबल दुश्मन रही है और इनमें कम से कम

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

दो पार्टियों के नाम तो लिए जा सकते हैं, पहला कांग्रेस का और दूसरा आरजेडी का.

नरेंद्र मोदी के सामने चुनौतियां हैं. भारतीय जनता पार्टी भी उनके लिए चुनौती है. संघ शायद अभी चुनौती नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बाहर जो पक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, वे भी उनके लिए कहीं न कहीं चुनौती साबित होंगे. जिस तरह से अपने भविष्य के साथियों से संपर्क करना चाहिए, उसकी कोशिश अवश्य नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दी होगी. एक चीज ने और शंकाएं पैदा की हैं कि इस बार चुनाव लड़ने के लिए भाजपा ने जितने अभिनेताओं को खड़ा किया है, उतने पहले कभी चुनाव में खड़े नहीं हुए थे. शायद इसके पीछे एक कारण अच्छे उम्मीदवारों का न होना भी हो सकता है, लेकिन दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि इस देश के लोग इतने बेवकूफ हैं कि वे किसी को भी वोट दे सकते हैं, जो उनके यहां कभी आया हो या न आया हो, उसने काम किया हो या न किया हो, उसमें समझदारी हो या न हो. लोग नहीं देखेंगे, चूंकि वह भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का उम्मीदवार है, इसलिए उसे वोट दे देंगे. यह समझ नरेंद्र मोदी और कांग्रेस दोनों में है, लेकिन इस समझ ने हिंदुस्तान के लोगों की उस मानसिकता को ज़रूर उजागर किया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के लोगों को चुनाव के समय आसानी से बेवकूफ या मूर्ख बनाया जा सकता है. अब यहां देश के लोगों को फ़ैसला करना है कि क्या वे सचमुच मूर्ख बन रहे हैं या बनना चाहते हैं? अगर बनना चाहते हैं, तो उनकी कोई मदद नहीं कर सकता और अगर नहीं बनना चाहते, तो यह चुनाव भारतीय मतदाताओं के दिमाग का एक कड़ा परीक्षण भी साबित हो सकता है. नरेंद्र मोदी के पक्ष में सबसे बड़ी बात कांग्रेस पार्टी का ढुलमुलपन है. कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी का सामना करने का सांगठनिक तौर पर कोई प्रयास ही नहीं किया. कांग्रेस पार्टी के दो सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के अंतर्विरोधों को न समझ पाए और न उनका फ़ायदा उठा पाए. देश में अच्छी योजनाएं कैसे भ्रष्टाचार बढ़ाने में सहायक होती हैं, इसका कांग्रेस पार्टी ने सबसे अच्छा उदाहरण देश के सामने रखा है. नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच की तुलना में लोग नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं. उच्च वर्ग, जिनमें प्रमुख बैंकों के अधिकारी एवं आर्थिक जगत के बड़े लोग शामिल हैं, तो यह कह रहा है कि हमें एक हिटलर जैसा शख़्स चाहिए, जो इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सके और उनका अर्थव्यवस्था सुधारने से मतलब इस देश में बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था का पैर फैलाना है, ताकि उसके विरोध में कोई आवाज़ न उठ सके. इसके लिए वे नरेंद्र मोदी को सर्वथा उपयुक्त व्यक्ति समझते हैं. इसलिए उच्च मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग में नरेंद्र मोदी का नाम देश में भविष्य के सफल प्रशासक के रूप में लिया जा रहा है. राहुल गांधी को वे बच्चा मानते हैं और उनका मानना है कि यह देश तबाह हो जाएगा, अगर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री पद पर आते हैं.

मैंने रविशंकर प्रसाद से पूछा कि आख़िर भाजपा कब अकेले सरकार बनाने की बात करेगी या वह सहयोगियों की शर्तों पर ही सरकार बनाने की योजना बनाती रहेगी? इसका जवाब रविशंकर प्रसाद ने घुमा-फिरा कर दिया. मैंने यह भी पूछा कि क्यों इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की नहीं, मोदी सरकार की बात हो रही है, क्या मोदी भारतीय जनता पार्टी से बड़े हो गए हैं? इस सवाल के जवाब में रविशंकर चुप रहे. मेरा तीसरा सवाल था कि आज की समस्याएं क्या खुली नव-उदारवादी बाज़ार व्यवस्था की देन हैं? मौजूदा अर्थव्यवस्था की वजह से भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोज़गारी, आतंकवाद और सांप्रदायिकता में वृद्धि हुई है या इसकी जड़ में ख़राब राजनीतिक शैली ही है? इन सवालों पर भी साफ़ जवाब देने से रविशंकर बच गए. अर्थनीति के सवाल से अलग मैंने अरुण जेटली से पूछा कि क्या आपको पता है कि देश में मुसलमानों की संख्या कितनी है और उन्हें कितने टिकट आपकी पार्टी ने दिए हैं? अरुण जेटली ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया. मुसलमानों को जीतने योग्य या संसद में भेजने योग्य भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती, यह इस चुनाव के टिकट वितरण ने बता दिया है. लेकिन, कांग्रेस पार्टी भी उन्हें जीतने योग्य नहीं मानती या उनसे जो वादे करती है, उन्हें पूरा न कर पाने की स्थिति में माफ़ी भी नहीं मांगती, यह भी इस चुनाव ने बता दिया है. इस चुनाव में सबसे बड़ा अगर कोई लूज़र होने वाला है, तो वह इस देश का मुसलमान है, जिसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह चुनाव में क्या करे. इसीलिए मुसलमानों का एक तबका नरेंद्र मोदी की तरफ़ भी अपना समर्थन देने का मन बना रहा है और बाकी आपस में स्थानीय स्तर पर भटकते दिखाई दे रहे हैं.

नरेंद्र मोदी का आक्रामक प्रचार अभियान कांग्रेस के लिए मददगार भी साबित हो सकता है. नरेंद्र मोदी का प्रचार अभियान इतना ज़्यादा हुआ है, जो हमें याद दिलाता है कि नरसिम्हाराव का प्रचार अभियान भी कुछ इसी तरीक़े का था, जब वह 1996 का चुनाव लड़ रहे थे. उसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी का 2004 का चुनाव अभियान, जिसमें आडवाणी को प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग बताया गया था, वह भी कुछ इसी तरह का प्रचार अभियान था. कभी-कभी होता यह है कि जिस तरह का प्रचार होता है, वैसा भरोसा खुद पार्टी करने लगती है और पार्टी उसी पर अपनी हार की इबारत लिखने लगती है. कहानी हम सबने सुनी है, कछुआ और खरगोश की. यह कछुआ और खरगोश भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी हो सकता है और भारतीय राजनीति में भी कि दौड़ता हुआ खरगोश यानी नरेंद्र मोदी सो जाएं और कछुआ राजनाथ सिंह बाजी मार ले जाएं या राजनीति में खरगोश नरेंद्र मोदी सो जाएं और कछुआ यानी कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ धीरे-धीरे बहुमत के नज़दीक पहुंच जाए. भारतीय राजनीति में कमाल का खेल है. 2014 का चुनाव, जिसमें चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि ममता बनर्जी, जयललिता, नवीन पटनायक, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह एवं मायावती जैसे लोग चुनाव के बाद की राजनीति में ट्रम्प का रोल निभाएंगे या जोकर के रूप में स्वयं को सुशोभित करेंगे, लेकिन प्रचार में तो नरेंद्र मोदी बादशाह के रोल में नज़र आते हैं. इक्के के रूप में अगर कोई उन्हें मात दे सकता है, तो वह इस देश की जनता है और अगर जनता भी उन्हें बादशाह मान ले, तो इक्के का रोल ताश के खेल में पूर्णतया ख़त्म हो जाता है. ■

editor@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 06 अंक 06
दिल्ली, 14 अप्रैल–20 अप्रैल 2014
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे-3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ-226001
फोन : 0522-2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

बाबुओं की बड़ी चिंता

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हाल में प्रेम कुमार धूमल की पूर्व भाजपा सरकार और उनके सांसद बेटे अनुराग ठाकुर के क़रीबी बाबुओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की है. यह बात अब बाबुओं के बीच चर्चा का बड़ा मुद्दा बनी हुई है. लेकिन, जब राज्य सतर्कता ब्यूरो ने तेजी से कार्रवाई की और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन प्रकरण समेत ठाकुर से जुड़े अन्य मामलों में मुकदमे दर्ज किए, तो सबकी चिंता बढ़ गई. कई बाबुओं का मानना है कि इस प्रकरण से आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बीच दूरियां बढ़ेंगी. आईएएस अधिकारी इस बात से चिंतित हैं कि सरकार ने एचपीसीए मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक सनान और आईएएस अधिकारी आर एस गुप्ता को कारण बताओ नोटिस भेजा है. कांग्रेस सरकार फोन टेपिंग मामले की भी जांच शुरू करने पर पहल कर रही है. उसने पुलिस महानिदेशक आई डी भंडारी की एक ग़ैर-महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति कर दी है. सूत्रों के मुताबिक, बाबुओं के साथ वीरभद्र सिंह का कार्यकाल मुश्किल रहने वाला है, जो या तो उनके ख़िलाफ़ हैं अथवा काम करने से डर रहे हैं. ■

सामने आएगी सारी कहानी

अगर अफवाहों की मानें, तो कोयला घोटाला मामले में आरोपी पूर्व कोयला सचिव पी सी पारेख द्वारा लिखित किताब आने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो सुर्खियों में रहने वाला है. सीबीआई ने पिछले साल कुमार मंगलम बिड़ला के साथ पारेख का नाम जांच में शामिल किया था, लेकिन उन्हें अपने सहयोगियों और यहां तक कि कुछ मंत्रियों से भी समर्थन मिला है. सूत्रों का यह भी कहना है कि पूर्व नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और यहां तक कि पूर्व सीबीआई निदेशक भी पुस्तक लोकार्पण समारोह में शिरकत कर सकते हैं. माना जा रहा है कि अपनी जीवनी में पारेख ने दावा किया है कि सीबीआई ने कोल ब्लॉक आवंटन मामले की सही तस्वीर सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं पेश की. साथ ही, सीबीआई का मामला न्यायिक तौर पर बिल्कुल नहीं ठहरेगा और नतीजा यह होगा कि सभी आरोपी बरी हो जाएंगे. हालांकि, यह अभी देखा जाना बाकी है, लेकिन इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि पारेख की किताब से सीबीआई और उसके शीर्ष अधिकारियों को शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है. ■

जल्दबाजी में बदलाव की बयार

अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में यूपीए सरकार वित्त मंत्रालय की भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के कुछ खास अधिकारियों को नियुक्तियों के जरिये ईनाम देने को ज़्यादा उत्सुक नज़र आ रही है, जबकि कुछ सप्ताह पहले ही चुनाव आचार संहिता लागू हुई है. सूत्रों के मुताबिक, वरिष्ठ आईईएस अधिकारी अंबरीश कुमार को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है, जबकि कुमार लंबे समय से छुट्टी पर चल रहे थे. इसी तरह 1980 बैच के आईईएस अधिकारी बी ब्रह्मा को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार बनाया गया है, वहीं अवतार सिंह सहोता को पदोन्नति देते हुए पंचायती राज मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार की ज़िम्मेदारी दी गई है. यद्यपि मंत्रालय ने इसे सामान्य नियुक्ति बताया है, वहीं चुनाव आयोग ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. वित्त मंत्रालय ने पांच अन्य अधिकारियों को इसी तरह पदोन्नति दी है. उक्त नियुक्तियां सामान्य हैं या ईनाम और यह नियमों का उल्लंघन है या नहीं, यह साफ़ नहीं है, लेकिन दिल्ली के बाबुओं के बीच यह बहस का मुद्दा बना हुआ है कि केंद्र में नज़र आते बदलाव के मद्देनज़र इसे महज सामान्य गतिविधि नहीं कहा जा सकता. ■

dilipcherian@gmail.com

सच्चर समिति की सिफारिशें लागू करने के लिए उठाए गए क़दमों के विश्लेषण के लिए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट में प्रोफेसर अमिताभ कुंडू की अध्यक्षता में गठित विशेष समिति की राय भी यही है कि इसका लाभ मुसलमानों तक नहीं पहुंच रहा है. यही कारण है कि भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने हाल में मुंबई की एक चुनावी रैली में कहा कि एमएसडीपी का एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा सका है.

कांग्रेस ख़त्म होने की कगार पर

सच्चर समिति की सिफारिश नंबर 40 के अनुसार और वक्फ़ संपत्ति के विकास के मद्देनजर नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (नवादको) के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा बीती 29 जनवरी को उद्घाटन के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कांग्रेस एवं यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की उपस्थिति में जाफराबाद-दिल्ली निवासी सामाजिक कार्यकर्ता एवं हकीम फहीम बेग द्वारा उठाई गई बातों पर अगर सरकार समय रहते ध्यान देती, तो आज उसे जिन कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, न करना पड़ता.

ए यू आसिफ

कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए-2 सरकार का अब चल-चलाव है. इस कटु सत्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस द्वारा पिछली चुनावी घोषणा में स्वास्थ्य, आवास, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, इंटरप्रेन्योरशिप, रोज़गार, कृषि, सांप्रदायिकता विरोधी क़ानून, महिलाओं को आरक्षण, सच्चर समिति की सिफारिशें लागू करने जैसे वादे पूरे नहीं हो पाए. इस बार के चुनाव घोषणापत्र में कांग्रेस द्वारा ज़्यादातर पुराने और कुछ नए वादे किए गए हैं. अनेक योजनाओं में धनराशि बढ़ाने की बात है, वहीं कुछ बिंदुओं पर फिर से वादे किए गए हैं और यकीन दिलाया गया है. (देखिए, कांग्रेस का घोषणापत्र: वादे हैं वादों का क्या, 7-13 अप्रैल, 2014).

लगता है, कांग्रेस योजनाओं की धनराशियां बढ़ाने को ही विभिन्न समस्याओं का हल मानती है, जबकि नीयत, तरीके और रणनीति की कमी समस्या के मूल में है. बात आम जनता की नहीं, बल्कि कमजोर वर्ग, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, तक विभिन्न योजनाओं का लाभ न पहुंचने की है. इसके अलावा, देश में 1991 से लागू नई आर्थिक नीति भी विभिन्न समस्याओं का समाधान न होने के लिए ज़िम्मेदार है. सवाल यह है कि 23 वर्षों के अनुभवों के बाद भी कांग्रेस, उसके समर्थक पार्टियां और विपक्षी पार्टियां जाग क्यों नहीं रही हैं? वे बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था की बजाय जनहितैषी अर्थव्यवस्था की बारे में क्यों नहीं सोच रही हैं? एक ऐसा देश, जहां कृषि को आज भी दूसरे क्षेत्रों की तुलना में महत्व प्राप्त है और जहां के पारंपरिक उद्योगों की दुनिया भर में गूंज है, आख़िर क्यों पिछड़ेपन का शिकार है? वजह यह है कि सरकारों ने नई आर्थिक नीति के प्रभाव में इन तमाम मुद्दों पर ध्यान देना कम कर दिया. इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहले जनहितैषी आर्थिक नीति लागू करने का प्रयास हो, तभी देश एवं जनता, दोनों का भला हो सकता है.

हाल में नेशनल सैंपुल सर्वे के 2011 से लेकर 2012 तक सामने आए आंकड़े बताते हैं कि स्थिति बदतर होती जा रही है. आंकड़े कहते हैं कि पुरुष एवं महिला, दोनों की शिक्षा के बढ़ते हुए स्तर के साथ-साथ बेरोज़गारी में तेजी से वृद्धि हुई है. 29 वर्ष तक के 16.3 फ़ीसद पुरुष स्नातक बेरोज़गार हैं. बेरोज़गारी की यह स्थिति बीते दशक में बदतर हुई है. डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट धारकों को भी मिला लें, तो बेरोज़गारी 12.5 फ़ीसद और बढ़ जाती है. मतलब यह है कि वोकेशनल कोर्स या डिग्री हासिल करने के बाद युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर कम होते जा रहे हैं. स्नातक डिग्री या वोकेशनल कोर्स वाले प्रति चार युवाओं में एक बेरोज़गार है. यह प्रतिशत अल्पशिक्षित वर्ग की बेरोज़गारी की तुलना में बहुत अधिक है. जाहिर-सी बात है कि 2014 के संसदीय चुनाव में जो 8 करोड़ नए मतदाता हैं, उनके लिए रोज़गार सबसे बड़ी समस्या है. शिक्षा अधिकार क़ानून एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थिति भी निराशाजनक है. राजनीतिज्ञ शिक्षा एवं स्वास्थ्य के मामलों में फंड देने की बात तो करते हैं, मगर उन फंडों के इस्तेमाल पर उनका कंट्रोल कमजोर है.

इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे (आईएचडीएस) 2004-05 एवं 2011-12 के अनुसार, सरकारी कार्यक्रमों और जमीनी स्तर पर अनुभवों के बीच अंतर बहुत ज़्यादा है. रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में नल का पानी 2004-05 में 25 प्रतिशत उपलब्ध था, जबकि 2011-12 में उसमें मात्र 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई. शहरी क्षेत्रों में यह पानी आधे या 2 तिहाई परिवारों को हासिल है, जबकि फ्लश वाले शौचालय केवल एक तिहाई लोगों के पास है. बिजली 2004-05 में 72 प्रतिशत लोगों को मिलती थी, 2011- 12 में यह 83 प्रतिशत लोगों को पहुंची. वर्ष 2004-05 एवं 2011-12 में कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए, जैसे शिक्षा का अधिकार क़ानून (आरटीई) 2010, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ मिशन (एनआरएचएम) 2005 और जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) 2005, लेकिन नतीजे निराशाजनक रहे. 2001 की जनगणना के आधार पर अल्पसंख्यक आबादी एवं पिछड़ेपन के पैमाने पर चुने गए अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले 90 ज़िलों में 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत मल्टी-सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम (एमएसडीपी) लागू किया गया, जो 2012-13 तक चलता रहा, लेकिन

2013-14 में इसके प्रारूप में परिवर्तन करके इसे चुने हुए ब्लॉकों एवं शहरों में लागू कर दिया गया. ग़ौरतलब है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना एवं 2012-13 के दौरान इन 90 ज़िलों के लिए 4843.64 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट मंजूर किए गए.

अल्पसंख्यकों के लिए एमएसडीपी का मामला हो या मैट्रिक से पूर्व-पश्चात छात्रवृत्ति स्कीम, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, मुफ्त कोचिंग, इक्विटी, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल मायनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनांस को-ऑपरेशन, ग्रांट इन एड टू मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन, कंप्यूटराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स स्टेट वक्फ बोर्ड्स, नई रोशनी, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जियो पारसी, सिविल सर्विसेज, स्टाफ सेलेक्शन कमीशन एवं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आर्थिक सहायता, विदेशों में शिक्षा के लिए ऋण के ब्याज पर सब्सिडी, प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय अल्पसंख्यक कार्यक्रम के बावजूद स्थिति बेहतर होने की बजाय बदतर होती जा रही है. इसकी वजह विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्रों तक न पहुंचना है.

सच्चर समिति की सिफारिशें लागू करने के लिए उठाए गए क़दमों के विश्लेषण के लिए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट में प्रोफेसर अमिताभ कुंडू की अध्यक्षता में गठित विशेष समिति की राय भी यही है कि इसका लाभ मुसलमानों तक नहीं पहुंच रहा है. यही कारण है कि भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने हाल में मुंबई की एक चुनावी रैली में कहा कि एमएसडीपी का एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा सका है. प्रोफेसर जोया हसन, जिन्होंने 11वीं पंचवर्षीय योजना के वर्किंग ग्रुप की अध्यक्षता की, भी मानती हैं कि सामूहिक तौर पर अल्पसंख्यकों को एमएसडीपी से कोई लाभ नहीं हुआ. बकौल जोया हसन, 2006 में उन्होंने जोर डालकर कहा था कि योजनाएं क्षेत्रों नहीं, बल्कि अल्पसंख्यकों पर केंद्रित होनी चाहिए. ज्ञात रहे कि यूपीए सरकार का यह कार्यक्रम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए बनीं योजनाओं के विकल्प के तौर पर शुरू किया गया था, लेकिन नाकाम रहा, क्योंकि यह अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से नहीं था. यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तरीका नहीं था कि सरकार द्वारा किए जा रहे निवेश से अल्पसंख्यकों की स्थिति बदलने जा रही है. दरअसल, उक्त योजनाएं कुछ राज्यों में पिछड़े ज़िलों के विकास कार्यक्रम के आधार पर थीं.

जोया हसन कहती हैं कि इससे विभिन्न ज़िलों के ढांचों में विकास तो हुआ होगा, परंतु अल्पसंख्यकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि उक्त ज़िले शत-प्रतिशत अल्पसंख्यक ज़िले नहीं हैं. इसलिए ऐसी योजनाएं बनाई जाएं, जिनका निशाना अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक एवं गांव हों. यही विचार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्लाह एवं प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हर्षवर्द्धन के हैं. ग़ौरतलब है कि हर्षवर्द्धन ने इस बात पर गत वर्ष विरोध प्रकट करते हुए नेशनल एडवाइजरी काउंसिल से त्यागपत्र भी दे दिया था. उनका ऐतराज यह भी था कि जब सच्चर समिति की सिफारिशों पर अमल करते हुए मुसलमानों की भलाई के लिए योजनाएं बनाई गईं, तो वे आम अल्पसंख्यकों एवं क्षेत्रों के लिए क्यों लागू की गईं? इसके अलावा, अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत जो धनराशियां अल्पसंख्यकों के लिए तय की जाती हैं, वे उन तक नहीं पहुंच पाती हैं और कुछ तो खर्च भी नहीं हो पाती हैं.

सच्चर समिति की सिफारिश नंबर 40 के अनुसार और वक्फ़ संपत्ति के विकास के मद्देनजर नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (नवादको) के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा बीती 29 जनवरी को उद्घाटन के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कांग्रेस एवं यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की उपस्थिति में जाफराबाद-दिल्ली निवासी सामाजिक कार्यकर्ता एवं हकीम फहीम बेग द्वारा उठाई गई बातों पर अगर सरकार समय रहते ध्यान देती, तो आज उसे जिन कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, न करना पड़ता. फहीम बेग ने उस समय कहा था, प्रधानमंत्री जी, आप द्वारा पहले घोषित योजनाएं असल हक़दार तक पहुंच नहीं पाई हैं. आख़िर क्यों आपकी सरकार योजना पर योजना की घोषणा करती जा रही है? मेरा संबंध दिल्ली के एक ऐसे क्षेत्र से है, जो एमएसडीपी के अंतर्गत चुने हुए 90 ज़िलों में से एक है और जहां आपकी कोई भी अल्पसंख्यक योजना जमीनी सतह तक नहीं पहुंच पाई हैं. अगर सरकार ने फहीम बेग के विरोध को एक व्यक्ति नहीं, बल्कि जनता की आवाज़ समझा होता, तो आज कांग्रेस में जो अनिश्चितता की स्थिति है, वह कदापि न होती. उस समय उनके मुंह को जिस तरह जबरदस्ती बंद करने का प्रयास किया, वह जनतांत्रिक मूल्यों का दमन था. सच तो यह है कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में अपना एपिटाफ स्वयं लिख लिया है और वह अल्पसंख्यकों के लिए इतनी सारी घोषणाओं एवं निर्णयों के बावजूद परेशान है. जो कुछ उसे आज झेलना पड़ रहा है, उसके लिए वह खुद ज़िम्मेदार है. उसे अपनी सोच और व्यवहार पर पुनर्विचार करना चाहिए. ■

सभी फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

feedback@chauthiduniya.com

> राजद भी इस मामले में पीछे नहीं है, लेकिन वहां भी पार्टी के अंदर आईटी सेल जैसी कोई व्यवस्था नहीं है. लालू के दोनों पुत्र तेजप्रताप और तेजस्वी फेसबुक पर काफी सक्रिय नज़र आते हैं. खुद राजद प्रमुख लालू प्रसाद भी ट्वीटर पर आ चुके हैं. बीते फरवरी माह में तेजस्वी ने फेसबुक के साथियों के साथ एक चाय पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें सौ से अधिक लोग इकट्ठा हुए थे.

बिहार : सोशल मीडिया बना प्रचार का हथियार

शशि सागर

तकनीक और राजनीति का रिश्ता वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन हाल के दिनों में चुनावी राजनीति में उसका बेहतर प्रयोग कैसे हो, इसकी एक बानगी नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में दिखाई थी. थ्री डी तकनीक के आधार पर देश भर के करोड़ों मतदाताओं को एक ही स्थान से संबोधित करके रूबरू होने का एहसास नरेंद्र मोदी ने देश को कराया था. फेसबुक और ट्वीटर जैसी सोशल मीडिया के साधनों का प्रयोग नेताओं ने वोटरों तक पहुंचने के लिए जोर-शोर से करना शुरू किया. आम आदमी पार्टी ने तो इसका पूरा फ़ायदा दिल्ली के चुनाव में उठाया. बिहार में भी इन दिनों लगभग सभी दलों ने सोशल मीडिया को अपने प्रचार का एक प्रमुख हथियार बना लिया है और कम से कम समय में बिना कोई खास खर्च वे अपने वोटरों तक पहुंचने में लगे हैं.

बात सत्तारूढ़ जदयू से शुरू करते हैं. जदयू कार्यालय में इधर-उधर की बात होते-होते हम फेसबुक-ट्वीटर की दुनिया में आ जाते हैं. बतकही का हिस्सा बन रहे तमाम नेता-कार्यकर्ता यह स्वीकारते हैं कि जदयू की तुलना में भाजपा सोशल मीडिया पर कहीं ज़्यादा सक्रिय है. कार्यालय सचिव बबलू के हाथ में महंगा एंड्रॉयड फोन होता है और रह-रहकर वह अपना फेसबुक अपडेट देखते हैं. बातचीत के दौरान ही हम उनसे कहते हैं कि आपको भाजपा ने सोशल मीडिया पर मात दे दी है. छूटते ही बबलू खुद सवाल करते हैं,

> ट्राई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, बिहार की टेली डेंसिटी 48.90 है, वहीं इसकी रूरल टेली डेंसिटी सबसे कम 27.5 है. इंटरनेट एक्सेस करने के मामले में बिहार देश का बारहवां राज्य है. एक जानकारी यह भी है कि सिर्फ़ राजधानी पटना में 11 लाख लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं.

आपको क्या लगता है कि बिहार भी दिल्ली या जापान है, जहां सोशल मीडिया का जादू चल जाएगा? हमें जहां एक्टिव रहना चाहिए, वहां हैं. वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फेसबुक पेज दिखाते हुए कहते हैं, देखते हैं कभी कि यहां मुख्यमंत्री के पोस्ट पर लोग कैसे-कैसे कमेंट करते हैं? व्यक्तिगत खुन्नस निकालते हैं, गाली-गलौज तक करते हैं. हमने कहा कि जिन्हें सरकार से नाराज़गी होगी, वही ऐसा करते होंगे. इस पर बबलू कहते हैं, नहीं, भाजपा ने कुछ लोगों को हायर किया है अपने आईटी सेल में. यह सब उन्हीं का काम है. वे भाजपा को सोशल मीडिया पर प्रमोट करते हैं और सरकार का दुष्प्रचार करते हैं.

बबलू की बातें सही हों या गलत, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार के राजनीतिक दल और नेता सोशल मीडिया की ताकत पहचान चुके हैं. यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ-साथ बिहार के लगभग सभी बड़े नेता फेसबुक-ट्वीटर पर सक्रिय नज़र आते हैं. वैसे मुख्यमंत्री नीतीश हाल-हाल तक सोशल मीडिया पर एक्टिव नेताओं पर व्यंग्य करते रहे हैं. किसी भी नेता के ट्वीटर अपडेट पर जब कोई नीतीश से उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता, तो वह व्यंग्य करने में तनिक भी देरी नहीं करते थे. हाल में एक अख़बार के लोकार्पण के मौक़े पर उन्होंने परोक्ष रूप से लालू पर निशाना साधते हुए कहा था कि नए लोगों की तो छोड़िए, अब पुराने लोग भी चेंचियाने लगे हैं. बताते चलें कि उक्त समारोह से कुछ दिनों पहले यह ख़बर आई थी कि लालू अब ट्वीटर पर नज़र आएंगे. उसके कुछ दिनों बाद ही नीतीश खुद फेसबुक पर नज़र आने लगे. नीतीश ने फेसबुक पर सिर्फ़ एकाउंट ही नहीं खोला है, वह लगातार इस माध्यम पर सक्रिय भी रहते हैं. अपनी तमाम गतिविधियों को अपडेट करते रहते हैं. फेसबुक पर उनके चाहने वालों की संख्या एक लाख से भी अधिक है. पिछले दिनों नीतीश ने अपने पेज पर फेडरल फ्रंट के आकार लेने और उससे जुड़ी बातों को फेसबुक पर अपडेट किया. मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं. कुछ लोगों ने आलोचना की, तो बहुतों ने नीतीश के इस क़दम को सराहा भी.

सूत्र बताते हैं कि नीतीश का यह पेज उनके एक सचिव देखते हैं और नीतीश हर रोज आ रही प्रतिक्रियाओं से अवगत होते हैं. जदयू के एक नेता कहते हैं कि अब तो हम लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर अभी ध्यान देने का वक्त नहीं है. लेकिन उनकी बातों से लगता है कि उन्हें इसका मलाल है कि समय रहते हुए जदयू ने इस ओर ध्यान नहीं दिया. जदयू में फिलहाल आईटी सेल भी नहीं है. जदयू की जो आधिकारिक वेबसाइट है, वह दिल्ली से संचालित होती है और वह भी अपडेट नहीं है. वहीं बिहार जदयू की अलग से कोई वेबसाइट नहीं है और न वह सोशल मीडिया पर है. पिछले कुछ दिनों से जदयू के प्रदेश प्रवक्ता नवल शर्मा पार्टी की गतिविधियां बेहतर तरीके से सोशल मीडिया पर रखने का काम कर रहे हैं. हम नवल से कहते हैं कि आपको यह काम कुछ और पहले से शुरू कर देना चाहिए था. इस पर नवल कहते हैं कि यह काम एक प्रवक्ता का नहीं है, हमने खुद ही आगे बढ़कर इसकी ज़िम्मेदारी ली है. हमारा उद्देश्य है नीतीश के कामों को जन-जन तक पहुंचाना.

भाजपा इस दौड़ में अन्य सभी दलों से आगे है. भाजपा का प्रदेश कार्यालय वाई-फाई है और वहां बाकायदा आईटी सेल और संवाद सेल हैं. पार्टी के तमाम बड़े-छोटे नेता सोशल मीडिया पर जबरदस्त रूप से सक्रिय नज़र आ जाते हैं. भाजपा के एक नेता हैं अरविंद कुमार सिंह, जो लोक सेवा अधिकार मंच के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं. वह अपने तमाम लाइक्स, फ्रेंड और फॉलोअर गिनाते हुए कहते हैं कि बताइए, अब इतने सारे लोग हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं और जिन तक हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं. कहीं न कहीं यह सब भाजपा के लिए ही तो है. उनका समर्थन करते हुए संजय मयूख कहते हैं कि हम नई-नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं. हर पंचायत का अध्यक्ष हमसे जुड़ा हुआ है. मयूख जानकारी देते हैं कि पिछले दिनों उनके यहां इस बात की ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे फेसबुक का इस्तेमाल लोकसभा को ध्यान में रखकर किया जाए. नेशनल मीडिया में कई बार यह ख़बर आई कि भाजपा के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग के लिए प्रोफेशनल्स और पीआर एजेंसी का सहारा लिया जा रहा है. सूत्र बताते हैं कि बिहार भाजपा की गतिविधियां सोशल मीडिया तक जोरदार तरीके से पहुंचाने के लिए यहां भी कुछ आईटी प्रोफेशनल्स को रखा गया है, लेकिन भाजपा संवाद सेल के अध्यक्ष संजय चौधरी इस बात को स्वीकारते नहीं हैं.

संजय कहते हैं कि हमारे यहां आईटी सेल है और संवाद सेल भी है, यही दोनों मिलकर सोशल मीडिया का सारा काम देखती हैं. वह कहते हैं कि हमारे यहां कुछ प्रोफेशनल्स तो हैं, लेकिन हमने किसी को हायर नहीं किया है. ये वे लोग हैं, जिन्हें नमो से लगाव है, हम इन्हें कोई मानदेय या भत्ता नहीं देते. ये पार्टी के लोग हैं और नमो को पीएम बनाने के लिए काम कर रहे हैं. संजय कहते हैं कि यह एक दिन में नहीं हुआ है, हम सोशल मीडिया को लेकर बहुत पहले से सजग हैं. नमो की हुंकार रैली से पहले पटना में बिहार भाजपा ने एक वर्कशॉप का आयोजन किया था. उस दौरान पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि भाजपा के सारे कार्यकर्ताओं के पास ईमेल होना अनिवार्य है. उन्होंने सलाह दी थी कि सभी लोग स्मार्ट फोन और थ्री जी कनेक्शन ज़रूर लें. भाजपा नई तकनीक का बखूबी इस्तेमाल कर रही है. हाल में टेली विजिंग टेक्नोलॉजी के जरिये पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं से प्रदेश के पदाधिकारी ने सीधे संवाद किया था. समय-समय पर पार्टी वीडियो कांफ्रेंसिंग कराती रहती है, चाय पर चर्चा उसी का एक उदाहरण है. बिहार भाजपा के सुशील मोदी, मंगल पांडेय, नंदकिशोर यादव सहित कई नेता फेसबुक पर जोरदार तरीके से सक्रिय नज़र आते हैं. हर रोज उनका फेसबुक पेज और एकाउंट अपडेट नज़र आता है.

वैसे राजद भी इस मामले में पीछे नहीं है, लेकिन वहां भी पार्टी के अंदर आईटी सेल जैसी कोई व्यवस्था नहीं है. लालू के दोनों पुत्र तेजप्रताप और तेजस्वी फेसबुक पर काफी सक्रिय नज़र आते हैं. खुद राजद प्रमुख लालू प्रसाद भी ट्वीटर पर आ चुके हैं. बीते फरवरी माह में तेजस्वी ने फेसबुक के साथियों के साथ एक चाय पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें सौ से अधिक लोग इकट्ठा हुए थे. सोशल जस्टिस से सोशल मीडिया की ओर बढ़ रहे इस क़दम को लोग तेजस्वी के दिमाग की उपज बताते हैं. बैठक के दौरान तेजस्वी ने सोशल मीडिया की महत्ता को स्वीकारा भी. तेजस्वी ने कहा कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का लक्ष्य हासिल करने के लिए सोशल मीडिया कारगर हथियार है. बिहार प्रदेश कांग्रेस भी सोशल मीडिया पर सक्रिय नज़र आती है. प्रदेश कांग्रेस का मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इस गतिविधि को देखता है. प्रदेश कांग्रेस की अपनी वेबसाइट है और सोशल मीडिया पर उसके पेज भी हैं. खुद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी और प्रदेश प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा भी फेसबुक पर खूब नज़र आते हैं. प्रेमचंद्र कहते हैं कि युवाओं पर पकड़ बनाने के लिए यह एक बेहतर जरिया है और इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता.

ट्राई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, बिहार की टेली डेंसिटी 48.90 है, वहीं इसकी रूरल टेली डेंसिटी सबसे कम 27.5 है. इंटरनेट एक्सेस करने के मामले में बिहार देश का बारहवां राज्य है. एक जानकारी यह भी है कि सिर्फ़ राजधानी पटना में 11 लाख लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं. आज बिहार की तमाम पार्टियां और छोटे-बड़े नेता सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं. पटना में कई ऐसी पीआर एजेंसियां काम कर रही हैं, जो कुछ नेताओं के प्रोफाइल का संचालन करती हैं. लोकसभा चुनाव में बिहार में भी सोशल मीडिया का असर दिखेगा, भले थोड़ा कम ही सही. हमारी बात को वरिष्ठ पत्रकार एवं सोशल मीडिया के जानकार ज्ञानेश्वर भी पुष्ट करते हैं. ज्ञानेश्वर कहते हैं कि आज जो भी सोशल मीडिया की पहुंच को नकारेगा, वह पीछे छूट जाएगा. इससे तेज माध्यम तो है ही नहीं लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए. ज्ञानेश्वर के अनुसार, देश के 340 चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं, जहां सोशल मीडिया का प्रभाव दिखेगा. बिहार में भी पटना, बक्सर, आरा, पूर्णियां, कटिहार, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और शिवहर ऐसे ज़िले हैं, जहां का लोकसभा चुनाव सोशल मीडिया भी प्रभावित करेगा. वह कहते हैं कि हाल के दिनों में जितने भी परिवर्तन हुए हैं, उनमें सोशल मीडिया का अहम योगदान है. ■

ट्वीटर पर नेताओं के फॉलोअर

नरेंद्र मोदी-भाजपा-3.5 मिलियन
सुशील कुमार मोदी-भाजपा-66.3 हज़ार
लालू प्रसाद यादव-राजद- 17.8 हज़ार
नीतीश कुमार-जदयू-2533
चिराग पासवान-लोजपा-533

> भाजपा इस दौड़ में अन्य सभी दलों से आगे है. भाजपा का प्रदेश कार्यालय वाई-फाई है और वहां बाकायदा आईटी सेल और संवाद सेल हैं. पार्टी के तमाम बड़े-छोटे नेता सोशल मीडिया पर जबरदस्त रूप से सक्रिय नज़र आ जाते हैं. भाजपा के एक नेता हैं अरविंद कुमार सिंह, जो लोक सेवा अधिकार मंच के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं.

feedback@chauthiduniya.com

उलेमा काउंसिल ही नहीं, अन्य कई मुस्लिम संगठनों के रहनुमा भी सपा सरकार और पार्टी प्रमुख के ख़िलाफ़ मोर्चा खोले हुए हैं. असल में वोटों की चाहत में समाजवादी नेताओं ने मुसलमानों से ऐसे–ऐसे वादे कर लिए थे, जिन्हें पूरा करना असंभव नहीं, तो मुश्किल ज़रूर है. इसमें से कई वादे तो क़ानूनन पूरे नहीं किए जा सकते. लेकिन, जब सियासत देश और प्रदेश की बजाय कौमों को खुश करने में जुट जाती है, तो इस तरह का बखेड़ा खड़ा होना स्वाभाविक है.

आजमगढ़

मुलायम की मुश्किल

अजय कुमार

समाजवादी पार्टी का हमेशा मजबूत गढ़ माना जाने वाला आजमगढ़ इस बार मुलायम सिंह के लिए पेचीदगी भरा साबित हो रहा है. सपा का सामाजिक समीकरण बुरी तरह फंस गया है. 20 फ़ीसद यादव और 25 फ़ीसद मुसलमानों के सहारे जीत का सपना संजोए मुलायम के सामने भाजपा के मौजूदा सांसद रमाकांत यादव, उलेमा काउंसिल के अलावा बसपा के पाले में खड़े 30 फ़ीसद दलित एवं 25 फ़ीसद सवर्ण, पिछड़े और अन्य ग़ैर यादव मतदाता चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं. सपा में डर इतना अधिक है कि मुलायम सिंह की जीत के लिए अखिलेश ने स्वयं मोर्चा संभाल रखा है.

आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के सामने कुछ वैसी ही मुश्किलें आ रही हैं, जिनसे वाराणसी में नरेंद्र मोदी को दो–चार होना पड़ रहा है. भले ही मुलायम समर्थक कहते घूम रहे हों कि नेता जी यहां के लिए बाहरी उम्मीदवार नहीं हैं, परंतु क्षेत्रीय जनता मानने को तैयार नहीं है कि मुलायम आजमगढ़ के भी हो सकते हैं. आजमगढ़ और मैनपुरी से लोकसभा चुनाव में उतर रहे मुलायम के सामने सवाल यह भी उछाला जा रहा है कि अगर वह दोनों जगह से चुनाव जीतेंगे, तो क्या अपनी परंपरागत मैनपुरी सीट छोड़कर यहां के होकर रह जाएंगे? यही सवाल मोदी से वाराणसी और बड़ोदरा को लेकर पूछा जाता है.

तमाम मुद्दों पर आजमगढ़ में असहज दिख रहे पार्टी के रणनीतिकारों के सामने एक समस्या सपा का एम–वाई (मुस्लिम–यादव) फॉर्मूला यहां न चल पाना भी है, यह फॉर्मूला यहां कसौटी पर है. आजमगढ़ की सीट इस समय भाजपा के पास है और उसके सांसद रमाकांत यादव हैं. रमाकांत की क्षेत्रीय यादव बिरादरी में अच्छी–खासी पैठ है. रमाकांत की पहचान सामाजिक वर्चस्व के लिए यादव–ठाकुर संघर्ष में बिरादरी के साथ हमेशा खड़े रहने वाले भरोसेमंद नेता की है. रमाकांत अपनी जीत पक्की करने के लिए घूम–घूमकर कह रहे हैं कि मुलायम आजमगढ़ की जनता का भला करने नहीं आए हैं, उनका मकसद पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को रोकना भर है. चुनाव बाद वह आजमगढ़ को भूल जाएंगे. इस सियासी बिसात का अंदाजा सपा नेताओं का विश्वास भांपकर लगाया जा सकता है. सपाई यहां यादवों से अधिक ध्यान मुसलमानों को मनाने में दे रहे हैं.

एक तरफ़ भाजपा के यादव प्रत्याशी रमाकांत सपा के अवरोधक बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ़ उलेमा काउंसिल सपा के दो वर्षों के शासनकाल में मुजफ्फरनगर सहित तमाम दंगों को लेकर घेर रही है. उलेमा काउंसिल का जन्म 2008 में हुआ था. उसके जन्म के पीछे जो वजह बताई गई थी, उसके अनुसार, आजमगढ़ को आतंकी पैदा करने का ठिकाना बताए जाने और बटला हाउस कांड के बाद मुसलमानों का विश्वास कांग्रेस एवं सपा से उठ गया था. 2009 के लोकसभा चुनाव में काउंसिल लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़, जौनपुर, मछलीशहर, लालगंज एवं अंबेडकर नगर से लोकसभा चुनाव लड़ी थी. तब भी काउंसिल की नाराज़गी कांग्रेस और सपा से थी, आज भी स्थिति यही है. उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष आमिर रशादी तो यहां तक कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान एक बार नरेंद्र मोदी को माफ़ कर सकता है, लेकिन मुलायम सिंह को नहीं. मुसलमानों के हक़ में मोदी से बुरे हैं मुलायम.

वह अपनी बात पर मुहर लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश भी जोड़ देते हैं, जिसमें मुजफ्फरनगर दंगों के लिए अखिलेश सरकार को कठघरे में खड़ा किया गया था.

वह कहते हैं कि 2012 के विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह ने कई वादे किए थे, जिनमें आतंकवाद के फर्जी मामलों में जेलों में बंद निर्दोष मुस्लिम युवाओं की रिहाई, सच्चर कमेटी एवं रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिशें राज्य में लागू कराने, सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को 18 फ़ीसद आरक्षण दिलाने जैसे वादे प्रमुख थे. इसीलिए प्रदेश के मुसलमानों ने अपने वोट सपा की झोली में डाल दिए थे. तल्खी का आलम यह है कि नाराज़ रशादी आजमगढ़ से मुलायम के ख़िलाफ़ स्वयं मैदान में उतरने की बात कह रहे हैं. उलेमा काउंसिल की जितनी नाराज़गी सपा से है, उतनी ही कांग्रेस से भी. वह दोनों पर मुसलमानों का नुकसान करने का आरोप लगाते हैं. 2009 में जब मुलायम सिंह ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के नायक कल्याण सिंह से हाथ मिलाया था, तब भी कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सपा को कोसते हुए उससे किनारा कर लिया था. सपा का मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले आजम खां भी इसी वजह से उससे दूर हो गए थे, लेकिन यह दोस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई. कल्याण से मोहभंग होने के बाद मुलायम सिंह ने अपने इस कृत्य के लिए मुसलमानों से माफी तक मांगी. लेकिन, कहते हैं कि एक बार गांठ पड़ जाए, तो फिर पड़ ही जाती है. उलेमा काउंसिल ने तब भी कल्याण–मुलायम की दोस्ती पर जबर्दस्त नाराज़गी व्यक्त की थी.

उलेमा काउंसिल ही नहीं, अन्य कई मुस्लिम संगठनों के रहनुमा भी सपा सरकार और पार्टी प्रमुख के ख़िलाफ़ मोर्चा खोले हुए हैं. असल में वोटों की चाहत में समाजवादी नेताओं ने मुसलमानों से ऐसे–ऐसे वादे कर लिए थे, जिन्हें पूरा करना असंभव नहीं, तो मुश्किल ज़रूर है. इसमें से कई वादे तो क़ानूनन पूरे नहीं किए जा सकते. लेकिन, जब सियासत देश और प्रदेश की बजाय कौमों को खुश करने में जुट जाती है, तो इस तरह का बखेड़ा खड़ा होना स्वाभाविक है. हमारे नेताओं को यह बात जिस दिन समझ में आ जाएगी, उस दिन वे ऐसे लोगों से छुटकारा पा जाएंगे, जो वोटों का सौदा करते हैं और अपनी जाति–समुदाय के ठेकेदार बने घूमते हैं. मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में समाजवादी पार्टी अपने कई संगी–साथियों से दूर चली गई है. दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम मौलाना अहमद बुखारी 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन अब वह मुलायम के दुश्मन नंबर वन हैं. इत्तेहाद–ए–मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा पिछले विधानसभा चुनाव के समय सपा के लिए वोट डलवा रहे थे. खुश होकर सपा सरकार ने उन्हें लालबत्ती से नवाजा, फिर भी तौकीर सपा से दूर चले गए. पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ पकड़ा, अब वह बसपा के साथ हैं.

बहरहाल, भले ही एक तरफ़ भाजपा के दबंग प्रत्याशी एवं मौजूदा सांसद रमाकांत यादव सपा प्रमुख के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं और दूसरी तरफ़ उलेमा काउंसिल के नेता ताल ठोंक रहे हों, लेकिन शहर के वाशिंदे अतीक अहमद कहते हैं कि मुलायम का कद बहुत बड़ा है. उनका मुकाबला करने की काबिलियत वाला नेता आज की तारीख में यहां नहीं दिखाई दे रहा. बात उलेमा काउंसिल के खलल डालने की चलती है, तो अतीक कहते हैं कि 2009 में भी उलेमा काउंसिल मैदान में थी, लेकिन उसे वोट मिले सिर्फ़ 60 हज़ार के क़रीब. हां, वह यह ज़रूर जोड़ देते हैं कि उलेमा काउंसिल अगर मैदान में कूदती है, तो उसका फ़ायदा सांप्रदायिक शक्तियों को मिल सकता है. जब चुनाव जीतने के बाद मुलायम के यहां से पलायन कर जाने की बात छिड़ती है, तो सपा नेता सफाई देते हैं कि एक तो ऐसा होगा नहीं. अगर ऐसे हालात पैदा भी हुए, तो चिंता की कोई बात नहीं है, मुलायम अपने छोटे बेटे प्रतीक को यहां की ज़िम्मेदारी सौंपकर जनता की झोली मुरादों से भर देंगे. फिलहाल, भाजपा और सपा की जंग में यहां बसपा और कांग्रेस पिछड़ती दिख रही हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

लखनऊ संसदीय सीट

ग़ैरों को अपना बनाते रहे लखनवी

अजय कुमार

पूरे देश में नरेंद्र मोदी भले ही भारतीय जनता पार्टी के पोस्टरमैन बने हों, लेकिन लखनऊ में आज भी जीत के लिए भाजपा को अपने पूर्व प्रधानमंत्री और पांच बार लखनऊ से सांसद रहे अटल बिहारी वाजपेयी का ही सहारा है. क़रीब दस वर्षों से सक्रिय राजनीति से दूर चल रहे अटल का लखनऊ में आज तक भाजपा विकल्प नहीं तैयार कर पाई है. 1991 में भाजपा के सिर अटल के सहारे पहली बार जीत का सेहरा बंधा था. उसके बाद हुए सभी छह चुनावों में भाजपा का ही परचम लहराता रहा. अटल ने राजनीति से दूरी बनाई, तो 2009 में उनकी खड़ाऊ पकड़ कर लालजी टंडन ने लखनऊ का प्रतिनिधित्व किया. मौजूदा भाजपा सांसद लालजी टंडन की जगह इस बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह मैदान में ताल ठोंक रहे हैं. लालजी टंडन की तरह राजनाथ भी अटल के सहारे अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं. शायद यही वजह है, उन्हें मीडिया के सामने बताना पड़ रहा है कि वह आज भी महीने में चार बार अटल जी के पैर छूते हैं.

लखनऊ के मतदाताओं के मिजाज की बात की जाए, तो यहां के वाशिंदे जिसे गले लगाते हैं, उसे आसानी से नहीं छोड़ते. इतना ही नहीं, तहजीब के शहर लखनऊ के मतदाताओं ने कभी भी यह सोचकर अपना नुमाइंदा नहीं चुना कि कौन शहर का है और कौन बाहर का. इसी वजह से लखनऊ का सांसद बनने वालों में बाहर के नेताओं की फेहरिस्त लंबी है. हाल के वर्षों में मौजूदा सांसद लालजी टंडन को छोड़कर पिछले कई लोकसभा चुनावों में बाहर से आए नेताओं को ही यहां की जनता ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर लोकसभा भेजना ज़्यादा पसंद किया. पांच बार लखनऊ से चुनाव जीते भाजपा नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, तीन बार कांग्रेस के टिकट से संसद पहुंचने वाली शीला कौल, विजयलक्ष्मी पंडित, पुलिन बनर्जी, मान्धाता सिंह, हेमवती नंदन बहुगुणा एवं आनंद नारायण मुल्ला आदि सभी बाहर के थे. 15 बार हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस एवं भाजपा को छोड़कर यहां के मतदाताओं ने सिर्फ़ दो बार अन्य दलों (जनता पार्टी और जनता दल) के प्रत्याशी और एक बार निर्दलीय उम्मीदवार को अपना प्रतिनिधि चुना. लखनऊ कभी नेहरू–गांधी खानदान का वैसे ही मजबूत गढ़ हुआ करता था, जैसे आज अमेठी और रायबरेली है. 1952 में हुए पहले चुनाव में जवाहर लाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित यहां से जीतीं. बाद में विजयलक्ष्मी राजदूत बनकर रूस चली गईं. उसके बाद हुए उपचुनाव में नेहरू की ही बहन शिवराजवती नेहरू विजयी हुईं. 1957 में कांग्रेस के पुलिन बनर्जी और 1962 में बी के धवन के सिर जीत का सेहरा बंधा. 1971, 1980 और 1984 में यह सीट एक बार फिर नेहरू खानदान की शीला कौल के पास रही. कांग्रेस को आपातकाल के बाद यहां बहुत बड़ा झटका लगा और 1977 में जनता पार्टी के टिकट से हेमवती नंदन बहुगुणा चुनाव जीत गए, वहीं 1989 में जनता दल के टिकट से मान्धाता सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे. इसे महज इत्तेफाक ही कहा जाएगा कि भले ही लखनऊ के किसी भी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की साइकिल अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाई हो, लेकिन 1967 में यहां निर्दलीय उम्मीदवार एवं हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज पंडित आनंद नारायण मुल्ला की साइकिल (मुल्ला का चुनाव चिन्ह) खूब दौड़ी थी. आनंद नारायण मुल्ला के बाद लखनऊ से कभी कोई निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सका. फिल्म अभिनेता राज बब्बर, डॉ. कर्ण सिंह, राम जेठमलानी, भगवती सिंह एवं दाऊ जी गुप्त जैसे नेताओं ने भी लखनऊ से भाग्य आजमाया, परंतु उन्हें जीत नसीब नहीं हुई.

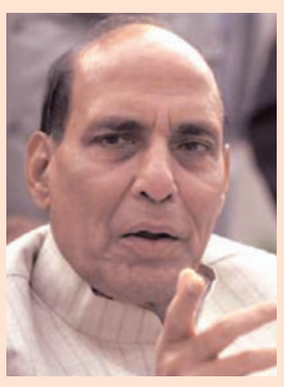

रही बात लखनऊ के सियासी मिजाज की, तो यहां कभी किसी प्रत्याशी के पक्ष में ध्रुवीकरण जैसे हालात नहीं बने. 1999 एवं 2004 के लोकसभा चुनाव में यहां से बसपा प्रमुख मायावती और 1998 एवं 2009 में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतार कर वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन उनका यह पैतरा चल नहीं पाया. 1998 में मुंबई की चकाचौंध से आए सपा प्रत्याशी मुजफ्फर अली ज़रूर भाजपा प्रत्याशी अटल बिहारी वाजपेयी को टक्कर देते नज़र आए और दूसरे स्थान पर रहे. इसके अलावा कभी कोई मुस्लिम प्रत्याशी मजबूती के साथ मुकाबले में खड़ा नहीं दिखा. यही वजह है कि इस बार यहां कांग्रेस, बसपा और समाजवादी पार्टी यानी किसी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा. 1998 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, जब मैदान में कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है. समाजवादी पार्टी को लेकर काफी अटकलें लगी थीं कि वह मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतार सकती है, लेकिन जब उसने भी चुनावी संध्या में क़रीब डेढ़ वर्ष पूर्व घोषित प्रत्याशी अशोक वाजपेयी का टिकट काटकर दूसरे ब्राह्मण प्रत्याशी अभिषेक मिश्र (अखिलेश सरकार में मंत्री एवं लखनऊ उत्तर से विधायक) को मैदान में उतारा, तो उसके मुस्लिम प्रत्याशी वाले सभी कयासों पर विराम लग गया.

बात 16वीं लोकसभा चुनाव के लिए लखनऊ में सजी सियासी बिसात की करें, तो इस बार हवा का रुख काफी बदला–बदला लग रहा है. लखनऊ का सांसद बनने के लिए दो विधायकों (लखनऊ कैंट से कांग्रेस की डॉ. रीता बहुगुणा जोशी एवं लखनऊ उत्तर से सपा के अभिषेक मिश्र) के अलावा गाजियाबाद संसदीय सीट छोड़कर लखनऊ में किस्मत आजमाने आए राजनाथ सिंह और पिछली बार बसपा के टिकट से ताल ठोंकने वाले नकुल दुबे प्रमुख रूप से इस बार भी मैदान में हैं. ऐसा लगता है कि लखनऊ में जो भी लड़ेगा, वह भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह के ख़िलाफ़ ही लड़ेगा. ऐसा अटल के नाम, राजनाथ के व्यक्तित्व और मोदी लहर के कारण होता दिख रहा है. राजनाथ ने टिकट काटे जाने से नाराज़ चल रहे मौजूदा सांसद एवं बुजुर्ग नेता लालजी टंडन के हाथों में अपने चुनाव की कमान सौंपकर उनकी नाराज़गी पर पानी डालने का काम कर दिया है. पिछली बार कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. रीता बहुगुणा जोशी ने भाजपा के लालजी टंडन को कड़ी टक्कर दी थी. इस बार भी वैसा ही होता दिख रहा है. हाल में ही समाजवादी पार्टी ने अपने सोलह महीने पहले से घोषित प्रत्याशी अशोक वाजपेयी को बदल कर राज्यमंत्री अभिषेक मिश्र को प्रत्याशी बनाकर नया दांव चला है. अभिषेक युवा हैं, पढ़े–लिखे हैं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के क़रीबी हैं और 2012 के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज कर चुके हैं. सपा सरकार के दो वर्षों के कार्यकाल पर भले ही उंगली उठ रही हो, लेकिन अभिषेक मिश्र के कामकाज से स्थानीय जनता संतुष्ट नज़र आती है. अभिषेक पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे.

जातीय गणित पर नज़र डालें, तो लखनऊ में क़रीब साढ़े चार लाख मुस्लिम, तीन लाख से ऊपर ब्राह्मण, क़रीब डेढ़ लाख पहाड़ी, दो लाख कायस्थ, एक लाख से ज़्यादा पिछड़े और ढाई लाख दलित मतदाता हैं. 2009 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं के दृष्टिगत सपा ने नफीसा अली को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्हें सिर्फ़ साठ हज़ार वोट मिले और जमानत तक जब्त हो गई थी. कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी की ब्राह्मणों में स्वीकार्यकर्ता देखकर मुस्लिम उनके पाले में खड़े हो गए. नतीजा यह हुआ, जो लालजी टंडन आसानी से जीतते हुए दिख रहे थे, वह सिर्फ़ 40 हज़ार वोटों से जीत हासिल कर पाए. सपा ने 2009 में मुस्लिम कार्ड खेला था, तो 2004 में बसपा यह दांव चल चुकी थी, लेकिन मुसलमानों को जब लगा कि लखनऊ में बसपा का आधार दलित वोट बहुत ज़्यादा नहीं है और दूसरी जातियां बसपा को वोट नहीं करेंगी, तो उन्होंने सपा की डॉ. मधु गुप्ता का समर्थन कर दिया. नतीजा यह हुआ कि बसपा का मुस्लिम उम्मीदवार सिर्फ़ 50 हज़ार वोट पा सका और उसकी जमानत जब्त हो गई.

खैर, राजनीतिक पंडितों का मानना है कि कांग्रेस, बसपा और सपा प्रत्याशी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़े, तो उसका फ़ायदा उनसे अधिक भाजपा के राजनाथ सिंह को मिलेगा. फिलहाल मुस्लिम मतदाताओं में भ्रम की स्थिति नज़र आ रही है, लेकिन मतदान वाले दिन वे ज़रूर तय कर लेंगे कि भाजपा प्रत्याशी को कौन सा ग़ैर–भाजपाई उम्मीदवार टक्कर दे सकता है. उसी के अनुसार वे मतदान कर देंगे. इससे सपा, बसपा और कांग्रेस किसी को भी फ़ायदा हो सकता है. आम आदमी पार्टी ने अभी तक यहां से प्रत्याशी नहीं तय किया है. वहीं तृणमूल कांग्रेस ने मोहम्मद सरवर मलिक को मैदान में उतारा है. लखनऊ संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाली पांच विधानसभा सीटों पर कभी भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहता था, लेकिन परिसीमन के बाद हुए विधानसभा चुनाव में पांच में से तीन सीटों पर सपा ने कब्जा कर लिया, कांग्रेस और भाजपा के खाते में एक–एक सीट आई. ■

feedback@chauthiduniya.com

ड्रीमगर्ल के नाम से मशहूर हेमामालिनी मथुरा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं. राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित सिंह के पुत्र जयंत चौधरी मथुरा से हेमामालिनी का सामना करते हुए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. उनका कहना है कि मथुरा संसदीय क्षेत्र में भाजपा का किसी स्तर पर प्रतिनिधित्व नहीं है.

गांधी की विरासत नहीं बदल सकी अमेठी की किस्मत

अमेठी संसदीय क्षेत्र से नेहरू-गांधी परिवार का रिश्ता बहुत पुराना है. अमेठी में इस परिवार का आगमन 1975 में हुआ था. तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी ने अमेठी के अतिपिछड़े गांव खेरौना में काम करना शुरू किया था. वह देश भर के चुनिंदा युवा कांग्रेसियों के साथ यहां श्रमदान करने आए. इसके जरिये उन्होंने सक्रिय राजनीति में आने का ऐलान किया. यह बात अलग है कि आज तक उस खेरौना गांव की स्थिति जैसी की तैसी बनी हुई है. संजय गांधी के अमेठी में सक्रिय होने के साथ ही देश में आपातकाल घोषित हो चुका था. इसके बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में संजय गांधी और इंदिरा गांधी की बुरी तरह पराजय हुई. 1977 में अमेठी निवासी रवींद्र प्रताप सिंह ने संजय गांधी को हराकर संसद में प्रवेश किया था. 1980 में हुए मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस की वापसी हुई. इंदिरा गांधी रायबरेली और संजय गांधी अमेठी से सांसद बने. संजय गांधी के निधन के बाद 1981 में राजीव गांधी अमेठी से सांसद बने. राजीव गांधी अपने जीवन के अंतिम समय तक संसद में अमेठी की नुमाइंदगी करते रहे. 1991 में चुनाव अभियान के दौरान ही राजीव गांधी की हत्या कर दी गई.

उसके बाद अमेठी की विरासत गांधी परिवार के बेहद क़रीबी कैप्टन सतीश शर्मा ने संभाली. सतीश शर्मा दो बार लगातार सांसद बने, केंद्र में पेट्रोलियम मंत्री का भी कार्यभार उन्हें मिला. उन्हीं के कार्यकाल में अमेठी क्षेत्र में राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी गई, लेकिन 1998 के लोकसभा चुनाव में अमेठी

कांग्रेस कहती रही है कि राहुल गांधी के प्रयासों से अमेठी में विकास की कई योजनाएं क्रियान्वित हुई हैं और अनेक प्रस्तावित हैं, जबकि बड़ी सच्चाई यह भी है कि कई योजनाओं का शुभारंभ तो चुनावी बयार के दौरान होता है, लेकिन बाद में उनका कहीं कोई पता नहीं चलता.

रियासत के राजकुमार डॉ. संजय सिंह ने भाजपा का दामन थामा. संजय सिंह ने उस चुनाव में कैप्टन सतीश शर्मा को हरा दिया. 1999 में सोनिया गांधी ने यहां से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. गांधी परिवार ने उसके बाद सियासत को खुलकर अपनाया. बाद में सोनिया गांधी ने जहां अपनी सास इंदिरा गांधी की संसदीय सीट रायबरेली अपनाई, वहीं उनके बेटे राहुल गांधी

ने अमेठी का नेतृत्व किया. राहुल गांधी 2004 के आम चुनाव में पहली बार अमेठी से सांसद बने. 2009 में भी राहुल गांधी ने जीत दर्ज की, लेकिन आज तक अमेठी विकास की उस किरण के लिए तरस रही है, जिसकी वहां के लोगों ने उम्मीद लगाई थी. दूसरी तरफ़ गांधी परिवार का संसदीय क्षेत्र के लिए बेहद कम उपलब्ध हो पाना भी लोगों की नाराज़गी की अहम वजह है.

बहरहाल, एक बार फिर 2014 की रणभेरी बज चुकी है. वैसे तो राहुल गांधी के ख़िलाफ़ आम तौर पर कोई विपक्षी दल मजबूत उम्मीदवार नहीं उतारता, लेकिन इस बार मामला उलट है. आम आदमी पार्टी ने कुमार विश्वास को यहां से राहुल गांधी के ख़िलाफ़ मैदान में उतारा है. कुमार विश्वास अब गांव-गांव जाकर खुलकर कह रहे हैं कि राहुल गांधी युवराज हैं, अमेठी की जनता उनसे मिलने को तरस जाती है, लेकिन अगर वह जीते, तो हर वक्त जनता के लिए उपलब्ध रहेंगे. उधर भाजपा ने स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के ख़िलाफ़ चुनाव में उतारने का मन बनाया है. दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष एवं स्टार प्रचारक वरुण गांधी लोकसभा चुनाव में अपने चचेरे भाई एवं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के ख़िलाफ़ अमेठी में प्रचार न करने का ऐलान कर चुके हैं.

कांग्रेस कहती रही है कि राहुल गांधी के प्रयासों से अमेठी में विकास की कई योजनाएं क्रियान्वित हुई हैं और अनेक प्रस्तावित हैं, जबकि बड़ी सच्चाई यह भी है कि कई योजनाओं का शुभारंभ तो चुनावी बयार के दौरान होता है, लेकिन बाद में उनका कहीं कोई पता नहीं चलता. शिक्षा, चिकित्सा, सड़क एवं परिवहन आदि के मामले में आज भी अमेठी प्रदेश के अन्य वीआईपी संसदीय क्षेत्रों से कहीं पीछे है. कांग्रेस इसकी सियासी वजह बताती हो, लेकिन अमेठी की जनता बार-बार इसी तर्क को सुनना नहीं चाहती. इसीलिए अपने ही गढ़ के गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए जाने जैसे विरोध का सामना करना पड़ चुका है. कांग्रेस दिखावे के तौर पर भले ही कुछ भी कहती रहे, लेकिन जिस तरीके से उसे पार्टी के अंदर और बाहर विरोध का सामना करना पड़ रहा है, वह कहीं न कहीं क्षेत्रीय लोगों की उपेक्षा और उनसे दूरी का नतीजा है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सवाल जीत-हार का नहीं, प्रतिष्ठा का

अरुण तिवारी

निराला शहर वाराणसी दुनिया भर में मशहूर है. गंगाघाट, अल्हड़पन, धार्मिकता, संगीत और ऐसी अनगिनत ख़ूबियां यह शहर स्वयं में समेटे हुए है. राजनीति तो जैसे इस शहर की धमनियों में बहती है. सिर्फ़ इतना ही नहीं, देश के कई हिस्सों से इतर यहां का हर वाशिंदा राजनीति में डूबा हुआ अपनी भावनाओं का इजहार करने को आतुर रहता है. इस बार लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कुछ खास घटित हो रहा है. शायद पहली बार इस लोकसभा क्षेत्र में दो राजनीतिक पार्टियों के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार आमने-सामने हैं. बात हो रही है भाजपा के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की. इसलिए पूरे देश के साथ-साथ दुनिया की नजर भी वाराणसी पर टिकी हुई है. अरविंद केजरीवाल ने काफी समय पहले घोषणा की थी कि नरेंद्र मोदी देश में जहां से भी उम्मीदवार होंगे, वह वहीं से चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने वही किया भी. जैसे ही नरेंद्र मोदी के यहां से चुनाव लड़ने की घोषणा हुई, अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी दावेदारी पेश करने में तनिक भी देर नहीं लगाई. इसी के बाद वाराणसी सीट पर चुनाव ज़्यादा दिलचस्प हो गया है. इस सीट का परिणाम बताएगा कि अरविंद केजरीवाल जनता के बीच अपनी बात कह पाने में ज़्यादा सक्षम हुए या फिर नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल ने जनता को अपनी तरफ़ ज़्यादा आकर्षित किया. इस सीट से कई और भी दावेदार मैदान में मौजूद हैं. बसपा ने यहां से विजय प्रकाश जायसवाल को उतारा है, वहीं मऊ के विधायक एवं कई पार्टियों की सैर कर चुके, मगर इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहे मुख्तार अंसारी भी मुस्लिम वोटों को देखते हुए मैदान मारने का ऐलान कर रहे हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें भाजपा के कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी ने वाराणसी से ही मात दी थी. मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय हत्याकांड में आरोपी भी हैं.

अरविंद केजरीवाल ने काफी समय पहले घोषणा की थी कि नरेंद्र मोदी देश में जहां से भी उम्मीदवार होंगे, वह वहीं से चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने वही किया भी. जैसे ही नरेंद्र मोदी के यहां से चुनाव लड़ने की घोषणा हुई, अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी दावेदारी पेश करने में तनिक भी देर नहीं लगाई.

जिस बात ने इस सीट को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाया, वह है नरेंद्र मोदी का यहां से चुनाव लड़ना. यहां से मोदी के चुनावी समर में उतरने के बाद शहर का चुनावी पारा काफी गरमाया हुआ है. इस सीट से मोदी की उम्मीदवारी को लेकर भी काफी जद्दोजहद हुई, क्योंकि यहां पहले से पार्टी की मजबूत धुरियों में से एक मुरली मनोहर जोशी मौजूद थे. एक और बात जो जोशी को यहां से हटाकर भाजपा में साबित कर दी गई कि पार्टी में मोदी के आगे अब किसी दूसरे की बात का न कोई महत्व है और न कोई औचित्य. जोशी को हटाने के पीछे तर्क यह दिया गया कि अगर नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़ते हैं, तो वह पूर्वांचल की लगभग 30-32 सीटों को प्रभावित कर सकेंगे. मोदी के लिए एक तो जनता में माहौल है, वहीं दूसरी ओर मीडिया भी उनकी लौहपुरुष की छवि गढ़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है. हर तरफ़ उनकी विकास पुरुष वाली छवि न सिर्फ़ बनाई जा रही, बल्कि मोदी खुद अपने भाषणों के दौरान भी ऐसा ही जता और समझा रहे हैं कि देश की समस्याओं का अब सिर्फ़ एक ही विकल्प मौजूद है और वह है नरेंद्र मोदी. इस सीट पर लड़ाई को और दिलचस्प बनाने का श्रेय अरविंद केजरीवाल को जाता है. वह दिल्ली विधानसभा चुनाव में शीला दीक्षित को हराकर बड़ा उलट-फेर कर चुके हैं. शायद उन पर उसी जीत का असर है कि वह नरेंद्र मोदी जैसे लोकप्रिय नेता के साथ दो-दो हाथ करने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं. दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली थी. उसने पहली ही बार चुनाव लड़कर 28 सीटें जीतने में सफलता हासिल की थी. इसके बाद वह कांग्रेस के समर्थन से राज्य के मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन उन्होंने जल्द ही कई मजबूरियां बताते हुए त्यागपत्र दे दिया. ऐसा कहा जा रहा है कि केजरीवाल की निगाहें प्रधानमंत्री पद पर थीं और चूंकि दिल्ली में राज्य सरकार के पास कई अधिकार नहीं होते, उन्होंने अपना पद छोड़ना ही बेहतर विकल्प समझा. हालांकि जनता उनसे इस सवाल का जवाब जानने को बेताब है कि आख़िर बिना कोई ठीकठाक ज़िम्मेदारी निभाए उन्होंने ऐसा क्यों किया?

अब इस लोकसभा सीट का परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है. अब यह सीट चुनावी हार-जीत से ऊपर उठकर प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है. देखना यह होगा कि इस चुनावी समर में बाजी कौन मारता है? ■

चुनावी महाकुंभ में फिल्मी सितारे

दर्शन शर्मा

कांग्रेस, भाजपा एवं अन्य राजनीतिक दल चुनावों में फिल्म जगत के चुनिंदा सितारों को अपने प्रचारक के रूप में पेश करते थे, जिससे वे जनता का वोट बटोरने में काफी हद तक सफल भी होते रहे. समय बदला, चुनाव हाईटेक होने लगे, तो फिल्मी सितारों से प्रचार कराने की बजाय पार्टियां उन्हें टिकट देकर जनता के बीच उतारने लगीं. जनता ने भी उन्हें सिर-आंखों पर बैठाकर, वोट देकर जिताया. यह बाज़ार इतना गर्म हुआ कि इसमें न केवल फिल्म जगत, बल्कि खेल जगत के प्रसिद्ध खिलाड़ी भी कूदने को आतुर हुए. देश के किसी कोने से चुनाव लड़कर वे संसद की दहलीज आसानी से लांघ गए. सोलहवीं लोकसभा चुनाव में सिनेमा और सियासत के बीच जो धुरंधर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें क़रीब 150 फिल्मों में काम कर चुके राजबब्बर भी शामिल हैं, जो 1994 में राज्यसभा के जरिये राजनीति में आए. वह तेरहवीं एवं चौदहवीं लोकसभा चुनाव के आगरा से सांसद बने. पंद्रहवीं लोकसभा में राजबब्बर फिरोजाबाद से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह की बहू डिंपल को हराकर कांग्रेस के सांसद बने. इस बार वह गाज़ियाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं. वह जनमोर्चा, समाजवादी पार्टी होते हुए अब कांग्रेस में हैं. राजनीतिक गलियारों में राजबब्बर के लिए कहा जाता है कि वह विश्वसनीय हैं और ज़िम्मेदार भी. राजबब्बर कहते हैं कि वह सिनेमा के साथ-साथ राजनीति में सक्रिय हैं और गंभीर भी.

1996 में तेलुगुदेशम पार्टी से राज्यसभा में पहुंच कर अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने वाली जयाप्रदा 2004 एवं 2009 में सपा के टिकट पर उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद बनीं. अब वह अजित सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर बिजनौर से संसद में पहुंचने की राह पर अग्रसर हैं. भोजपुरी फिल्मों के हीरो रवि किशन जौनपुर से राजनीति की वैतरणी पार करके कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके समर्थन में वहां के हालात कोई बहुत सुकून देने वाले नहीं हैं.

1996 में तेलुगुदेशम पार्टी से राज्यसभा में पहुंच कर अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने वाली जयाप्रदा 2004 एवं 2009 में सपा के टिकट पर उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद बनीं. अब वह अजित सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर बिजनौर से संसद में पहुंचने की राह पर अग्रसर हैं. भोजपुरी फिल्मों के हीरो रवि किशन जौनपुर से राजनीति की वैतरणी पार करके कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके समर्थन में वहां के हालात कोई बहुत सुकून देने वाले नहीं हैं. रवि किशन के लिए एक अहम बात यह मानी जा रही है कि परदे की पटकथा से लेकर निजी जीवन की हर कथा, अंतर्कथा और व्यथा में हर तरह के साथ निभाने वाली उनकी सहेली नगमा भी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर इस बार मेरठ से चुनाव लड़ रही हैं. रवि एवं नगमा की कई फिल्में हिट रही हैं. कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने वक्त रहते कानपुर से समाजवादी पार्टी का टिकट लौटाकर अपनी इज्जत बचा ली और बाद में भाजपा में चले गए.

ड्रीमगर्ल के नाम से मशहूर हेमामालिनी मथुरा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं. राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित सिंह के पुत्र जयंत चौधरी मथुरा से हेमामालिनी का सामना करते हुए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. उनका कहना है कि मथुरा संसदीय क्षेत्र में भाजपा का किसी स्तर पर प्रतिनिधित्व नहीं है. न तो भाजपा की किसी विधानसभा सीट से कोई उम्मीदवार जीता है और पंचायत पार्षद के तौर पर. उन्होंने अपने कार्यकाल में किए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी मुख्य लड़ाई भाजपा से है. उसके लिए वह पूरी तरह तैयार हैं. अमेठी से भाजपा ने छोटे पर्दे पर बहू का किरदार निभा चुकीं स्मृति ईरानी को टिकट दिया है. उनका मुकाबला कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से है. आप ने अभिनेता जावेद जाफरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के सामने लखनऊ से उतारा है. देखना यह है कि इनमें से किसे जीत मिलती है. ■

अगर स्थानीय गारो जनजाति के 272 लोगों को मतदान का अधिकार मिला है, तो उसका स्वागत होना चाहिए. स्थानीय प्रशासन को बुनियादी सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए. गारो जनजाति बहुल सभी चौदह गांवों के लोगों को मनरेगा के तहत काम मिलना चाहिए, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो. राज्य एवं केंद्र सरकार को चाहिए कि वे उनके लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करें.

झारखंड

दांव पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा

मंगलानंद

विभिन्न राजनीतिक दलों ने राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है. वे यहां की 14 सीटों में से अधिक से अधिक अपने खाते में करने की कोशिश कर रहे हैं. राज्य के कई राजनीतिक दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. क्षेत्रीय दलों की सक्रियता से राष्ट्रीय दलों के नेताओं की नींद उड़ गई है. रही-सही कसर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने पूरी कर दी है. सभी दलों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं. दुमका संसदीय सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, राजमहल संसदीय सीट पर पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू, रांची संसदीय सीट पर आजसू अध्यक्ष एवं पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुदेश महतो, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, गोड्डा के वर्तमान सांसद निशिकांत दुबे, गिरिडीह संसदीय सीट पर भाजपा के वर्तमान सांसद रवीन्द्र पाण्डेय, हजारीबाग संसदीय सीट पर भाजपा के दिग्गज नेता यशवंत सिन्हा के पुत्र जयंत सिन्हा, सक्सेस गुरु अरुण कुमार मिश्र, आजसू के लोकनाथ महतो और कांग्रेस विधायक सौरभ नारायण सिंह, पलामू संसदीय सीट पर पूर्व डीजीपी एवं भाजपा प्रत्याशी बी डी राम, कोडरमा संसदीय सीट पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रवीन्द्र कुमार राय, धनबाद संसदीय सीट पर पी एन सिंह और तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री ददई दुबे सहित दो दर्जन ऐसे दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लग चुकी है, जिनकी झारखंड की राजनीति में मजबूत पकड़ मानी जाती है.

संथाल परगना में इस बार सबसे अहम मुकाबला होने के आसार हैं, क्योंकि दो-दो पूर्व मुख्यमंत्री यानी बाबूलाल मरांडी और शिबू सोरेन चुनाव मैदान में आमने-सामने हैं. दोनों अपने-अपने दलों के प्रमुख भी हैं. शिबू सोरेन के बेटे हेमंत फिलवक्त राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए दुमका सीट के लिए उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. वहीं झारखंड विकास मोर्चा प्रमुख बाबूलाल मरांडी दो बार दुमका के सांसद रह चुके हैं. संथाल परगना की तीन सीटों दुमका, गोड्डा एवं राजमहल के लिए तीसरे दौर में 24 अप्रैल को मतदान होगा.

तृणमूल कांग्रेस ने रांची लोकसभा सीट से मांडर विधायक बंधु तिर्की और लोहरदगा से बिशुनपुर विधायक चमरा लिंडा को चुनाव मैदान में उतारा है. पलामू से कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबले में तीन ही माने जा रहे हैं. भाजपा के बी डी राम, राजद के मनोज भुइयां और झाविमो के घुरन राम के बीच कड़ी टक्कर का अनुमान है. पलामू में पुलिस के शीर्ष पद से सेवानिवृत्त बी डी राम और नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर संसद का सफर करने के इच्छुक कामेश्वर बैठा आमने-सामने होंगे. कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के कुल 21 प्रत्याशियों में ज़्यादातर ऐसे हैं, जो पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं. कुछ प्रत्याशी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और कई बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं. कांग्रेस प्रत्याशी तिलकधारी प्रसाद सिंह छठवीं बार चुनाव लड़ रहे हैं. भाकपा (माले) के राजकुमार यादव तीसरी बार, जबकि झाविमो के प्रणव वर्मा एवं सपा के जयदेव चौधरी दूसरी बार चुनाव मैदान में हैं. झाविद के सूरज मंडल भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं. भाजपा के रवीन्द्र कुमार राय, आजसू के नजरुल हसन हाशमी, बसपा के विशेश्वर प्रसाद, जदयू के कृष्णा सिंह, आप के विजय चौरसिया, फारवर्ड ब्लॉक के रघुनंदन विश्वकर्मा, तृणमूल कांग्रेस की मंजू कुमारी समेत निर्दलीय प्रत्याशी कंचन कुमारी, रामेश्वर प्रसाद यादव, योगेंद्र राम, फलजीत महतो, जलील अंसारी, मनोज कुमार सिंह, शिवनाथ साव, महेंद्र दास एवं मुस्तकीम अंसारी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं.

संथाल परगना में इस बार सबसे अहम मुकाबला होने के आसार हैं, क्योंकि दो-दो पूर्व मुख्यमंत्री यानी बाबूलाल मरांडी और शिबू सोरेन चुनाव मैदान में आमने-सामने हैं. दोनों अपने-अपने दलों के प्रमुख भी हैं. शिबू सोरेन के बेटे हेमंत फिलवक्त राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए दुमका सीट के लिए उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. वहीं झारखंड विकास मोर्चा प्रमुख बाबूलाल मरांडी दो बार दुमका के सांसद रह चुके हैं. संथाल परगना की तीन सीटों दुमका, गोड्डा एवं राजमहल के लिए तीसरे दौर में 24 अप्रैल को मतदान होगा. दुमका सीट से अपने पिता शिबू सोरेन की जीत सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं. भाजपा के सुनील सोरेन ने पिछले चुनाव में शिबू सोरेन को कड़ी टक्कर दी थी और वह बहुत कम मतों से हारे थे. भाजपा ने इस बार फिर उन पर दांव लगाया है. यह सीट समझौते के तहत झामुमो को गई है, इसलिए यहां से कांग्रेस का कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है.

गोड्डा में जदयू द्वारा राजवर्धन आज़ाद को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद भाजपा के निशिकांत दुबे घिरते नज़र आ रहे हैं. राजवर्धन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आज़ाद के पुत्र हैं. उनका कार्यक्षेत्र संथाल रहा है और ससुराल देवघर में है. क्षेत्र में उनके परिवार का प्रभाव है और प्रतिष्ठा भी. वह यहां के ब्राह्मण बाहुल्य तीन विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं. कांग्रेस ने यहां से पूर्व सांसद फुरकान अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि झाविमो से पूर्व सांसद प्रदीप यादव चुनाव लड़ रहे हैं. फुरकान अंसारी का मुसलमान मतदाताओं में अच्छे-खासे प्रभाव से भी भाजपा प्रत्याशी को निपटना होगा. प्रदीप यादव भी भाजपा से सांसद रहे हैं. इस बार उन्हें झाविमो ने मैदान में उतारा है. कार्यकर्ताओं की नाराज़गी भी भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे को भारी पड़ सकती है. राजमहल क्षेत्र में भी भाजपा कार्यकर्ता खासे नाराज़ हैं. यहां मुख्य मुकाबला झामुमो के विजय हांसदा और भाजपा के हेमलाल मुर्मू के बीच होने की संभावना है. विजय हांसदा ईसाई एवं मुस्लिम मतों के भरोसे हैं, वहीं मुर्मू को भाजपा के परंपरागत वोटों के अलावा ग़ैर ईसाई मतदाताओं का सहारा है. मुर्मू की राह में रोड़े अटकाने के लिए झामुमो और झाविमो के नेता सक्रिय हो गए हैं. हेमंत सोरेन को चुनौती देकर राजनीति में अपने ऊंचे कद का परिचय देने वाले हेमलाल मुर्मू इस बार नए अवतार में लोगों के बीच हैं.

राज्य में टीएमसी का बढ़ता असर भी लोगों को देखने को मिलेगा. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के झारखंड आगमन के बाद सभी दलों के नेताओं के होश उड़े हुए हैं. देखना यह है कि राज्य के किन राजनीतिक दिग्गजों की लुटिया डूबती है और किसकी बचती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

मेघालय

जिन्हें अपने ही देश में वोट देने का हक़ नहीं

क्या मेघालय हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर यह सूबा इस देश का अंग है, तो मेघालय के क़रीब सात हज़ार लोगों को आज़ादी के 66 वर्षों बाद भी वोट देने का अधिकार क्यों नहीं है? आख़िर देश के बाकी हिस्सों की तरह यहां के लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया क्यों नहीं कराई गई हैं?

एस. बिजेन सिंह

मेघालय को संपूर्ण राज्य का दर्ज़ा मिले चालीस साल गुज़र गए, लेकिन राज्य के एक समूह को आज भी चुनावों में वोट देने का अधिकार नहीं है. इस साल गारो जनजातीय समूह के 272 लोग संसदीय चुनाव में पहली बार हिस्सा लेंगे, हालांकि वे इससे पहले राज्य विधानसभा और स्वायत्त परिषद् के चुनावों में मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं. ग़ौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट देने जा रही गारो जनजाति पूर्वी खासी हिल्स ज़िले में बसी हुई है. इस समुदाय के 7000 लोगों ने आज़ादी के बाद से अभी तक किसी चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उनके नाम राज्य की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं. मताधिकार से वंचित उक्त सभी लोग भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित क़रीब 14 गांवों में पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं. उनमें से सिर्फ़ 272 लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल करके उन्हें मतदाता पहचानपत्र निर्गत किया गया है. बेशक वे पहली बार आम चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवारों के बारे में कुछ भी पता नहीं है.

राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है. आयोग के मुताबिक़, गारो जनजाति के 7000 लोगों को अभी तक मताधिकार नहीं मिला है, इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हुआ जा सकता. अगर सरकारी स्तर पर कोई लापरवाही है, तो उसे अविलंब दूर किया जाएगा, साथ ही मतदाताओं को जागरूक भी किया जाएगा. उल्लेखनीय है कि मेघालय में तीन प्रमुख जनजातियां हैं, गारो, खासी और जयंती. आबादी के लिहाज़ से गारो राज्य की दूसरी बड़ी जनजाति है. याद रखने वाली बात यह है कि वर्ष 1971 में हुए बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय क़रीब 1500 ग़ैर स्थानीय आदिवासियों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा था. यही वजह है कि वे भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट बसे 14 गांवों में तबसे रह रहे हैं. वे शासन-प्रशासन की तरफ़ से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हैं.

देर से ही सही, अगर स्थानीय गारो जनजाति के 272 लोगों को मतदान का अधिकार मिला है, तो उसका स्वागत होना चाहिए. स्थानीय प्रशासन को बुनियादी सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए. गारो जनजाति बहुल सभी चौदह गांवों के लोगों को मनरेगा के तहत काम मिलना चाहिए, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो. राज्य एवं केंद्र सरकार को चाहिए कि वे उनके लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करें. बहरहाल, इस बीच पी ए संगमा के नेतृत्व वाली एनपीपी ने गारोलैंड राज्य की मांग का समर्थन किया है. गारो हिल्स स्टेट मूवमेंट कमेटी (जीएचएसएमसी) ने संगमा के इस फ़ैसले का स्वागत किया है. उसके मुताबिक़, एनपीपी का यह फ़ैसला क़ाबिल-ए-तारीफ़ है. ग़ौरतलब है कि गारो जनजाति की समस्याओं के मद्देनज़र एनपीपी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में इस समुदाय के हितों को शामिल किया है. गारो हिल्स स्टेट मूवमेंट कमेटी की मानें, तो पी ए संगमा का यह निर्णय क्षेत्र की जनता के लिए सही साबित होगा. उसके अनुसार, संगमा बतौर सांसद काफ़ी अच्छा काम करेंगे. वहीं दूसरी तरफ़ पी ए संगमा के इस समर्थन पर मेघालय के मुख्यमंत्री डॉ. मुकुल संगमा ने नाराज़गी ज़ाहिर की है. उनके अनुसार, यह सिर्फ़ राजनीतिक फ़ायदे के लिए किया गया एक फ़ैसला है और यह गारो जनजाति के हितों के ख़िलाफ़ है. उन्होंने कहा कि पी ए संगमा गारो जनजाति के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं. मुख्यमंत्री ने पी ए संगमा को भाजपा का एजेंट तक क़रार दे दिया. उनके इस बयान से प्रदेश भाजपा नेताओं में गहरी नाराज़गी है. ग़ौरतलब है कि मेघालय में एनपीपी का भाजपा के साथ गठबंधन है. वर्ष 2012 में पी ए संगमा को एनसीपी से निलंबित कर दिया गया था. उसके बाद उन्होंने एनपीपी नामक पार्टी का गठन किया. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

पहले विचारधारा स्पष्ट कीजिए

मैं वास्तव में यह नहीं जानता कि आम आदमी पार्टी में क्या हो रहा है, लेकिन एक परेशानी वाली बात यह है कि इस पार्टी ने भी अब तक अपनी विचारधारा सार्वजनिक नहीं की है. अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा कि वह विचारधारा को बहुत ज़्यादा नहीं समझते. अच्छी बात है, लेकिन दिल्ली जैसे छोटे राज्य को चलाना और देश चलाना अलग-अलग बातें हैं. अगर आप देश चलाना चाहते हैं, तो फिर आपको अपनी विचारधारा की व्यापक रूपरेखा स्पष्ट करनी होगा. विचारधारा के बिना कोई आधार नहीं होगा.

राजनीतिक दलों के भीतर अचानक बढ़ी गतिविधियों ने चुनावी परिदृश्य में कई नए मोड़ ला दिए हैं. मीडिया हमें यह यकीन दिलाना चाहता है कि सब लोग भाजपा की ओर भागना चाहते हैं. यह उन राज्यों के लिए कुछ हद तक सही हो सकता है, जहां भाजपा की अच्छी उपस्थिति है. यह सही है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर वह सरकार बनाते हैं, तो देश जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, उससे मुक्ति दिला देंगे. सही बात है कि मोदी एक निर्णायक व्यक्ति के रूप में सामने आए हैं. हालांकि, यह कहानी का एक पहलू है. दूसरा पहलू यह है कि देश के अन्य हिस्सों में भाजपा अनुपस्थित है. यह देश का एक बड़ा हिस्सा है. वहां क्या होता है, यह महत्वपूर्ण है. कोई कुछ भी कहे, वहां अन्य पार्टियां होंगी, कांग्रेस पार्टी होगी, क्षेत्रीय दल होंगे. भाजपा वहां कुछ भी करने में सक्षम नहीं होगी. बेशक, चुनाव के बाद वह नई लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी होगी और चुनाव में मिली सीटों के मुताबिक सत्ता में आने के लिए एक, दो या तीन छोटे दलों के साथ गठबंधन करने का प्रयास करेगी. ऐसा हो सकता है. खास तौर पर तब, जब शरद पवार जैसा एक परिपक्व राजनेता यह कहता हो कि उनके हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होगी और इसके बाद कांग्रेस. अब कांग्रेस कितना पीछे जाती है, यह कोई नहीं कह सकता.

नई सरकार के गठन में क्षेत्रीय दलों की निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका होगी. चाहे वे भाजपा के साथ आएं या एक मजबूत गठबंधन बनाकर कांग्रेस का समर्थन लें. बहरहाल, यह सब चुनाव के नतीजों पर निर्भर करता है. हम अभी जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, उसका उद्देश्य अलग है. मान भी लें कि भाजपा कुछ गठबंधन के साथ एक सरकार बना लेती है, फिर भी परेशानी की बात यह है कि भाजपा हमें अपने विचारों से अवगत नहीं करा रही है. हम जानते हैं कि कांग्रेस किस तरह का भारत बनाना चाहती है. वह अल्पसंख्यकों को एक वोट बैंक के रूप में देखती है, इस बात को लेकर हमारी शिकायतें हो सकती हैं. हम यह भी कह सकते हैं कि उसने यह नहीं किया, वह नहीं किया, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हावी रहा और नुकसान पहुंचाता रहा, लेकिन भाजपा ने अभी तक यह जाहिर नहीं होने दिया कि क्या वह अभी भी उसी विचारधारा को अपनाती है, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे सामने आई थी? क्या वह अभी भी दलित आरक्षण होना चाहिए वाली बात मानती है?

क्या वह मानती है कि अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, लघु उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए? या फिर वह यह मानती है कि अमीर और अमीर बनता रहे और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा. जहां तक अल्पसंख्यकों का सवाल है, वे डर रहे हैं, वे भाजपा के सत्ता में आने की बात को लेकर डर रहे हैं. हालांकि, उनके डर को उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के छह साल के शासन के दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे डरा जाए, लेकिन वह अटल बिहारी वाजपेयी थे. हमें इस नए शख्स के बारे में पता नहीं है.

“नई सरकार के गठन में क्षेत्रीय दलों की निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका होगी. चाहे वे भाजपा के साथ आएं या एक मजबूत गठबंधन बनाकर कांग्रेस का समर्थन लें. बहरहाल, यह सब चुनाव के नतीजों पर निर्भर करता है. हम अभी जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, उसका उद्देश्य अलग है. मान भी लें कि भाजपा कुछ गठबंधन के साथ एक सरकार बना लेती है, फिर भी परेशानी की बात यह है कि भाजपा हमें अपने विचारों से अवगत नहीं करा रही है.”

दूसरी बात. आम आदमी पार्टी ने एक अच्छे वादे के साथ शुरुआत की थी. उसके समर्थक कह रहे हैं कि पूरे देश में सौ सीटें मिल जाएंगी. ऐसा होता तो नहीं लगता, लेकिन वास्तव में सौ सीटें मिल जाती हैं, तो यह फिर नई राजनीति की शुरुआत होगी. कई मायने में यह अच्छा होगा, लेकिन जिस तरह से सब कुछ होता दिख रहा है, उससे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा. जिस तरीके से पार्टी के लोग टिकट लौटा रहे हैं, उससे लगता है कि शायद वे संसाधन जुटा पाने में सक्षम नहीं हैं. आम आदमी पार्टी का विश्वास है कि पैसा उन्मुख राजनीति नहीं होनी चाहिए. राजनीति सीधे मतदाताओं के संपर्क में रहकर होनी चाहिए, चाहे सोशल मीडिया के जरिये या इंटरनेट के जरिये. लेकिन, अब वह भी पारंपरिक तरीके अपनाने की कोशिश करती दिख रही है. अगर वह ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना चाहती है, बड़ी रैलियां करना चाहती है, तो निश्चित रूप से वह नुकसान में रहेगी. इस मामले में कांग्रेस और भाजपा उससे कहीं आगे होंगी.

मैं वास्तव में यह नहीं जानता कि आम आदमी पार्टी में क्या हो रहा है, लेकिन एक परेशानी वाली बात यह है कि इस पार्टी ने भी अब तक अपनी विचारधारा सार्वजनिक नहीं की है. अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा कि वह विचारधारा को बहुत ज़्यादा नहीं समझते. अच्छी बात है, लेकिन दिल्ली जैसे छोटे राज्य को चलाना और देश चलाना अलग-अलग बातें हैं. अगर आप देश चलाना चाहते हैं, तो फिर आपको अपनी विचारधारा की व्यापक रूपरेखा स्पष्ट करनी होगा. विचारधारा के बिना कोई आधार नहीं होगा.

कुल मिलाकर परिदृश्य अभी भी भ्रामक है. बेशक पारंपरिक ज्ञान यह कहता है कि भाजपा को 180 सीटें मिल जाएं और वह अकाली दल, शिवसेना और कुछ अन्य ऐसे सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बना ले, जिनके पास 20, 30 या 40 सीटें हों, लेकिन वह किस तरह की सरकार देने में सक्षम होगी, हम नहीं जानते. सत्ता विरोधी लहर में यह कहना आसान है कि मुद्रास्फीति बड़े पैमाने पर बढ़ी है. अब आप कैसे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने जा रहे हैं, इसके बारे में कोई उपाय नहीं बताया जा रहा है. किसानों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है. वे औद्योगिक विकास, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे तमाम बिंदुओं पर बात कर रहे हैं, लेकिन कोई कृषि की दुर्दशा के बारे में बात नहीं कर रहा है. भारत में असली समस्या कृषि की है. कृषि क्षेत्र की वर्तमान हालत अगर दस साल भी रह जाए, तो भविष्य में हमें खाद्यान्न की कमी से जूझना पड़ेगा. जो भी पार्टी सत्ता में आती है, उसे समझना होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और जब तक कृषि को प्रमुखता नहीं दी जाएगी, देश के उज्ज्वल भविष्य की आशा नहीं की जा सकती. मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस और भाजपा इस बारे में बातें और वादे कर रही हैं. बहरहाल, जितनी जल्दी इस समस्या का समाधान निकलेगा, उतना ही इस देश के बेहतर भविष्य के लिए अच्छा होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

समेकित बाल विकास योजना का सच

सैय्यद एजाज़ उल हक़ बुखारी

बफलियाज़ से 9 किलोमीटर की दूरी पर मड़हा गांव है. यहां के आईसीडीएस केंद्र की कहानी बड़ी अजीबो-ग़रीब है. स्थानीय निवासी मौलाना नूर ए इलाही नक्शबंदी कहते हैं कि गांव के एक ही मोहल्ले में दो केंद्र हैं और दोनों एक साथ दो भाइयों के घर में चलते हैं. एक को नीचे और दूसरे को ऊ पर की मंजिल मिली हुई है.

भारत सरकार द्वारा 1975 में समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर आंगनवाड़ी एवं लघु आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किए जाते हैं. योजना का मुख्य उद्देश्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती-स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षिक सेवाओं का ध्यान रखना है. 2009-10 के केंद्रीय बजट के अनुसार, योजना के तहत उक्त सभी सेवाएं इस आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता के साथ उपलब्ध कराई जाएगी. योजना पर खास ध्यान देते हुए 2012-13 के बजट में इसके लिए 15,870 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. इसके बावजूद देश के दूरदराज के इलाकों में इस योजना का क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पा रहा है. सीमावर्ती इलाकों में सरकार की यह योजना सिर्फ़ फाइलों में सिमट कर रह गई है. सवाल यह पैदा होता है कि क्या केंद्र सरकार की इस योजना का फ़ायदा वास्तव में उन लोगों तक पहुंच रहा है, जिनके लिए यह शुरू की गई थी?

जम्मू-कश्मीर के पुंछ ज़िले की सुरनकोट तहसील के फागला के मोहल्ला कसलां स्थित आंगनवाड़ी केंद्र की संरक्षिका मुंबई में रहती हैं. यह केंद्र तब खुलता है, जब राशन वगैरह बच्चों के लिए आता है. यह सामान आने के बाद कहां जाता है, इसका कुछ पता नहीं? इस बारे में संबंधित विभाग का कहना है कि जांच हो रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस दिन टीम जांच के लिए पहुंचती है, बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और केंद्र खुल जाता है. सुरनकोट के गांव बफलियाज़ के मोहल्ला सेठा का आंगनवाड़ी केंद्र दोपहर 12 बजे तक बंद मिला. केंद्र सहायिका ने बताया कि संरक्षिका की शादी मंडी तहसील में हो गई है, इस वजह से वह कभी-कभी आती हैं. जब सहायिका से पूछा गया कि आप केंद्र को समय पर और नियमित रूप से क्यों नहीं खोलतीं? तो जवाब मिला, आपको यह पूछने का हक़ किसने दिया? जब संरक्षिका से फोन द्वारा जानने की कोशिश की गई, तो उन्होंने भी सहायिका वाला जवाब दोहरा दिया.

बफलियाज़ से 9 किलोमीटर की दूरी पर मड़हा गांव है. यहां के आईसीडीएस केंद्र की कहानी बड़ी अजीबोग़रीब है. स्थानीय निवासी मौलाना नूर ए इलाही नक्शबंदी कहते हैं कि गांव के एक ही मोहल्ले में दो केंद्र हैं और दोनों एक साथ दो भाइयों के घर में चलते हैं. एक को नीचे और दूसरे को ऊ पर की मंजिल मिली हुई है. दूसरी ओर इसी गांव में एक ऐसा मोहल्ला ऐसा भी है, जहां पर तक़रीबन 40 घर हैं, लेकिन कोई केंद्र नहीं है. उधर भाइयों की सरपरस्ती में चलने वाले दोनों केंद्रों का हाल बेहाल है. स्थानीय लोग बताते हैं कि उक्त केंद्र कभी भी खुले हुए नहीं देखे गए. इन केंद्रों के बच्चों के हिस्से का राशन कब आता है और कहां चला जाता है, किसी को नहीं मालूम.

सुरनकोट के हाड़ी बुढ्डा गांव निवासी मोहम्मद इरशाद (50) बताते हैं कि उनके वार्ड नंबर एक में कोई भी केंद्र नहीं है, जिससे बच्चे फ़ायदा ले सकें. जब दूसरे मोहल्लों में केंद्र हैं, तो फिर यहां क्यों नहीं? लोगों ने संबंधित अधिकारी से बात की, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला. केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की संयुक्त सचिव प्रीती मदान ने बीते जनवरी माह में कहा था कि इस मामले की जांच कराई जाएगी, लेकिन तीन महीने बीत जाने के बावजूद कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है. एक रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारी इन केंद्रों के लिए आने वाला सरकारी राशन बेचकर अपनी जेब भर रहे हैं और बच्चों को घटिया राशन दिया जा रहा है. कहीं-कहीं तो वह भी नहीं. (चरखा) ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

नारी सुरक्षा समाज की ज़िम्मेदारी

भारतीय संस्कृति में नारी सर्वथा वंदनीय है, वह शक्तिस्वरूपा है. एक कन्या गांव की बेटी होती है, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के चलते समाज में भी बदलाव आया है. मूल्यों का ह्रास समाज के लिए ख़तरनाक है. महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि जब पूर्णिमा की अर्द्धरात्रि चांदनी की रोशनी में आभूषण पहने सोलह वर्षीय कन्या निर्भय होकर विचरण कर सके, तब मेरा सपना पूरा होगा. ऐसी मेरी रामराज्य की कल्पना है. उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि रामराज्य में चोर, लुटेरे या व्याभिचारी नहीं होंगे. अंतर सिर्फ़ इतना होगा कि तब अगर कोई अपराधी किसी युवती से छेड़छाड़, लूटपाट की चेष्टा करेगा भी, तो जागरूक समाज के कड़े प्रतिकार से उसके हौसले पस्त हो जाएंगे. अर्थात क़ानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला. हमें समाज को जागरूक करना होगा. जब हमारे मन में यह भाव पैदा होगा कि सामने लुटने वाली युवती मेरी बेटी-बहन है, तो कोई उसे क्षति कैसे पहुंचा सकेगा.

–राजेंद्र शुक्ल, *कानपुर, उत्तर प्रदेश.*

देश की गरिमा दांव पर

देश का गौरव लोकतंत्र है, जिसका केंद्र संसद भवन है. यदि लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसद अपनी बात मनमाने के लिए असभ्यता का परिचय दें, तो देश की गरिमा तार-तार होने लगती है. यहां सांसदों के वेतन-भत्तों में वृद्धि, मंत्रियों के आवास की साज-सज्जा जैसे मुद्दे पर तुरंत आम सहमति बन जाती है, लेकिन महिला आरक्षण, जन-लोकपाल, अपराधियों को सजा दिलाने, चीन-पाक द्वारा सीमाओं के उल्लंघन पर कार्रवाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर एकमत कायम नहीं हो पाता. इसके लिए आख़िर कौन ज़िम्मेदार है?

–चिंतनशील सच्चानंद चेलानी, *कटनी, मध्य प्रदेश.*

नई परंपराओं का उदय

31 मार्च-06 अप्रैल के अंक में प्रकाशित आलेख-कम होती बहस और प्रचार की परंपराएं पढ़ा, अच्छा लगा. पहले चुनाव के दौरान बहस होती थी, जो अब नहीं दिखाई देती. सारी बहस केवल एक-दो व्यक्तियों तक सीमित रह गई है. पहले दीवार लेखन के जरिये मतदाताओं को आकर्षित किया जाता था. समय के साथ चुनाव प्रचार के तौर-तरीकों में बदलाव आया और बहस न के बराबर रह गई.

–नवनीत सिंह, *औरंगाबाद, बिहार.*

अर्थव्यवस्था में सुधार की ज़रूरत

31 मार्च-06 अप्रैल का संपादकीय काफी विचारोत्तेजक है. सचमुच देश में एक बदलाव आते-आते भटक गया, रुक गया, समाप्त हो गया. यह सही है कि देश की अर्थव्यवस्था अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है. ऐसा ही रहा, तो भारत में आर्थिक मंदी आ सकती है, जिससे हमें बचना होगा.

–अंकित गुप्ता, *गोरखपुर, उत्तर प्रदेश.*

नौटंकी

नौटंकी चलती नहीं, अधिक दिनों तक मित्र.
फटा मुखौटा आप का, दिखने लगे चरित्र.
दिखने लगे चरित्र, आप के हर सूबों के.
दिखे साजिशी चित्र, आप के मंसूबों के.
जिसे देखिए चोर, भ्रष्ट, षड्यंत्री कहते.
फिर टपकाते लार, उसी धारा में बहते.

–पं रामखेलावन गर्ग, कटनी, मध्य प्रदेश.

सोचें, समझें, करें विचार

ढाई दशक से ज़्यादा समय गुजर जाने के बाद भी मेरे जैसा आम हिंदुस्तानी यह नहीं समझ सका कि पाकिस्तान एवं उसके द्वारा समर्थित आतंकवादी संगठन हमेशा ऐसे कार्य क्यों करते हैं, जिससे हिंदुस्तान के आम मुसलमानों की मुश्किलें बढ़ें, उन्हें शक की निगाह से देखा जाए. दोषी कम और निर्दोष ज्यादा, खासकर पढ़े-लिखे नवजवान पकड़े जाएं और ज़िल्लत की ज़िंदगी जीने को मजबूर हों. ताजा उदाहरण बिजनौर के 32 वर्षीय नासिर हुसैन का है, जिन्हें जून, 2007 को स्पेशल टास्क फोर्स ने ख़तरनाक आतंकवादी बताकर लखनऊ के एक होटल से गिरफ्तार दिखाया था.

हज़ारों सलाम, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के स्वामी शिवानंद को, जिन्होंने अदालत को बताया कि सुबह 5 से 7 बजे के बीच सादे लिबास में आए कुछ लोग उनके आश्रम में निर्माण कार्य में लगे नासिर को ज़बरदस्ती उठाकर ले गए थे. स्थानीय पुलिस ने इसकी रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया था. शिवानंद महाराज द्वारा 2013 में दिए गए इस बयान के आधार पर अदालत ने हाल में नासिर हुसैन को बाइज्जत बरी किया है. अजीब विडंबना है, जब कोई गिरफ्तार होता है, तो प्रमुखता से समाचार प्रकाशित-प्रसारित किए जाते हैं, उन्हें अपराधी और देशद्रोही मान लिया जाता है, लेकिन जब बाइज्जत रिहा होते हैं, तो उस समाचार को कोई प्रमुखता नहीं मिलती.

–सैयद शहनशाह हैदर आब्दी झांसी, *उत्तर प्रदेश.*

अन्ना का सच

31 मार्च-06 अप्रैल की कवर स्टोरी-अन्ना हजारे ने देश को धोखा दिया, काफी विचारोत्तेजक है. बिल्कुल सही है कि अन्ना ने पहले कहा कि वह ममता बनर्जी की पार्टी को समर्थन करेंगे, लेकिन रामलीला मैदान में आयोजित रैली के बाद उन्होंने अपने सुर बदल लिए और कहा कि ममता बनर्जी अच्छी हैं, लेकिन उनकी पार्टी का समर्थन नहीं करूंगा.

–सिद्धार्थ सिंह, *गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश.*

लोकतंत्र का त्योहार

देश में लोकसभा चुनाव की धूम मची हुई है. राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार के लिए नए-नए तरीके अपना रही हैं. चुनाव लोकतंत्र का त्योहार होता है, जिसमें सभी छोटी-बड़ी पार्टियां भाग लेती हैं. मेले या त्योहार में प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है और जो जीतता है, उसे ईनाम मिलता है. वैसे ही चुनाव में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के कामकाज के आधार पर जनता उन्हें अपना मत रूपी ईनाम देती है. वह अच्छा काम करने वाले को बागडोर सौंपती है और उम्मीदों पर खरे न उतरने वाले को बेदखल कर देती है.

–प्रिया सिंह, *शाहदरा, दिल्ली.*

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

अब जनता को फ़ैसला करना है

बात भारतीय जनता पार्टी की आज की स्थिति की करनी चाहिए, नरेंद्र मोदी की नहीं. आज हिंदुस्तान में 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं. इनमें से कुछ राज्यों के आज लोकसभा में कितने सांसद हैं, इस बारे में बात करते हैं. आंध्र प्रदेश से 42, केरल से 20, ओडिशा से 21, तमिलनाडु से 39, दिल्ली से 7 और जम्मू-कश्मीर से 6 लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं. इन सारे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी शून्य है. उसे एक भी सीट इन राज्यों में, मौजूदा लोकसभा में जो भंग हो चुकी है, नहीं मिल पाई. जबकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीतने और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की जी-जान से कोशिश की थी.

अब कुछ छोटे प्रदेशों के बारे में बात कर ली जाए. मणिपुर से दो, मेघालय से दो, मिजोरम से एक, त्रिपुरा से दो, लक्ष्यद्वीप से एक, अरुणाचल प्रदेश से दो, पुडुचेरी से एक, सिक्किम से एक, चंडीगढ़ से एक सीटें आती हैं और इन सभी छोटे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का कोई खाता ही नहीं है. यहां पर भी लोकसभा में उसके सदस्यों की संख्या शून्य है. 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 15 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला है. कुल मिलाकर इन 15 प्रदेशों में 148 सीटें है, जबकि लोकसभा की कुल सीटें 543 हैं. अगर इन 543 सीटों में से 148 सीटें घटा दें, तो बचे हुए 20 राज्यों में लोकसभा की 395 सीटें बचती हैं.

अगर पंद्रह राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी सीट नहीं है, तब आज भारतीय जनता पार्टी के पास जितनी सीटें हैं, वे बचे हुए बीस राज्यों में हैं. उनमें भी पश्चिमी बंगाल जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ़ एक सीट मिली और यहीं से इतिहास बदलेगा या नहीं बदलेगा, इसकी कहानी शुरू होती है. अगर भारतीय जनता पार्टी इन पंद्रह राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाती है और बचे हुए बीस राज्यों में अपने सीटों की संख्या बढ़ा पाती है, तभी भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में सरकार बनाना संभव हो पाएगा. पर एक फर्क है, मौजूदा लोकसभा जो भंग हो चुकी है, इसका चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा था और आने वाली लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं. क्या नरेंद्र मोदी की छवि भाजपा से बड़ी हो गई है? इस सवाल का जवाब पहली नज़र में देखें, तो इसमें सत्यता है.

नरेंद्र मोदी जैसा चाहते हैं, वैसा उनकी पार्टी कर रही है और इसीलिए किसी भी टेलीविजन चैनल में, चाहे वह खेल का चैनल हो, चाहे समाचारों का चैनल हो, चाहे फिल्म का चैनल हो, यानी हर एक में एक ही विज्ञापन आ रहा है, अबकी बार मोदी सरकार. नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा कद बनाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहमति है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नरेंद्र मोदी पर जानबूझ कर दांव नहीं लगाया है, मजबूरी में दांव लगाया है. मुंबई में जब भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन हो रहा था, तब नरेंद्र मोदी उस अधिवेशन में नहीं आ रहे थे. उनकी शर्त थी कि संजय जोशी को पार्टी से निकाला जाए या ज़िम्मेदारियों से मुक्त किया जाए. संघ इसे मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे हैं, तब उसने अचानक संजय जोशी को सभी पदों से इस्तीफ़ा देने के लिए कहा.

उस समय संजय जोशी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और अगर संजय जोशी नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ घूम जाते, तो नरेंद्र मोदी का गुजरात में तीसरी बार चुनकर आना संभव नहीं रह जाता. नरेंद्र मोदी ने यहीं से अपनी रणनीति बनाई और उन्होंने सबसे पहला काम ऐसे लोगों को पिंजरे में बंद करने का किया, जो उनके लिए भविष्य में कभी ख़तरा हो सकते थे. संजय जोशी उनमें से एक हैं. उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस तरह घेरा कि चाहे भैया जी जोशी हों या मोहन भागवत हों और चाहे भारतीय जनता पार्टी के भीतर रामलाल जी हों, ये सब नरेंद्र मोदी को 2014 के चुनाव के लिए अवश्यंभावी मानने लगे. यहां से मोहन भागवत ने शायद यह सोचा कि इसी हथियार से वह भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन नेताओं का राजनीतिक वध कर सकते हैं, जो उनसे उम्र में और अनुभव में बड़े हैं.

पूरी कोशिश लालकृष्ण आडवाणी को चुनाव के परिदृश्य से हटाने की हुई, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी ने स्वयं को इस पूरे परिदृश्य में अंगद की तरह खड़ा कर दिया और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यह सलाह नहीं मानी कि वह इस बार का चुनाव न लड़ें. ठीक यही काम मुरली मनोहर जोशी ने किया. हालांकि, अभी भारतीय जनता पार्टी के संघ से जुड़े लोग कहते हैं कि अगर मुरली मनोहर जोशी पहली ही मीटिंग में यह सलाह मान जाते, तो देश में यह संदेश नहीं जाता कि मुरली मनोहर जोशी संघ का फ़ैसला नहीं मान रहे हैं या आडवाणी जी संघ का फ़ैसला नहीं मान रहे हैं. जानबूझ कर आडवाणी जी ने भोपाल सीट पर अपने लड़ने की अफवाह को बढ़ने दिया. इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य नहीं है, बल्कि बहुत छोटा रहस्य है कि आडवाणी जी के शिष्य शिवराज सिंह एक तरफ़ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पर अगर कोई ऐसा भी वक्त आता है, जब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार रहते सरकार नहीं बन पाती है, उस स्थिति में राजनाथ सिंह की जगह शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया जा सके.

यही पर संघ ने सोच-समझ कर एक फ़ैसला लिया कि अगर यह चीज होती है, सीटें 160-180 या 200 आती हैं, लेकिन सरकार साफ़ तौर पर एनडीए की नहीं बन पाती है और उसमें रोड़ा नरेंद्र मोदी का नाम है, तब उन सारे लोगों की पार्टी में चलेगी, जिन्हें संघ हटाना चाहता है और इस फेहरिस्त में ज़्यादा नहीं, चार-पांच नाम हैं. आडवाणी जी हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, जसवंत सिंह को पार्टी से निकाल ही दिया गया है, यशवंत सिन्हा हैं. इनके जैसे लोग अपने को संघ से अलग भाजपा का मानने लगे हैं और आडवाणी जी तो स्वयं अपना कद इतना बड़ा मानते हैं कि संघ उन्हें निर्देश नहीं दे सकता. संघ अब चाहता है कि नरेंद्र मोदी को किसी भी क़ीमत पर नहीं हटने देना है और सरकार नहीं बनती है, तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठे और उन सारे लोगों को संन्यास लेने का निर्देश दिया जाए, जिनकी वजह से पार्टी इस हालत में पहुंची है.

संघ का यह फ़ैसला और भारतीय जनता पार्टी की आज की स्थिति कम से कम यह साबित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के सामने अब बौनी हो गई है. नरेंद्र मोदी इतिहास बदलने की दिशा में जा सकते हैं. अगर वह उन 15 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का पौधा रोप दें, जहां पर भाजपा के पास एक भी सीट नहीं है और उन 20 राज्यों में जहां भाजपा के पास एक से लेकर 20 तक सदस्य हैं, वहां भाजपा की सीटें बढ़ाएं. यही सोचकर नरेंद्र मोदी ने अपने प्रचार की व्यूह रचना 3 साल पहले रच ली थी, जिसकी शुरुआत उन्होंने मुंबई अधिवेशन के बाद कर दी. उन्होंने स्वयं को रहस्यमय भी रखा, उन्होंने स्वयं को आतंक का चेहरा भी बनाकर रखा, ताकि देश में यह संदेश जाए कि मुसलमानों को अगर कोई ठीक कर सकता है, तो मोदी कर सकते हैं. फिर नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का मुद्दा छोड़कर रामदेव के आश्रम से सर्वे भवंतु सुखिन: का नारा भी दिया, ताकि उन्हें भरमाया जा सके, जो नरेंद्र मोदी को आज भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं. और, आख़िर में नरेंद्र मोदी मुसलमानों को अपने पक्ष में लाने के लिए जी-जान से लग गए हैं. इसके लिए उन्होंने कई बड़ी दरगाहों के धार्मिक नेताओं को अपने पक्ष में तोड़ा. उन्होंने मुसलमानों के उन नेताओं को भी पक्ष में तोड़ा, जिनके जलसों में लाखों लोग आते हैं और जिनके कहने पर वोट नहीं मिलते. मुस्लिम पत्रकारों को उनके लोग यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार मुस्लिम नौजवान नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगे, क्योंकि वे उन बाकी नौजवानों से अलग नहीं हैं, जो देश में मोदी- मोदी चिल्ला रहे हैं.

अगर पंद्रह राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी सीट नहीं है, तब आज भारतीय जनता पार्टी के पास जितनी सीटें हैं, वे बचे हुए बीस राज्यों में हैं. उनमें भी पश्चिमी बंगाल जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ़ एक सीट मिली और यहीं से इतिहास बदलेगा या नहीं बदलेगा, इसकी कहानी शुरू होती है. अगर भारतीय जनता पार्टी इन पंद्रह राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाती है और बचे हुए बीस राज्यों में अपने सीटों की संख्या बढ़ा पाती है, तभी भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में सरकार बनाना संभव हो पाएगा.

मानना यह चाहिए कि चाहे मुसलमान हों या दूसरे कमजोर वर्गों के लोग, आज जो मोदी-मोदी का नारा लगा रहे हैं, कल उन्हें इतनी निराशा न मिले कि वे नरेंद्र मोदी के सामने गिद्ध बनकर खड़े हो जाएं और यहीं पर मोदी की कुशलता की परीक्षा होने वाली है कि क्या वह एम जे अकबर जैसे लोगों से कोई सलाह लेंगे या उन्होंने एम जे अकबर को भी शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी की तरह एक शो पीस की तरह पार्टी में शामिल किया है. सवाल देश का है. सवाल और भी बड़ा है कि क्या नरेंद्र मोदी के आने से यह देश और तनाव में जाएगा या नरेंद्र मोदी के आने से यह देश तनाव से उबरेगा?

नरेंद्र मोदी को सबसे ज़्यादा धन्यवाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए, जो यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि तीन सालों से नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए हुए प्रचार अभियान का मुकाबला किस तरह से करें. नरेंद्र मोदी भी कोई संभावना देश को नहीं दिखा पा रहे हैं और न राहुल गांधी दिखा पा रहे हैं, लेकिन इस स्थिति में भी नरेंद्र मोदी का कद बड़ा दिखाई दे रहा है और राहुल गांधी का कद छोटा. यह चुनाव कुछ फ़ैसले अवश्य करेगा. हालांकि हर चुनाव कुछ न कुछ फ़ैसले करता है, पर इस चुनाव में देश की जनता की भी परीक्षा है कि क्या वह अभी चुनाव के नाम पर सड़क पर चल रहे मदारी और बंदर के तमाशे को देखना चाहती है या सचमुच गंभीरता से उन सवालों के जवाब चाहती है, जो महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और सांप्रदायिकता के रूप में हमारे सामने खड़े हैं.

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र की ज़रूरत

फेसबुक पर एक चर्चित एकाउंट होना या ट्वीटर पर कोई चर्चित एकाउंट होना सीट की उम्मीदवारी का हक़ नहीं देता. कोई आश्चर्य नहीं है कि दिल्ली में आप कार्यकर्ता खुद को बहुत दुःखी महसूस कर रहे हैं. यहां तक कि एक बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बनने की संभावनाएं भी क्षीण हो रही हैं. यह सिर्फ़ अरविंद केजरीवाल की पार्टी और उन्हीं का वन मैन शो बनकर रह गई है. हालांकि, यह चुनाव नए भारत के लिए सिर्फ़ एक चुनाव भर हैं.

जब मैं लेबर पार्टी में शामिल हुआ था, तो उस समय मुझे यह समझाया गया था कि मैं किस तरह संसद पहुंच सकता हूं. इसका मतलब यह था कि मैं भावी उम्मीदवारों की सूची में किस तरह अपना नाम शामिल कर सकता था. उसके बाद यह देखना कि आसपास के संसदीय क्षेत्र में कौन सी सीट आगामी चुनाव में खाली है, जिससे संसदीय उम्मीदवार बना जा सके. आपको आवेदन करना होता था और अगर आपका नाम सौभाग्यशालियों में होता था, तो फिर आपको दूसरे प्रतिभागियों से प्रतियोगिता करनी होती थी. उम्मीदवार का चुनाव पचास या उससे अधिक प्रतिनिधि, जो उस संसदीय क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों से आए होते थे, करते थे. अगर आप जीत जाते थे, तो उसके बाद आप उम्मीदवार बनते थे, लेकिन इस जीत के बावजूद अगर अगली बार आपको खड़ा होना हो, तो फिर उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था.

यह बात मैंने इसलिए बताई, क्योंकि हाल में राहुल गांधी ने कुछ सीटों के लिए प्राथमिक प्रक्रियाओं की बात की थी, जहां पर कांग्रेस पार्टी अक्सर असफल हो जाती थी. भारत में पार्टी के भीतर लोकतंत्र जैसी चीज का कोई चलन नहीं रहा है. पार्टियों में सक्रिय सदस्यता का कोई प्रावधान नहीं है, जिससे चुनावों के दौरान भी सदस्य आपस में लगातार बैठकें करते रहें. सदस्य पार्टी की नीतियों पर चर्चा नहीं करते और न वे पार्टी की नीतियों पर फ़ैसले लेते हैं. सालाना बैठकों में कोई बहस या राजनीतिक मुद्दों पर बेहतर विकल्प को लेकर कोई बात नहीं होती. किसी मामले पर पार्टी के सदस्यों द्वारा वोटिंग का कोई प्रावधान नहीं है. भारत में हर पार्टी में बेहद केंद्रीयकृत संरचना है. उम्मीदवारों की घोषणा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा की जाती है. गांधी नगर या वाराणसी के भाजपा कार्यकर्ता इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि वे किसे अपनी संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाना चाहते हैं.

आख़िर ऐसा अंतिम बार कब हुआ था, जब अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने संसदीय उम्मीदवार के प्रदर्शन और हाजिरी पर चर्चा करने के लिए कोई बैठक की हो? आख़िर इस संसदीय क्षेत्र की पार्टी यूनिट के साथ कितनी बैठकों में राहुल गांधी सम्मिलित हुए? निश्चित रूप से यह राहुल गांधी की गलती नहीं है कि वह अपनी ही पार्टी का इतिहास नहीं जानते हैं. महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी बड़ी संख्या में लोगों की सदस्यता लेकर बनाई थी. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में शामिल होने के लिए ज़िला स्तर से भी प्रतिनिधि आते थे. कांग्रेस का वार्षिक अध्यक्ष एआईसीसी द्वारा ही चुना जाता था. हालांकि गांधी जी की भी उसमें अपनी पसंद होती थी. जैसा कि सुभाष चंद्र बोस के समय में हुआ था, लेकिन पार्टी की यह लोकतांत्रिक प्रतिनिधियों वाली संरचना चुनावों में प्रभावी नहीं होती थी.

1937 में जब पहली बार चर्चित चुनाव लड़े गए, उस समय सरदार पटेल संसदीय बोर्ड के चेयरमैन थे और उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से केंद्रीयकृत कर दिया गया था. बाकी जो थोड़ा-बहुत बचा हुआ था, उसे इंदिरा गांधी ने ख़त्म कर दिया था. इस समय भी सारी पार्टियां उसी तरह व्यवहार कर रही हैं. किसे कौन सी सीट मिलेगी, यह पार्टी का चुनावी बोर्ड तय करता है. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सीटों को लेकर बवाल करना त्रासदी से ज़्यादा एक मजाक लगता है. सबसे खराब तो तब लगता है, जब एक बड़ी पार्टी के नेता उस तरह से विरोधी हो जाते हैं, जैसा कि मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद करते हैं. सभी पार्टियों में भ्रष्टाचारी हैं, दूसरी पार्टियों के छोड़े हुए लोग भी हैं. ऐसे फिल्म स्टार भी हैं, जिनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है या फिर सेवानिवृत्त नौकरशाह और सेना के अधिकारी भी हैं.

यह बात मायने नहीं रखती कि ये उम्रदराज नेता किस पार्टी में जाएंगे. पार्टियों के पास कोई सक्रिय राजनीतिक सदस्यता नहीं है, केवल पद की चाहत रखने वालों की भरमार है. इसलिए आख़िरी समय के नाटकों के बावजूद कोई भी इन सब मामलों पर उंगली नहीं उठाने जा रहा है. ऐसा ही अगली बार चुनाव में भी होगा. इस मामले में आम आदमी पार्टी तो वास्तविक रूप से बहुत दु:खी करने वाली पार्टी है. ऐसा कहा जाता है कि यह पार्टी सत्ता के विकेंद्रीकरण और लोगों को ताकत देने में भरोसा रखती है. दिल्ली के हर मोहल्ले का अपना मेनिफेस्टो था, इसके लिए सलाह भी ली गई थी, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी बनने की जल्दबाजी में मूलभूत सिद्धांतों को भुला दिया गया. यह बिल्कुल वैसा है, जैसा अन्य पार्टियां उम्मीदवारों के चयन में करती हैं. आम आदमी पार्टी ने संसदीय क्षेत्रों की यूनिटों के अपने कार्यकर्ताओं से कोई सलाह नहीं ली, जबकि वे पार्टी की नीतियों की चर्चाएं भी करते हैं. उम्मीदवारों का चयन पार्टी के सदस्यों के मुताबिक नहीं हुआ.

फेसबुक पर एक चर्चित एकाउंट होना या ट्वीटर पर कोई चर्चित एकाउंट होना सीट की उम्मीदवारी का हक़ नहीं देता. कोई आश्चर्य नहीं है कि दिल्ली में आप कार्यकर्ता खुद को बहुत दु:खी महसूस कर रहे हैं. यहां तक कि एक बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बनने की संभावनाएं भी क्षीण हो रही हैं. यह सिर्फ़ अरविंद केजरीवाल की पार्टी और उन्हीं का वन मैन शो बनकर रह गई है. हालांकि, यह चुनाव नए भारत के लिए सिर्फ़ एक चुनाव भर हैं. मतदाता का तंत्र से मोहभंग हो गया है. संभव है कि मतदाता चुनाव में किसी स्थानीय चेहरे को ज़्यादा पसंद करें, बजाय किसी बाहरी नेता के. शायद लोकतंत्र भारत में अब आए. चलिए, इस बात की आशा करते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

> गुजरात के मुसलमानों को दंडित करने के मोदी छाप फासीवादी हथकंडे आज पूरे देश को न बताए जा रहे हैं, न दिखाए. हाल में बीबीसी के मधुकर उपाध्याय ने गुजरात के कथित विकास की तस्वीर विस्तार से बताई. उन्होंने मुस्लिम बस्तियों में जाकर उनका मन टटोलने की कोशिश की, लेकिन भय इस कदर व्याप्त है कि उन्हें सफलता नहीं मिली. जब वह एक मदरसे में पहुंचे, तो उन्हें धकिया कर बाहर कर दिया गया. मधुकर का तजुर्बा मेरे उपरोक्त आकलन का जीता–जागता सुबूत है.

> सवा अरब से अधिक और दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश जब अपने अगले पांच वर्षीय राजकाज का निर्णय लेने वाला हो, उसकी पूर्व संध्या पर देश की राजनीतिक आबो-हवा ज्वलंत समस्याओं पर केंद्रित न होकर व्यक्ति आधारित हो, तब पाठक अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का भविष्य कैसा होगा? देश की तमाम बुनियादी समस्याओं यथा पानी, बिजली, सड़क, परिवहन, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान-तकनीक एवं रोज़गार के मसले जहां एक तरफ मुंह चिढ़ाते हैं, वही देश के लगातार बिगड़ते सामाजिक परिवेश पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है.

भारतीय मुसलमान और 2014 का आम चुनाव

शमशाद इलाही शम्स

भारत की 16वीं लोकसभा का चुनाव कथित भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है. गत दस वर्षों की कांग्रेस हुकूमत के दौरान जनता के धन एवं संपदा की गई लूट के रूप में मनमोहन–सोनिया गांधी का नेतृत्व अपने भ्रष्ट आचरण के चलते जो नजीरें दे गया है, उसका हिसाब–किताब करना असाध्य कार्य है. 2012 के अंत में क़रीब आधा दर्जन राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव हुए, जिनमें गुजरात में भाजपा लगातार चौथी बार जीतकर आई, तभी से भारत के शासक वर्ग ने गुजरात के कथित विकास मॉडल को देश भर में प्रचारित कर उसके नाम पर केंद्र की हुकूमत बनाने का मंसूबा बना लिया था. समय गुजरा और पिछले वर्ष भारत के प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने मोदी को अपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया.

मीडिया और देशी–विदेशी औद्योगिक घरानों ने इस चुनाव में जिस पेशेवर सक्रियता का नमूना देशवासियों के सामने रखा, वह अपने आप में अनूठा है. यह सक्रियता उनकी बेचैनी का सुबूत है. प्रचार माध्यमों द्वारा ऐसा भ्रामक प्रचार भारत के इतिहास में अपना पहला अनुभव है. ऐसा लग रहा है कि देश में लोकसभा नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री पद के लिए सीधा चुनाव हो रहा है. पूरे चुनाव में राजनीतिक दलों के किसी घोषणापत्र, आर्थिक नीति, विदेश नीति, सामाजिक कार्यक्रमों आदि पर चर्चा किए बगैर सिर्फ़ मोदी, राहुल अथवा केजरीवाल जैसे राजनीतिक चरित्रों पर फोकस किया जा रहा है. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गत दस वर्षों के कांग्रेसी शासन में की गई कारगुजारियों के चलते भाजपा को लगभग वाकओवर दे चुके हैं. ऐसे पस्त हालात में मीडिया को केजरीवाल जैसा फिलर मिल गया है, जिसका दोहन वह मोदी समर्थित जनविरोधी ताकतों के पक्ष में दिन–रात कर रहा है. मोदी को डिजाइनर पारंपरिक लिबास में पगड़ी थमाकर, तो कभी तलवार के साथ मंच पर किसी ऐसे नायक की तरह पेश किया जाता है, जैसे वह कोई राजनीतिज्ञ नहीं, बल्कि फ़िल्मी हस्ती हों, जो अपनी किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए देश भर की गलियां–कूचे नाप रही हो. मोदी के मंच पर आते ही सीटियां बजती हैं, जिससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का कौन सा प्रबुद्ध समाज उनकी राजनीतिक विचारधारा का बोझ उठा रहा है.

सवा अरब से अधिक और दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश जब अपने अगले पांच वर्षीय राजकाज का निर्णय लेने वाला हो, उसकी पूर्व संध्या पर देश की राजनीतिक आबो–हवा ज्वलंत समस्याओं पर केंद्रित न होकर व्यक्ति आधारित हो, तब पाठक अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का भविष्य कैसा होगा? देश की तमाम बुनियादी समस्याओं यथा पानी, बिजली, सड़क, परिवहन, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान–तकनीक एवं रोज़गार के मसले जहां एक तरफ मुंह चिढ़ाते हैं, वही देश के लगातार बिगड़ते सामाजिक परिवेश पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है. देश में बढ़ते सांप्रदायिक दंगे, खापों का बढ़ता प्रभाव, ऑनर किलिंग, सत्ता में अकलियतों, पिछड़ों एवं दलित तबकों की भागीदारी पर न कोई विचार है, न कोई नीति, न दिशा. भारत के शासक वर्ग द्वारा इन तमाम समस्याओं से जनता का ध्यान हटाकर मोदी जैसे गुब्बारे को इतना फुला देना ही उनके हित में है, जिसकी ओट में वह देश के संसाधनों पर अपने विदेशी आकाओं के साथ मिलकर अपनी लूट अनवरत रूप से न केवल जारी रखे, बल्कि उसे स्थायी अमलीजामा पहना सके. यह भारत का पहला ऐसा चुनाव है, जिसके एजेंडे से 20 करोड़ मुसलमान और 20 करोड़ दलित आबादी के जलते सवाल सिरे से गायब हैं. गुजरात के कथित विकास मॉडल पर मीडिया और कॉरपोरेट ताकतों ने जिस तरह तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर पेश किया है, वह निस्संदेह अकल्पनीय है. विकास मॉडल को देश भर में बेचने के साथ–साथ राजनीतिक दुष्प्रचार की सभी सीमाएं लांघ दी गई हैं. छह करोड़ की आबादी वाले गुजरात में लगभग 10 प्रतिशत आबादी मुसलमानों की है. मोदी की फासीवादी प्रचारक संस्थाएं एक ऐसे झूठ को देश भर में फैला रही हैं कि गुजरात का मुसलमान 2002 के जनसंहार को भूलकर मोदी के पीछे खड़ा है और उसे वोट देता है. भाजपा का मुसलमानों के प्रति क्या राजनीतिक दृष्टिकोण है, यह जगजाहिर है. लेकिन, यहां इस बात को ग़ौर से देखना चाहिए कि बतौर प्रतिपक्ष एक केंद्रीय दल अथवा कई सूबों में सत्ता संभाले दल का रवैया देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति कैसा है?

गुजरात विधानसभा में 182 सीटें हैं, जिनका 10 प्रतिशत यानी 18 सीटें मुसलमानों की होनी चाहिए. गुजरात भाजपा ने 2012 के विधानसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा. 2007 की विधानसभा में कुल पांच मुस्लिम विधायक थे, जो 2012 में घटकर मात्र दो रह गए. गुजरात भाजपा मुसलमानों को मात्र वार्ड प्रत्याशी बनाती है. जामनगर ज़िले के सलाया नगर (33 हज़ार आबादी, 90 फ़ीसद मुसलमान) में भाजपा ने 27 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे, जिनमें 24 जीते. ये सभी मुस्लिम बाहुल्य आबादी से थे. इसके अतिरिक्त भुज और अंजार जैसे नगरों में भाजपा के कुछ मुस्लिम पार्षद हैं, जिनमें से एक रियल स्टेट का बड़ा कारोबारी है. मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में 500 प्रत्याशियों में भाजपा ने मुसलमानों को कुल छह टिकट दिए, जिनमें क़रीब 50 मुस्लिम बाहुल्य आबादी के चुनाव क्षेत्र शामिल हैं. इसमें मात्र एक सदस्य आरिफ अकील भोपाल से चुने गए. चुनाव पूर्व इन राज्यों में मुस्लिम विधायकों की संख्या 17 थी. राजस्थान में 8.5 फ़ीसद आबादी मुसलमानों की है, जहां भाजपा ने 200 सीटों वाले सदन में से कुल 4 टिकट दिए, जिनमें मात्र 2 विधायक चुने गए, जबकि यह संख्या उनकी आबादी के अनुसार 17 होनी चाहिए थी. दिल्ली में मुसलमानों की आबादी 12 फ़ीसद है. 70 सदस्यों वाले सदन में भाजपा ने सिर्फ़ एक मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया, जबकि यह संख्या 8 होनी चाहिए थी.

उक्त आंकड़ों से मुसलमानों और राजनीतिक नेतृत्व में उनकी हिस्सेदारी के सवाल को लेकर भाजपा की समझ साफ़ हो जाती है. अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र के सिद्धांतों में मुसलमानों की क्या स्थिति होगी, यह अंदाजा स्वत: ही लगाया जा सकता है. मरहूम सिकंदर बख्त, मुख्तार अब्बास, शाहनवाज हुसैन, नजमा हेपतुल्लाह, आरिफ मोहम्मद खान और हाल में शामिल हुए एम जे अकबर जैसे चेहरे दिखाने वाले मुसलमानों को प्रचार माध्यमों में रखकर देश का सबसे प्रमुख राजनीतिक दल अपनी मंशा साफ़ कर चुका है. चंद दिखावटी चेहरों का प्रदर्शन करके भाजपा–संघ परिवार भारत के बीस करोड़ मुसलमानों को किसी विधायिका में बैठने का हक़ छीन लेना चाहता है, उन्हें उन इदारों में मुसलमानों को बैठाने की कतई ज़रूरत महसूस नहीं होती, जहां वे नीति निर्धारण करें अथवा अपने भविष्य के लिए किसी नीति–योजना पर क़ानून बना सकें.

संघ परिवार का दूसरा सबसे बड़ा झूठ यह है कि गुजरात का मुसलमान उन्हें (भाजपा–मोदी) वोट देता है. यह एक तथ्य है और तथ्य सच नहीं होते. सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता प्रतीत होता है और हमें रात–दिन की अनुभूति होती है, सदियों तक इसी आंखों देखी बात पर मानव जाति ने यकीन किया, लेकिन वस्तुत: पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है, यह वैज्ञानिक सत्य है. गुजरात के मुसलमानों के वोट मोदी को पड़ना कोई ऐसा जटिल प्रश्न नहीं है, जिसे समझा न जा सके. बोहरा एवं खोजा दोनों मुस्लिम व्यापारी तबके हैं और व्यापारियों के अपने निहित स्वार्थ उन्हें सत्ता के इर्द–गिर्द रहने को मजबूर करते हैं. यह समुदाय आर्थिक दृष्टि से ऐतिहासिक रूप से संपन्न रहा है. इन्हीं बोहरा टोपियों को दिखाकर देश भर के मुसलमानों को यह संदेश दिया जा रहा है कि मोदी को मुस्लिम समर्थन प्राप्त है. यह एक प्रायोजित सत्य है. बोहरा देश में मुसलमानों का एक प्रतिशत भी नहीं हैं. दूसरा कारण भय की राजनीति है, जिसे न तो देश का मीडिया बताता है और न कांग्रेस जैसी राजनीतिक ताकतें.

जर्मन के फासीवादी तानाशाह हिटलर और इटली के मुसोलिनी संघ की प्रेरणा के प्रमुख स्रोत हैं. हिटलर द्वारा जर्मन के यहूदी समुदाय का दमन किसी से छिपा नहीं है, लेकिन उसके प्रचार तंत्र, जिसका मुखिया गोयबल्स था, उसने भी प्रचार किया था कि हिटलर को यहूदी समुदाय का समर्थन प्राप्त है. 1933 में मात्र 33 फ़ीसद वोट हासिल करके संसद में आए हिटलर को जर्मन राष्ट्रपति पॉल वान हिंडेन्बार्ग ने सरकार का मुखिया बनाया था, 87 वर्ष की उम्र में 2 अगस्त, 1934 को राष्ट्रपति की मृत्यु होने के तुरंत बाद हिटलर ने अध्यादेश पारित कर खुद को जर्मन का चांसलर घोषित कर दिया, जिसके तहत सभी संवैधानिक ताकत उसके पास आ गई. इस अध्यादेश का जनता से अनुमोदन लेने के लिए 19 अगस्त, 1934 को जर्मनी के 3.8 करोड़ मतदाताओं से एक जनमत संग्रह कराया गया था. अभी तक हिटलर की सत्ता को मात्र 19 माह हुए थे, उसके नाजी कार्यक्रम के चलते देश में जनतंत्र को कुचल कर सभी विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था या उनकी हत्याएं कर दी गई थीं. 19 अगस्त, 1934 के न्यूयार्क टाइम्स में इस जनमत संग्रह की रिपोर्ट की छपी ख़बर आज बड़ी प्रासंगिक है. जनमत संग्रह में 90 फ़ीसद मतदाताओं ने हिटलर को हां में जवाब दिया था. इसी मतदान में यहूदियों और कम्युनिस्ट समर्थकों ने भी हिटलर के पक्ष में मतदान किया था. यह भी एक तथ्य है, लेकिन सच से दूर.

उदाहरण के लिए जर्मनी के एक ज़िले में यहूदी इलाके से 168 वोट हां और 92 न में पड़े, 46 रद्द हुए. दूसरे ज़िले के एक यहूदी वृद्ध आश्रम से 94 वोट हां और 4 न में पड़े, 3 रद्द हुए. दचाऊ स्थित यातना शिविर में 1554 वोट हां और 8 न में पड़े और 10 रद्द हुए. जाहिर है, इनमें अधिकतर यहूदी समुदाय से थे. ठीक इसी प्रकार पश्चिमी बर्लिन, जो मजबूत कम्युनिस्ट प्रभाव क्षेत्र था, वहां क्रमश: 840 वोट हां और 237 न में पड़े. दूसरे कम्युनिस्ट गढ़ वेडिंग ज़िले में 949 वोट हां और 237 वोट न में पड़े. ध्यान रहे, उस वक्त कम्युनिस्ट नेता अर्नेस्ट थेलमान को हिटलर ने जेल में डाल रखा था. पूरे जर्मनी के शहरों में नाजियों ने बिल बोर्ड लगाए थे, जिनकी इबारत कुछ यूं थी, जर्मनी के पुनर्जन्म के लिए हिटलर अब तक हवाई जहाज, रेल, मोटरकार, पैदल 15 लाख किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका है. तुम घर से 100 मीटर चलो और उसे हां का वोट दो. मतदान 19 अगस्त की सुबह आठ बजे से शुरू होना था, लेकिन हिटलर के नाजी दस्ते, जिसमें हिटलर यूथ ट्रूप्स, नाजी लेबर यूनियन और अन्य संगठनों के कार्यकर्ता थे, सुबह 6 बजे सड़कों पर सक्रिय हो चुके थे और जनता को मतदान में जाने के लिए उकसा रहे थे. मतदान केंद्रों पर हिटलर की पुलिस, फ़ौज और गेस्टापो के दस्तों की गहरी नज़र प्रत्येक मतदाता को देख रही थी और दबाव बना रही थी कि जनता को क्या वोट करना है. इन परिस्थितियों की पड़ताल किए बिना कोई मतदान के मनोविज्ञान को कैसे अनदेखा कर सकता है? लेकिन यह सच है कि हिटलर उस जनमत संग्रह में 90 फ़ीसद वोट पाकर जनता द्वारा अनुमोदित हुआ था.

उक्त घटना के अध्ययन के बाद गुजरात में भाजपा–मोदी को पड़े मुस्लिम वोटों का मूल्यांकन करना ज़रूरी है. भारत में वोटों की गिनती के दौरान यह सब जानकारी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को होती है कि किस वार्ड में कितने मुस्लिम मतदाता हैं और चुनाव जीतने अथवा हारने वाले दल को किस जनसमूह से कितने वोट मिले. 2002 का जनसंहार भुगत चुकी मुस्लिम अवाम के इस भयग्रस्त मनोविज्ञान के चलते यदि कोई गुजरात के मुसलमानों को भाजपा का मतदाता बता रहा है, तो वह हिटलर–गोयबल्स के ही वक्तव्य को दोहरा रहा है, जब 1934 में उन्होंने प्रचार किया कि उनकी सरकार को यहूदियों का समर्थन प्राप्त है. भाजपा विरोधी वोट करके गुजरात का मुसलमान क्या फिर कोई नई आफत मोल लेगा? क्या यह वही जगह नहीं, जहां दंगों के बाद केंद्र सरकार की राहत राशि भी वितरित नहीं हुई? आज अहमदाबाद के बाम्बे होटल एरिया में दंगा पीड़ितों को खत्तों पर बसाने वाली मोदी सरकार से उन्हें किसी रहम की उम्मीद हो सकती है, जहां न बिजली है, न पानी, न चिकित्सा सुविधा और न शिक्षा. गुजरात के मुसलमानों को दंडित करने के मोदी छाप फासीवादी हथकंडे आज पूरे देश को न बताए जा रहे हैं, न दिखाए. हाल में बीबीसी के मधुकर उपाध्याय ने गुजरात के कथित विकास की तस्वीर विस्तार से बताई. उन्होंने मुस्लिम बस्तियों में जाकर उनका मन टटोलने की कोशिश की, लेकिन भय इस कदर व्याप्त है कि उन्हें सफलता नहीं मिली. जब वह एक मदरसे में पहुंचे, तो उन्हें धकिया कर बाहर कर दिया गया. मधुकर का तजुर्बा मेरे उपरोक्त आकलन का जीता–जागता सुबूत है.

सूचना क्रांति के इस दौर में गुजरात के मुसलमानों का दर्द पूरा देश देख रहा है. संघ–भाजपा की यह राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि गुजरात के प्रयोग को पूरे देश में लागू किया जाए, जिसके लिए उन्होंने विकास का नाम लेकर मोदी को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 20 करोड़ की मुस्लिम आबादी इस जहर को आराम से निगल जाएगी. इतिहास गवाह है कि एक कट्टरपंथ दूसरे रंग के कट्टरपंथ को खाद–पानी देता है. यह ज़रूरी नहीं कि मुसलमान पूरे देश में किसी योजनाबद्ध तरीके से इस राजनीतिक चुनौती का जवाब देगा, लेकिन मोदी–तोगड़िया की वाणी औवेसी जैसी प्रतिध्वनि पैदा कर ही सकती है. हाल में राजस्थान में छह मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारी इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर की गई. पुलिस ने खुलासा किया कि वे मोदी पर हमला करने वाले थे. मुझे उनकी झूठी–सच्ची दलीलों पर यकीन नहीं होता, लेकिन मेरे लिए फ़िक्र इस बात की है कि उनमें से तीन युवक इंजीनियरिंग के छात्र हैं. वर्तमान स्थिति में अगर पढ़े–लिखे मुसलमानों ने धैर्य खोकर हथियार और आतंक का रास्ता अपना लिया, तो उसका ज़िम्मेदार भारत का राजनीतिक वातावरण होगा, जिसके दृश्य पटल पर आज मोदी का चेहरा लटका हुआ है.■

feedback@chauthiduniya.com

जिसे छुएंगे, सोना बना देंगे

इस सूची में शामिल किए गए निवेशकों ने इतना सोच समझकर निवेश किया कि साधारण सी दिखने वाल कंपनियां भी मुनाफा कमाने लगीं. जब यह कंपनियां मुनाफे का सौदा हो गईं तो इन निवेशकों ने अपने हिस्से के शेयरों को बेचकर 95 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया. इसे अप्रत्याशित सफलता ही कहेंगे. क्योंकि बीते पांच सालों के दौरान अमेरिका अर्थव्यवस्था के हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं. इस लिस्ट में पहले नंबर पर जिम गोयज रहे. गोयज सिकोइया कैपिटल के भागीदार हैं. और वाट्सअप के एकमात्र संस्थागत निवेशक थे. वहीं भारतियों में पहला स्थान अनिल भुसरी का है.

गौरव गर्ग

नीरज अग्रवाल

सलिल देशपांडे

समीर गांधी

वेंकी गणेशन

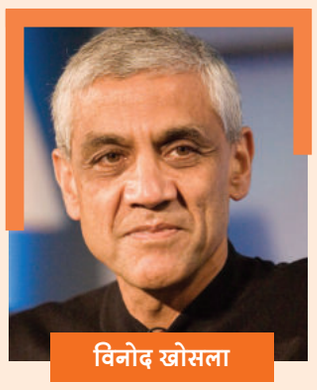
विनोद खोसला

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

यूनानी दंतकथाओं में मिडास नाम के एक ऐसे राजा का जिक्र किया गया है जो जिस किसी वस्तु को छू देता था वह सोना हो जाती थी. इसी राजा के नाम से मिडास टच नामक मुहावरा भी मौजूद है. हालांकि इस राजा की कहानी तो काफी पुरानी है लेकिन हाल ही अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स अपनी मिडास लिस्ट जारी की है जिसमें 11 भारतीय अमेरिकियों के नाम शामिल हैं. पत्रिका के मुताबिक ये भारतीय अमेरिकी जिस चीज को हाथ लगाते हैं उसे सोना बना देते हैं यानि की जिस भी किसी कंपनी या संस्था में धन लगाते हैं, वह मुनाफे का सौदा साबित होने लगती हैं. इस सूची में शामिल किए गए निवेशकों ने इतना सोच समझकर निवेश किया कि साधारण सी दिखने वाली कंपनियां भी मुनाफा कमाने लगीं. जब यह कंपनियां मुनाफे का सौदा हो गईं तो इन निवेशकों ने अपने हिस्से के शेयरों को बेचकर 95 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया. इसे अप्रत्याशित सफलता ही कहेंगे. क्योंकि बीते पांच सालों के दौरान अमेरिका अर्थव्यवस्था के हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं. इस लिस्ट में पहले नंबर पर जिम गोयज रहे. गोयज सिकोइया कैपिटल के भागीदार हैं. और वाट्सअप के एकमात्र संस्थागत निवेशक थे. वहीं भारतियों में पहला स्थान अनिल भुसरी का है. भुसरी इस सूची में 17वें स्थान पर हैं. उन्होंने 1.3 अरब डॉलर की कमाई की.

इसके बाद जिस भारतीय का नंबर आता है उनका नाम है देवेन पारेख. उन्होंने ट्विटर और टंबलर में निवेश कर भारी मुनाफा कमाया. वहीं तीसरे स्थान पर प्रमोद हक काबिज हुए. इस अंक में हम इन भारतीयों के जीवन की यात्रा के बारे में पड़ताल करेंगे कि आखिर क्यों दुनिया की सबसे बेहतरीन पत्रिकाओं में शुमार फोर्ब्स ने उन्हें मिडास लिस्ट में शामिल किया. आइए हम इस सूची में से कुछ टॉप रैंकिंग पाने वाले भारतीयों के बारे में जाने और समझे कि आखिर उनकी कार्यप्रणाली में ऐसा क्या है कि उन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया.■

अनिल भुसरी(17वीं पोजीशन)

वर्कडे के सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल भुसरी इस मिडास लिस्ट में टॉप पर हैं. स्टैनफोर्ड मैनेजमेंट स्कूल से ग्रेजुएट भुसरी ने 1.3 अरब डॉलर की कमाई की है. भुसरी वर्कडे की शुरुआत ने डेव डफिल्ड के साथ की थी. डेव उससे पहले पीपुल सॉफ्ट के सीईओ थे.

वर्कडे की शुरुआत करने से पहले अनिल भी पीपुल सॉफ्ट कंपनी में वाइस चेयरमैन के पद पर भी काम कर चुके हैं. उन्होंने साल 1999 में ग्रेलुक कंपनी ज्वाइन की थी. उन्हें साल 2007 में बड़ा मुनाफा उस समय हुआ था जब स्टोरेज सॉफ्टवेयर आउटफिट को एचपी ने 200 मिलियन डॉलर में खरीदा था. उसी समय में सॉफ्टवेयर वेंडर आउटलुक सॉफ्ट को एसएपी ने खरीद लिया था. उन्होंने उसके बाद बैकअप डिवाइस मेकर डाटा डोमेन पब्लिक के अधिकार खरीद लिए थे. ऐसा उन्होंने इस कंपनी को इएमसी द्वारा खरीदे जाने से पहले ही कर लिया था. डाटा डोमेन पब्लिक को साल 2009 में 2.4 बिलियन डॉलर में इएमसी ने खरीद लिया था. भुसरी के हालिया निवेशों में क्लाउडेरा, प्योर स्टोरेज, ड्रोबो(ऑटोमेटेड डाटा स्टोरेज), ओक्टा (आइडेंटिटी मैनेजमेंट), टाइडमार्क(क्लाउड बेस्ड एनालिटिक्स) और सर्विस नाउ(क्लाउड बेस्ड आईटी मैनेजमेंट) शामिल हैं. उनके बारे एक अमेरिकी उद्यमी का कहना है कि भुसरी के पास व्यवसाय के लिए सबसे बेहतर उद्यम अनुभव मौजूद है. वे बाजार की नब्ज को समझते हैं और उसी के अुनसार फर्मों में निवेश करते हैं. उनकी इस समझदारी की दाद देनी होगी कि वे किस तरह यह जान पाने में कामयाब होते है कि फला कंपनी का भविष्य में बाजार भाव बढ़ने वाला है. भुसरी की यही समझ उन्हें अमेरिका में क्या पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट वेंचरों में शामिल कराने की काबिलियत रखती है. अपने रोजगार के अलावा भुसरी खेलों में भी खासी दिलचस्पी रखते हैं. मेसाच्युसेट्स की बेस बॉल टीम बोस्टन रेड सॉक्स के वे काफी बड़े प्रशंसक हैं. अपने काम के दौरान भी वे इस टीम के मैचों को देखना पसंद करते हैं और यदि वे मैच नहीं देख पाते तो इसके स्कोर के बारे में जानकारी लेते रहते हैं. खेल के लिए ऐसा प्रेम भारतीय पाठकों के लिए समझना आसान है क्योंकि इस देश में क्रिकेट के प्रति दीवानगी तो जगजाहिर है. सिर्फ शहर ही नहीं गांवों तक में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो यदि मैच नहीं देख पा रहे हैं तो कमेंट्री ही सुन रहे हैं. यदि ऐसा कर पाना भी संभव नहीं है तो वे किसी दूसरे से ही इसके बारे में जानकारी लेते रहते हैं.■

देवेन पारेख (22वीं पोजीशन)

इस बार की सूची में जिन नए लोगों को शामिल किया गया है उनमें भारतीय अमेरिकी देवेन पारेख का नाम प्रमुख है. देवेन वार्टन स्कूल के ग्रेजुएट हैं. वह इनसाइट वेंचर पार्टनर्स के प्रबंध निदेशक हैं. उन्होंने ट्विटर और टंबलर में समझदारी भरा निवेश किया है. देवेन इस कंपनी के प्रबंध निदेशक के तौर पर जनवरी 2004 से काम कर रहे हैं. उन्होंने इस कंपनी को जनवरी 2000 में ज्वाइन किया था. यह कंपनी ज्वाइन करने से पहले साल 1992 से लेकर 2000 तक बेरेन्सन मिनेला एंड कंपनी में आठ सालों तक अपनी सेवाएं दी थीं. यह कंपनी न्यूयॉर्क स्थित एक मर्चेंट बैंकिंग फर्म थी. साल 1992 में देवेन द ब्लैक स्टोन ग्रुप के साथ काम कर रहे थे. वर्तमान समय में वे कई कंपनियों के निदेशक के तौर पर काम कर रहे हैं जिनमें चेग डॉट कॉम, हेनिडिल, न्यूएग डॉट जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं.

देवेन के बारे में यह मशहूर है कि वे जहां पैसा लगाते हैं वहां मुनाफा होना तय होता है. उन्हें वेंचर इनवेस्टमेंट के क्षेत्र काफी ज्यादा अनुभव है. सिर्फ इतना ही नहीं तकनीक, कॉरपोरेट गवर्नेंस और कैपिटल मार्केट की भी उन्हें बहुत अच्छी जानकारी है. जुलाई 2011 में उन्होंने मर्जर के मामले को लेकर कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था इसके बावजूद भी कंपनी के किसी भी अन्य डायरेक्टर को उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी. यह उनके बेहतरीन काम करने की मिसाल ही है क्योंकि ऐसा कम देखा जाता है कि अगर कोई अधिकारी अपनी किसी बात को लेकर त्यागपत्र दे दे और उसके साथी किसी भी डायरेक्टर को इसे लेकर कोई परेशानी न हो. ■

प्रमोद हक (27 वीं पोजीशन)

प्रमोद नार्वेस्ट वेंचर पार्टनर्स में सीनियर मैनेजिंग पार्टनर है. साइबर सिक्योरिटी कंपनी फायर आई उनका सबसे अच्छा निवेश माना जाता है. इससे पहले प्रमोद इसी कंपनी में मैनेजिंग पार्टनर के तौर पर 1990 से काम कर रहे थे. वर्तमान समय में कई कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों में शामिल हैं. इन कंपनियों में फायर आई, विरटेला टेक्नोलॉजी सर्विसेज इनकॉरपोरेट एंड हेल्थ केटेलिस्ट, एलएलसी जैसी कंपनियां शामिल हैं. इससे पहले वे परसिसटेंट सिस्टम लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डारेक्टरों में भी नवंबर 2005 से नवंबर 2010 तक रह चुके हैं. इसके अलावा वे वेराज नेटवर्क के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों में शामिल थे. यह एक ऐसी कंपनी है जो कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाती है. प्रमोद ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग में बीएस किया हुआ है. इसके बाद उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न स्कूल से एमबी किया और बाद में नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी पूरी की.प्रमोद को अपने हंसमुख स्वभाव के लिए जाना जाता है. वे जिस भी कंपनी में काम करते हैं वहां अपने सहयोगियों के साथ बेहतर ताल मेल के लिए उनकी दाद दी जाती है. सिर्फ इतना ही नहीं एक बेहतर वेंचर इन्वेस्टर होने के साथ साथ प्रमोद एक बेहतर इंसान भी हैं. ■

तकनीक के क्षेत्र में ज्यादा निवेशक

इस साल की मिडास लिस्ट में सबसे ज्यादा बेहतरीन निवेशक तकनीक के क्षेत्र हैं. इस लिस्ट में 20 नए चेहरे शामिल किए गए हैं और सात निवेशक इस लिस्ट में फिर से शामिल हुए हैं. टॉप टेन लिस्ट में फेसबुक और ट्विटर में निवेश करने वाले निवेशक भी शामिल किए गए हैं. इस लिस्ट में नेटवर्किंग वेबसाइट के सह संस्थापक रेड हॉफमेन सातवें स्थान पर काबिज हैं. पूरी लिस्ट में कई अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी शाामिल किया गया है लेकिन इनमें तकनीक के क्षेत्र में निवेश करने वालों की सिर्फ संख्या ही अधिक नहीं है बल्कि इनके मुनाफे का प्रतिशत भी ज्यादा है. तकनीक के क्षेत्र में निवेश करने वालों ने अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ऐसी फर्मो में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया और ऐसी फर्मों से उन्होंने ज्यादा मुनाफा भी कमाया.

इस सूची में कई अन्य भारतीयों को भी जगह दी गई है जिनमें नीजर अग्रवाल(37वीं पोजीशन), समीर गांधी (41वीं पोजीशन), अशीम चांदना (55वीं पोजीशन), वेंकी गणेशन (57वीं पोजीशन), विनोद खोसला (63वीं पोजीशन), सलील देशपांडे (67वीं पोजीशन) और गौरव गर्ग (86वीं पोजीशन) शामिल किए गए हैं. इस सूची में शामिल किए गए सभी उद्यमियों ने अपनी बेहतर समझ से लोगों को प्रभावित ही नहीं किया है बल्कि अपने लिए बेहतर मुनाफा भी कमाया है. इन्होंने कुछ ऐसी कंपनियों में भी धन लगाया जो डूबने का सौदा थीं. मानना पड़ेगा इनके कार्य करने की क्षमता और वक्त की नजाकत पहचानने की कला को.■

नवीन चड्ढा (30वीं पोजीशन)

नवीन चड्ढा ने भारत, चीन और अमेरिका के ऊर्जा क्षेत्र में काफी निवेश किया है. चड्ढा ने मेक माई ट्रिप और भारत मैट्रिमोनी में भी निवेश किया हुआ है. एक उद्यमी से वेंचर कैपिटलिस्ट बनने वाले नवीन मेफिल्ड फंड एंड इन्वेस्ट्स के प्रमुख हैं. यह ऐसी कंपनी है जिसने चीन, भारत और अमेरिका में ढांचागत संरचना और ऊर्जा के क्षेत्र में काफी धन लगाया हुआ है. इसके 11 आईपीओ हैं और इसने 9 अधिग्रहण किए हुए हैं. साल 2010 में जनता के बीच आई कंपनी मेक माई ट्रिप में भी नवीन का निवेश है जिसका बाजार भाव इस समय लगभग 716 मिलियन डॉलर के आसपास है. इसके अलावा भारत की ही एक दूसरी कंपनी परसिसटेंट सिस्टम भी साल 2010 में ही जनता के बीच आई थी. इस कंपनी में भी नवीन की कंपनी ने निवेश किया हुआ है. कुछ अन्य कंपनियां जिनका नवीन ने अधिग्रहण किया है उनमें विचरस, अंकीना, सी पॉवर शामिल है. साल 2010 में ही नवीन ने सोलर सिटी में भी निवेश किया था जिसका बाजार भाव इस समय लगभग 81 मिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया है. अब ऐसी अफवाहें हैं कि जल्दी ही यह कंपनी अपना आईपीओ भी बाजार में उतारने वाली है. नवीन ने वर्तमान समय में जिन कंपनियों में निवेश कर रखा है उन्हें मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म ऐपसेलेरेटर, क्लाउड स्टोरेज कंपनी स्टोर सिंपल, सोशल मीडिया कंपनी गिग्या, फैशन ऐप पॉशमार्क और भारत स्थित कंपनी भारत मैट्रिमोनी शामिल है. नवीन की नीतियां लोगों पर आधाारित होती हैं. उनका मानना है कि लोग उत्पादों को बनाते हैं न कि उत्पाद लोगों को बनाते हैं.■

साई

साई बाबा भक्तों और विश्व को सुख प्रदान कर कल्याण करते हैं. साई उदार हृदय हैं, जो भक्तगण उनके चरण–कमलों में स्वयं को समर्पित कर देते हैं. साई उनकी सदैव रक्षा और उद्धार करते हैं. साई अपने भक्तों पर स्नेह बरसाते हैं. भक्तों को आत्मदर्शन कराना ही संतों का प्रधान कार्य है.

एक बार...

भक्तों के पालनहार

चौथी दुनिया ब्यूरो

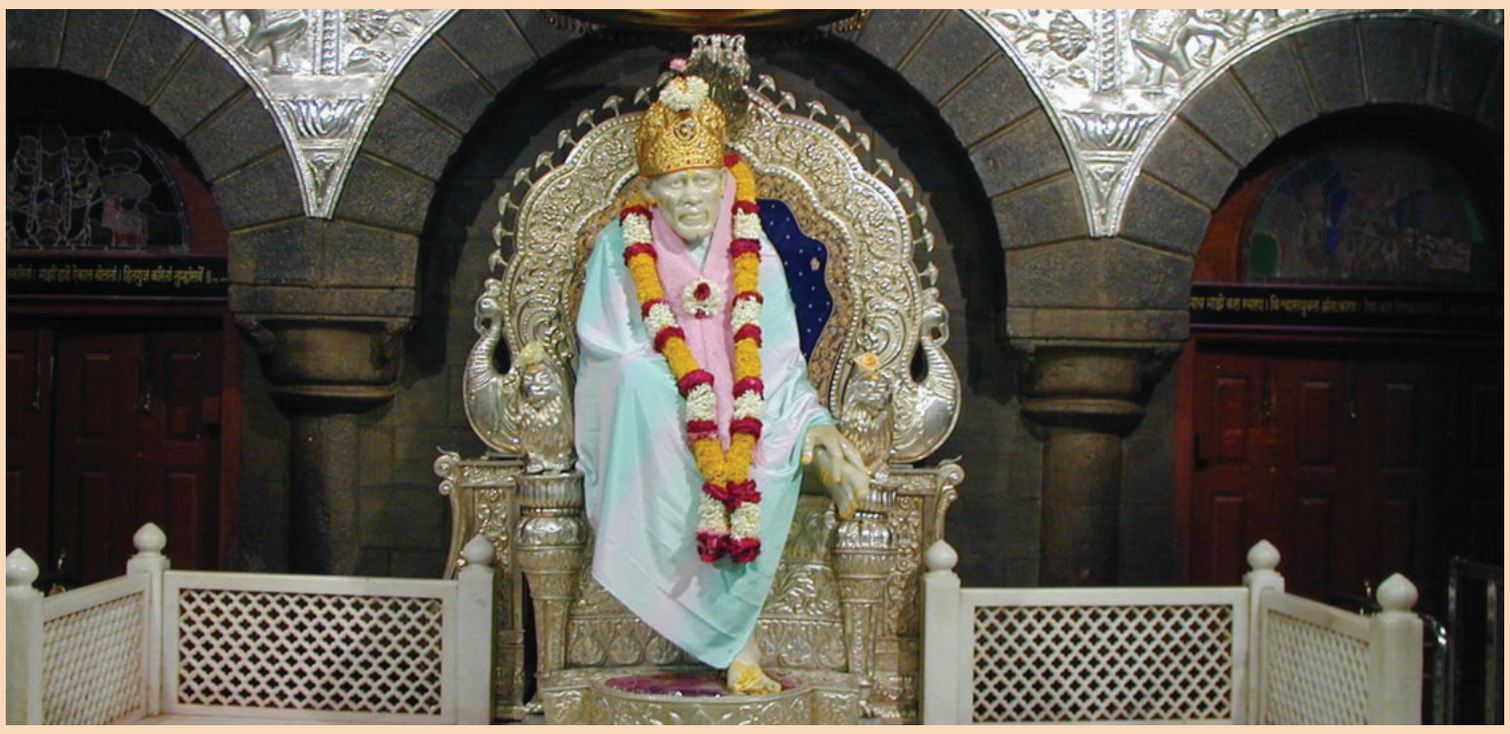

साई बाबा भक्तों की सदा रक्षा करते हैं और उन्हें हर संकट से बचाते हैं. जब साई ही भक्तों की नाव के खेवनहार हों, तो वे बिना किसी डर के भवसागर को पार कर लेते हैं. साई का नाम लेते ही ऐसा प्रतीत होता है कि वह हमारे सामने खड़े हैं. साई का नाम लेने मात्र से भक्तों के अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं. जब भक्त में अहंकार पैदा होने लगता है, तो साई उसका अहंकार मिटा देते हैं. साई बाबा भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं और उन्हें संतुष्टि प्रदान कर सुख का अधिकारी बना देते हैं. जो भक्त बाबा को नमन कर अनन्य भाव से उनकी शरण में जाता है, उसे फिर कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं होती. धर्म, अर्थ और मोक्ष उसे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं. ईश्वर के पास पहुंचने के चार मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति. इन सबमें भक्ति–मार्ग अधिक कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन साई पर विश्वास कर उन कठिनाइयों को पार करते हुए, खाइयों से बचते हुए सीधे अग्रसर होते जाएंगे, तो हम अपने ध्येय अर्थात ईश्वर के समीप आसानी से पहुंच जाएंगे. साई बाबा ने निश्चयात्मक स्वर में कहा है कि स्वयं ब्रह्मा और उनकी विश्व उत्पत्ति, रक्षण और लय करने आदि की भिन्न–भिन्न शक्तियों के पृथकत्व में भी एकत्व है. इसे ही ग्रंथकारों ने दर्शाया है.

साई बाबा ने स्वयं आश्वासन दिया था, मेरे भक्तों के घर अन्न एवं वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा. यह मेरा वैशिष्टय है कि जो भक्त मेरी शरण में आ जाते हैं और अंत:करण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याणार्थ मैं सदैव चिंतित रहता हूं. भगवान श्रीकृष्ण ने भी गीता में यही समझाया है. इसलिए भोजन एवं वस्त्र के लिए अधिक चिंता न करो. यदि कुछ मांगने की ही अभिलाषा है, तो ईश्वर को ही भिक्षा में मांगो. सांसारिक मान एवं उपाधियां त्याग कर ईश–कृपा व अभयदान प्राप्त करो और उन्हीं के द्वारा सम्मानित होओ. सांसारिक विभूतियों से कुपथगामी मत बनो. अपने इष्ट के साथ दृढ़ता से जुड़े रहो. समस्त इंद्रियों और मन को ईश्वर–चिंतन में लगाए रखो. किसी पदार्थ से आकर्षित न हो, सदैव साई स्मरण में मन को लगाए रखो, ताकि वह देह, संपत्ति एवं ऐश्वर्य की ओर आकर्षित न हो. तब चित्त स्थिर, शांत और निर्भय हो जाएगा. यह मन:स्थिति प्राप्त होना इस बात का प्रतीक है कि वह सुसंगति में है. यदि चित्त की चंचलता नष्ट न हुई, तो उसे एकाग्र नहीं किया जा सकता.

रामलाल को बाबा ने स्वप्न में एक महंत के वेश में दर्शन देकर शिरडी आने को कहा. उन्हें नाम ग्राम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. उन्हें साई दर्शन करने की तीव्र इच्छा तो थी, लेकिन पता-ठिकाना ज्ञात न होने के कारण वह बड़े असमंजस में पड़े हुए थे. जो आमंत्रण देता है, वही आने का प्रबंध भी करता है और अंत में हुआ भी वैसा ही. उसी दिन संध्या के समय जब वह सड़क पर टहल रहे थे, तो उन्होंने एक दुकान पर बाबा का चित्र टंगा देखा.

साई बाबा भक्तों और विश्व को सुख प्रदान कर कल्याण करते हैं. साई उदार हृदय हैं, जो भक्तगण उनके चरण–कमलों में स्वयं को समर्पित कर देते हैं. साई उनकी सदैव रक्षा और उद्धार करते हैं. साई अपने भक्तों पर स्नेह बरसाते हैं. भक्तों को आत्मदर्शन कराना ही संतों का प्रधान कार्य है. साई बाबा, जो संत शिरोमणि हैं, उनका तो मुख्य ध्येय ही यही है. जो भक्त उनकी शरण में जाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निश्चित ही दिन–प्रतिदिन उनकी प्रगति होती है. उनके चरणों का स्मरण कर भक्तगण शिरडी आते और उनके समीप बैठकर श्लोक पढ़कर गायत्री मंत्र का जप किया करते थे. साई बाबा जिसे अपने दर्शन हेतु बुलाते हैं, उसे उनके दर्शन अवश्य प्राप्त हो जाते हैं. ऐसा ही बाबा के एक भक्त रामलाल के साथ हुआ.

रामलाल को बाबा ने स्वप्न में एक महंत के वेश में दर्शन देकर शिरडी आने को कहा. उन्हें नाम ग्राम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. उन्हें साई दर्शन करने की तीव्र इच्छा तो थी, लेकिन

पता–ठिकाना ज्ञात न होने के कारण वह बड़े असमंजस में पड़े हुए थे. जो आमंत्रण देता है, वही आने का प्रबंध भी करता है और अंत में हुआ भी वैसा ही. उसी दिन संध्या के समय जब वह सड़क पर टहल रहे थे, तो उन्होंने एक दुकान पर बाबा का चित्र टंगा देखा. स्वप्न में उन्हें जिस आकृति वाले महंत के दर्शन हुए थे, वह उस चित्र के समक्ष ही थे. पूछताछ करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि यह चित्र शिरडी के साई बाबा का है. यह सुनकर उन्होंने शीघ्र ही शिरडी के लिए प्रस्थान कर दिया और जीवनपर्यंत शिरडी में ही निवास किया. इस प्रकार बाबा ने अपने भक्त को अपने दर्शन के लिए शिरडी बुलाया और उनकी लौकिक–पारलौकिक, समस्त इच्छाएं हमेशा पूर्ण कीं. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@ chauthiduniya.com

षष्ठम ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर

दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति

धर्मेंद्र सिंह

देवाधिदेव महादेव अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं और उन्हें हर भय से मुक्ति दिलाते हैं. भगवान शिव को सौम्य रूप और रुद्र रूप, दोनों के लिए जाना जाता है. भगवान शिव को औघड़दानी, अर्द्धनारीश्वर समेत अनेक नामों से पुकारा जाता है. शिव के स्मरण से भक्तों को मोक्ष प्राप्त होता है. शिव के ज्योर्तिलिंग पर जल या गंगाजल का अभिषेक करने का विशेष महत्व हैं. भगवान शिव को पंचामृत स्नान भी कराया जाता है, जिसमें दूध, शहद, देशी घी, शक्कर एवं गंगाजल होता है. शिव का रुद्राभिषेक भी किया जाता है, जिसका विशेष महत्व है. भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंग पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं और उनकी अलग–अलग मान्यताएं हैं. भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है.

भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग (मंदिर) महाराष्ट्र में पुणे से लगभग 100 किमी दूर स्थित है. यह बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है. यह मंदिर पश्चिमी घाट के सह्याद्रि पर्वत पर स्थित है और यहीं से भीमा नदी भी निकलती है, जो दक्षिण दिशा में बहती हुई रायचूर ज़िले में कृष्णा नदी से मिलती है. भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन पुराणों में भी मिलता है. भीमाशंकर के दर्शन से शिव भक्तों को पापों से छुटकारा मिलता है और सुख की प्राप्ति होती है. भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में शिवपुराण में कहा गया है कि एक समय भीम नामक एक राक्षस था, जो कुंभकर्ण का पुत्र था. उसका जन्म कुंभकर्ण की मृत्यु के तुरंत बाद हुआ था. उसे यह नहीं मालूम था कि उसके पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों हुई है. कुछ समय बीतने के बाद उसकी मां ने उसे बताया कि उसके पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों हुई है. यह सुनते ही वह क्रोध से लाल हो गया और भगवान राम का वध करने के लिए आतुर हो उठा.

अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की. उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे विजयी होने का वरदान दिया. वरदान पाने के बाद वह अधिक ताकतवर हो गया और मनुष्यों के साथ-साथ देवी-देवताओं को भी परेशान करने लगा, जिससे सभी भयभीत रहने लगे. धीरे-धीरे सभी जगहों पर उसने आतंक फैलाना शुरू कर दिया.

अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की. उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे विजयी होने का वरदान दिया. वरदान पाने के बाद वह अधिक ताकतवर हो गया और मनुष्यों के साथ–साथ देवी–देवताओं को भी परेशान करने लगा, जिससे सभी भयभीत रहने लगे. धीरे–धीरे सभी जगहों पर उसने आतंक फैलाना शुरू कर दिया. उसने युद्ध में देवताओं को भी परास्त कर दिया. वह जहां भी जाता, मृत्यु का तांडव मचाने लगता. देवता अत्यंत परेशान होकर भगवान शिव की शरण में गए. भगवान शिव ने देवताओं से कहा कि वे शांत हो जाएं. इसके बाद उन्होंने राक्षस भीम का वध कर दिया. देवताओं ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वह इसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजमान हों. देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान शिव भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हुए, जो आज वहां स्थित है.

यहां शिवरात्रि पर दर्शन का विशेष महत्व है. भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए देश–विदेश से हर वर्ष हज़ारों भक्त आते हैं. यहां आसपास कई अन्य मंदिर भी हैं, जिनमें कमलजा, जिन्हें माता पार्वती का अवतार कहा जाता है, का मंदिर प्रमुख है. भीमाशंकर मंदिर के पीछे मोक्षकुंड स्थित है. इसके अलावा कुशराशन्य और सर्वतीर्थ नामक मंदिर भी दर्शनार्थियों के आकर्षण के प्रमुख केंद्र हैं.

कैसे जाएं :-

अगर आप भीमाशंकर मंदिर जाना चाहते हैं, तो रेल, हवाई और सड़क मार्ग से जा सकते हैं. रेल मार्ग से जाने के लिए आप देश के किसी भी प्रमुख स्टेशन से ट्रेन द्वारा पुणे जाएं. वहां से सरकारी बसें रोजाना सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक चलती हैं. आप चाहें तो टैक्सी भी ले सकते हैं. हवाई मार्ग से जाने के लिए देश के किसी भी प्रमुख हवाई अड्डे से पुणे तक और फिर बस अथवा टैक्सी द्वारा भीमाशंकर जा सकते हैं. शिवरात्रि और प्रत्येक माह की शिवरात्रि के मौक़े पर विशेष बस सर्विस का प्रबंध किया जाता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

एक बार...

ईश्वर

चौथी दुनिया ब्यूरो

एक बार एक संत की सभा चल रही थी. लोग दूर–दूर से उनके दर्शन करने और उनके सत्संग का लाभ उठाने के लिए आए थे. वहां उपस्थित सारे भक्त उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे. हर कोई उनसे अपने प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत कर रहा था. संत सबके प्रश्नों के उत्तर स्नेहपूर्वक दे रहे थे. एक जिज्ञासु ने पूछा, महाराज, आप कहते हैं कि ईश्वर हर जगह पर है, उसे कहीं भी देखा या महसूस किया जा सकता है. यह बात सत्य है या ऐसे ही लोगों को भरमाने के लिए कह दी गई है? हमने यह सवाल पहले भी कुछ साधु–महात्माओं से किया था, पर मुझे आज तक इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सका. कृपया आप बताएं. किसी उदाहरण से समझाएंगे, तो अच्छा होगा.

संत मुस्कराए और उन्होंने आश्रम में रखी मेहंदी में से थोड़ी मेहंदी उस व्यक्ति के हाथ में लगाकर पूछा, अभी तुम्हें अपनी हथेली पर कौन सा रंग दिख रहा है? वह व्यक्ति बोला, जी, यह तो कोई भी बता सकता है. यह हरा रंग है. संत ने उसे थोड़ी देर प्रतीक्षा करने को कहा. फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने उसके हाथ धुलवा कर पूछा, अब बताओ कि यह लाल रंग कहां से आया? वह व्यक्ति संत का मुंह देखने लगा. सब उत्सुक हो उठे. संत बोले, जिस प्रकार हरे रंग की मेहंदी में लाल रंग मौजूद है, मगर दिखता नहीं, उसी प्रकार ईश्वर भी हम सबके भीतर अलग–अलग रूपों में उपस्थित है, उसे हम उचित प्रयास से ही अनुभव कर सकते हैं. लोग संत की इस व्याख्या से प्रसन्न हो गए. ■

शिक्षा–ईश्वर हमारे अंदर मौजूद है, केवल महसूस करने की ज़रूरत है.

feedback@chauthiduniya.com

राजनीति शास्त्र के विशेषज्ञ या दूसरे शब्दों में कहें, तो राजनीति का ज्ञान बघारने वाले यह मानते हैं कि राजनीति की खिचड़ी इसलिए पकती है, क्योंकि सब कुछ सबके लिए बराबर नहीं है यानी हर किसी की हर वस्तु में समान हिस्सेदारी नहीं हो सकती. वे यह भी देखते हैं कि कौन, कब, कैसे और क्या प्राप्त करता है? राजनीति की खिचड़ी बनाने वाला एक वरिष्ठ बावर्ची यहां तक कह जाता है कि यह एक कला है, लोगों को ठगने की.

मैं भी मुंह में ज़ुबान रखता हूं...

शफ़ीक आलम

जितने अजीब भैय्या हैं, उतने ही विचित्र उनके सवाल. वह पूछते हैं कि चुनाव के ही मौसम में नेता लोग एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में क्यों जाते हैं? अजीब सवाल है भाई! अब इस मौसम में नहीं जाएंगे, तो कब जाएंगे? ये पार्टियां उनके लिए ऐसी ट्रेनें हैं, जो हर घंटे, हर दिन या हर हफ्ते तो आती नहीं हैं. एक बार निकलीं, तो पूरे पांच साल लग जाते हैं, उन्हें वापस आने में. ऊपर से ऐसे-ऐसे तीसमार खां इन पर सवार होने के लिए पर-पुर्ज़े खोलकर तैयार रहते हैं कि आप का नंबर आएगा भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती और आप हमेशा इसी दुविधा में फंसे रहते हैं. वैसे भी इस मौसम में वे कबीर के अनुयाई बन जाते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब...

कबीर के अनुसरण के उनके अंदाज़ भी निराले हैं. कई ऐसे हैं, जिनके पास एक ट्रेन का टिकट है, लेकिन उसके बावजूद वे किसी दूसरी ट्रेन में बैठने के जुगाड़ में लगे रहते हैं. कई ऐसे हैं, जो आख़िर-आख़िर तक यह ज़ाहिर नहीं होने देते कि वे किस गाड़ी में सवार होंगे. कई ऐसे हैं, जो एक गाड़ी में बैठकर रास्ते में ही उतर जाते हैं, इस उम्मीद में कि कोई बेहतर एक्सप्रेस गाड़ी मिल जाए. कई ऐसे होते हैं, जो पांच साल पहले जिस एक्सप्रेस गाड़ी की सवारी कर चुके होते हैं और उन्हें उस गाड़ी का टिकट नहीं मिल पाता या टिकट मिलने की उम्मीद नहीं रहती, इसलिए वे इस फ़िराक़ में रहते हैं कि कोई लोकल ट्रेन ही मिल जाए और दो या तीन बड़ी गाड़ियों में भिडंत हो जाए, ताकि उनकी लोकल ट्रेन सबसे पहले मंज़िल तक पहुंच जाए.

यह तो हुई उनके गाड़ी बदलने की बात. अगर बात सिर्फ़ यहीं तक रहती, तो कोई बात नहीं थी. बात इसलिए और आगे जाती है, क्योंकि गाड़ी बदलने के साथ-साथ उनके चोले भी बदल जाते हैं और चोलों के साथ-साथ उन चोलों के रंग भी, जैसे काला रंग लाल हो जाता है, लाल हरा बन जाता है और पीला रंग नीला. रंगों का रंग उनके सिर इस तरह चढ़ता है कि एक खास रंग के अलावा उन्हें कोई भी रंग दिखाई नहीं देता. हम इसे कलर ब्लाइंडनेस कैसे कह सकते हैं, यह तो एक बीमारी का नाम है ना? लेकिन, अब रंगों की बात निकल ही आई है, तो लगे हाथ एक और वाक़या आपकी नज़र करता चलूं. किस्सा यूं है कि इस खेल में दो पार्टियां ऐसी हैं, जिनकी नज़दीकी उतनी ही है, जितनी पृथ्वी के दो ध्रुव में है. एक ने अगर पूरब

ओफ्फोह! बात कहां से शरू हुई थी और कहां पहुंच गई? हम बात कर रहे थे दल-बदल विरोधी क़ानून की और बात राजनीतिक खिचड़ी तक पहुंच गई (ज़िक्र जब छिड़ गया कयामत का/बात पहुंची तेरी जवानी तक). अब क्या करें.. भैय्या हैं ही अजीब, सब कुछ उल्टा-पुल्टा. इतनी सी बात उनकी समझ में नहीं आती कि जब चुनाव का मौसम आता है, तो उसमें ऐसा होना कोई अप्राकृतिक बात नहीं है. इस मौसम में हर शख्स यह कहते-कहते कि मैं भी मुंह में ज़ुबान रखता हूं...

को पूरब कह दिया, तो दूसरा मरते मर जाएगा, लेकिन उसे पश्चिम के सिवाय कुछ नहीं कहेगा. एक पार्टी ने अपने दफ्तर में आने वाले लोगों के लिए यह हिटलरी फरमान जारी किया कि चूंकि पीला रंग हमारे धुर विरोधियों का है, इसलिए पार्टी दफ्तर के आसपास पीला रंग दिखाई न दे. बस क्या था, उसके बाद पीले रंग को टकसाल बाहर किया गया और पूरे देश में पार्टी समर्थकों ने पीले रंग के ख़िलाफ़ अभियान शुरू कर दिया. अब देखना यह है कि देश में पीले रंग का क्या हश्र होता है?

लेकिन भैय्या को रंगों से क्या? वह तो ऐसे भोले हैं कि उनके भोलेपन का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जब देश में दल-बदल विरोधी क़ानून लागू हुआ, तो उन्हें लगा था कि इस क़ानून के लागू होने से हमारे राजनेता मौसमी परिंदों की तरह अपना ठिकाना नहीं बदल पाएंगे, उनकी उड़ान पर शिकंजा कस जाएगा या कम से कम उनकी उड़ने की शक्ति क्षीर्ण हो जाएगी और वे एक डाल से दूसरी डाल पर आज़ादी के साथ नहीं जा सकेंगे. लेकिन ये परिंदे अब इतने भी नादान नहीं थे कि अपने ही बनाए हुए जाल (क़ानून) में खुद ही उलझ जाएं और कोई सिरफिरा यह आवाज़ कसे कि लो आप अपने दाम (जाल) में सय्याद (शिकारी) आ गया.

राजनीति शास्त्र के विशेषज्ञ या दूसरे शब्दों में कहें, तो राजनीति का ज्ञान बघारने वाले यह मानते हैं कि राजनीति की खिचड़ी इसलिए पकती है, क्योंकि सब कुछ सबके लिए बराबर नहीं है यानी हर किसी की हर वस्तु में समान हिस्सेदारी नहीं हो सकती. वे यह भी देखते हैं कि कौन, कब, कैसे और क्या प्राप्त करता है? राजनीति की खिचड़ी बनाने वाला एक वरिष्ठ बावर्ची यहां तक कह जाता है कि यह एक कला है, लोगों को ठगने की. अर्थात जो जितना बड़ा ठग है, उसकी खिचड़ी उतनी ही स्वादिष्ट. इन सभी राजनीतिविदों के कथनों और राजनेताओं के क्रियाकलापों में जो समानता है, वह है अवसरवादिता की. इस हुनर को नेताओं ने विद्वानों से सीखा या विद्वानों ने नेताओं से, यह शोध का विषय है. लेकिन, जो बात तय है, वह है कि अवसर का लाभ कैसे उठाया जा सकता है. यहां कहने की कदापि ज़रूरत नहीं कि इसकी सीख हमें अपने नेताओं से लेनी चाहिए और उपरोक्त वर्णित वाक़यात का संबंध भी अवसर को सुअवसर में परिवर्तित करने की कला से है. इसके आगे हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आप खुद समझदार हैं.

ओफ्फोह! बात कहां से शरू हुई थी और कहां पहुंच गई? हम बात कर रहे थे दल-बदल विरोधी क़ानून की और बात राजनीतिक खिचड़ी तक पहुंच गई (ज़िक्र जब छिड़ गया कयामत का/बात पहुंची तेरी जवानी तक). अब क्या करें.. भैय्या हैं ही अजीब, सब कुछ उल्टा-पुल्टा. इतनी सी बात उनकी समझ में नहीं आती कि जब चुनाव का मौसम आता है, तो उसमें ऐसा होना कोई अप्राकृतिक बात नहीं है. इस मौसम में हर शख्स यह कहते-कहते कि मैं भी मुंह में ज़ुबान रखता हूं...ताल ठोंक कर अखाड़े में दो-दो हाथ करने के लिए आ मौजूद होता है और फिर गणित की अलग-अलग विधाओं का इस्तेमाल करके एक-दूसरे को पटखनी देने की कोशिश होती है, कोई ज्यामिति का सूत्र आजमाता है, तो कोई अंकगणित का. कहने का मतलब यह कि जितने मुंह, उतनी बातें. मुझे तो भैय्या की वजह से मैदान में कूदना पड़ा, वरना मैं तो...नहीं नहीं!! ■

feedback@chauthiduniya.com

कविताएं

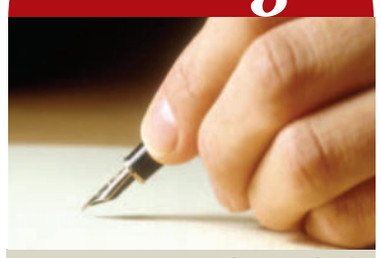

बदस्तूर अब भी जारी है

राजीव अरोड़ा

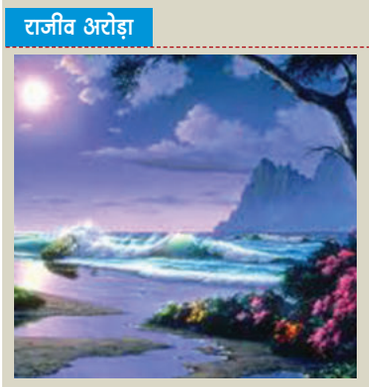

दूर सफेद बादलों का
जश्न तो जारी है,
यूं रह-रहकर तेरा नाचना
गाना, कूदना, भागना
बदस्तूर जारी है,
सबेरा हुआ है, पंछियों का
यूं रह-रहकर मचलना
भी तो जारी है,
कारे-कारे बादलों में
ऐ चांद तेरा ताकना
झांकना, अटखेलिया करना भी तो
बदस्तूर अब भी जारी है.

ख्वाब ख्वाब ही ना होता

मेरा ख्वाब ख्वाब ही ना होता
जो तुम मेरी ज़िंदगी में
यूं आई न होतीं,
ख्वाबों की दुनिया बसी ही न होती
जो तुमको देखा ही ना होता,
मेरी ज़िंदगी का ख्वाब बन बैठीं
तेरी यह याद, तेरा ख्वाब
तेरा यह साथ, तेरा यह प्यार भरा एहसास
यह प्यार भरे मेरे जज्बात
जुड़े तो ना होते,
गर तू मेरे पास से
यूं न गुजरी होती.

मेरी आदत सी बन गई है

तेरी परछाई बन, यूं तुझ संग चलना
मेरी आदत सी बन गई है,
यह आदत ही तो अब
हकीकत सी बन गई है,
हकीकत तेरी मेरी ही तो ज़िंदगी
बन गई है,
ज़िंदगी मेरी अब तुझ संग शुरू होकर
तुझ पर ख़त्म हो जाए,
यही तो मेरी चाहत सी बन गई है.

feedback@chauthiduniya.com

किताब मिली

पुस्तक	लेखक
पनघट पर गागर	पं. राम खेलावन गर्ग
प्रकाशक	**मूल्य**
सारंग प्रकाशन, जबलपुर, मध्य प्रदेश	150 रुपये

आज जबकि हर तरफ़ अतुकांत कविताओं की धूम है और अधिकांशतय: काव्य रचनाएं सीधे-सपाट तरीके से अपना संदेश पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं, ऐसे में गीत, दोहे, कुंडलियों, गीतिका (ग़ज़लों) एवं मुक्तकों से सजी पुस्तक-पनघट पर गागर के जरिये पं. राम खेलावन गर्ग ने काव्य प्रेमियों को एक अमूल्य सौगात दी है. रोज़मर्रा की ज़िंदगी की टूटन, बिखराव और स्वार्थ के मुलम्मे से ढकी जन-सामान्य की मुस्कान पर कवि ने अपनी भरपूर दृष्टि डाली है. इस पुस्तक में शामिल रचनाएं न केवल विसंगतियों पर रोशनी डालती हैं, बल्कि उनसे उबरने का उपाय भी प्रस्तुत करती हैं. तुकांत काव्य रचनाओं के रसज्ञ पाठकों के लिए यह पुस्तक पठनीय है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.
चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई-मेल: feedback@chauthiduniya.com

समीक्षा

इतिहास को सच का आईना

महेंद्र अवधेश

क़रीब दो साल पहले की बात है, मेरे एक अग्रजवत वरिष्ठ सहयोगी ने आपसी चर्चा के दौरान कहा था कि हमारे देश का इतिहास उतना विश्वसनीय नहीं है, जितना उसे लोग समझते हैं. यह अपनी सुविधा और अपनी मर्जी के मुताबिक लिखा गया इतिहास है, जो मौजूदा पीढ़ी को गलत जानकारियां दे रहा है. तब सहसा विश्वास नहीं होता था कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? सवाल उठते थे कि ऐसा आख़िर कौन और क्यों करेगा? लेकिन, पिछले दिनों जब मैंने सुभाष चंद्र कुशवाहा लिखित पुस्तक-चौरी चौरा पढ़ी, तो लगा कि वाकई देश की मौजूदा पीढ़ी के साथ अन्याय किया जा रहा है, उन्हें इतिहास संबंधी मनगढ़ंत जानकारियां बताकर भ्रमित किया जा रहा है.

दरअसल, किसी भी देश का इतिहास उसकी मौजूदा एवं भावी पीढ़ी का रास्ता तैयार करता है. अगर इतिहास ही भ्रामक हो, तो उसे पढ़कर आगे बढ़ने वालों का भविष्य क्या होगा, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है. भारत के स्वाधीनता संग्राम का जब इतिहास लिखा गया, तो उसमें कई प्रसंगों-घटनाओं के वे असली नायक दर्ज होने से रह गए अथवा जबरन कर दिए गए, जिन्होंने जाति-धर्म और क्षेत्र रूपी सारी सीमाएं लांघकर ब्रिटिश हुकूमत को सपने में भी डरने को विवश कर दिया था. यही नहीं, अपने इस कारनामे के लिए वे हंसते-हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए. चौरी चौरा का किसान विद्रोह क्यों हुआ, उसके पीछे असल कारण क्या थे, इस संबंध में समय-समय पर विभिन्न लेखकों-अन्वेषकों द्वारा अनेक बार रोशनी

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले का चौरी चौरा विद्रोह छोटे किसानों, खेतिहर मज़दूरों, समाज के दबे-कुचले वर्ग के उस दर्द का नतीजा था, जो जमींदारों, ताल्लुकादारों, उनके कारिंदों एवं ब्रिटिश अधिकारियों-कर्मचारियों के दमन से उपजा था. फसल न होने या कम होने पर भी जबरन लगान वसूलना, बेगार कराना, विरोध करने पर पीटना-अपमानित करना, निम्न जातियों के लोगों को हेय दृष्टि से देखना, उनके मान-सम्मान से खेलना आख़िर किसे और कहां तक बर्दाश्त होता?

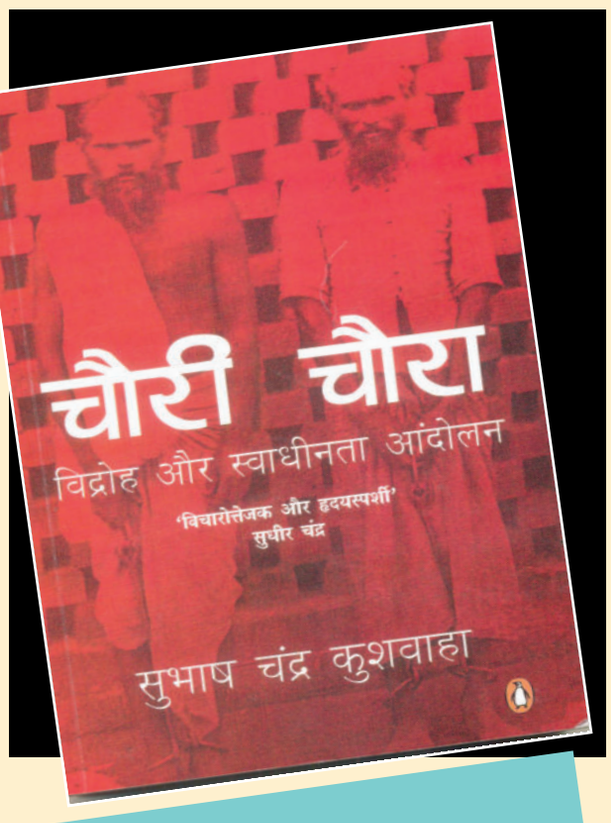

पुस्तक-चौरी चौरा
लेखक-सुभाष चंद्र कुशवाहा
प्रकाशक-पेंगुइन बुक्स, दिल्ली
मूल्य-225 रुपये

डालने के बावजूद सच्चाई सामने नहीं आ सकी. वह सच अक्षरश: देश के सामने आए, इसके लिए अथक प्रयास किया सुभाष चंद्र कुशवाहा ने. अध्ययन, अन्वेषण, संबंधित अति दुर्लभ दस्तावेजों की पड़ताल जैसा श्रमसाध्य और धैर्यसाध्य काम उन्होंने किया. उनके उसी प्रयास का नतीजा है, पुस्तक-चौरी चौरा. सुभाष चंद्र कुशवाहा ने अपनी मेहनत एवं समर्पण के बल पर कई ऐसे तथ्यों को आपस में पिरोने का काम किया है, जो सिर्फ़ जनसामान्य ही नहीं, बल्कि शासक वर्ग की भी आंखें खोलने में कामयाब होंगे. विद्यार्थियों, खासकर इतिहास विषय की पढ़ाई करने वालों के लिए यह पुस्तक काफी उपयोगी साबित हो सकती है.

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले का चौरी चौरा विद्रोह छोटे किसानों, खेतिहर मज़दूरों, समाज के दबे-कुचले वर्ग के उस दर्द का नतीजा था, जो जमींदारों, ताल्लुकादारों, उनके कारिंदों एवं ब्रिटिश अधिकारियों-कर्मचारियों के दमन से उपजा था. फसल न होने या कम होने पर भी जबरन लगान वसूलना, बेगार कराना, विरोध करने पर पीटना-अपमानित करना, निम्न जातियों के लोगों को हेय दृष्टि से देखना, उनके मान-सम्मान से खेलना आख़िर किसे और कहां तक बर्दाश्त होता? तिस पर देश को आज़ाद कराने का व्रत उठाने वाले स्वयंसेवकों का उत्पीड़न आग में घी डालने जैसा था. बावजूद इसके किसान शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज कराने के निकले. चौरा थाने तक गए, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के हिंदुस्तानी दारोगा गुप्तेश्वर सिंह की नासमझी ने प्रदर्शनकारियों के सब्र का बांध तोड़ दिया. नतीजा यह हुआ कि देखते ही देखते थाना आग के हवाले हो गया, पुलिसकर्मी और विभिन्न गांवों से आए चौकीदार गुस्से में बेकाबू प्रदर्शनकारी किसानों के शिकार बन गए. दारोगा गुप्तेश्वर सिंह को प्रदर्शनकारियों ने रेलवे लाइन के पास पकड़ कर इतना पीटा कि उसने मौक़े पर ही दम तोड़ दिया. इस विद्रोह में 24 पुलिसकर्मी मारे गए, जिनमें दारोगा भी शामिल था.

तीन भागों में विभक्त इस पुस्तक में 23 शीर्षकों के अंतर्गत लेखक ने बिंदुवार जानकारियां पिरोई हैं. बकौल इतिहासकार सुधीर चंद्र, यह स्वतंत्रता आंदोलन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण, लेकिन विवादित घटना का विचारोत्तेजक और हृदयस्पर्शी अध्ययन है. यहां तक कि इसकी कुछ स्थापनाओं से असहमत होने वालों (जिनमें मैं खुद हूं) को इसे गंभीरता से लेना होगा. वहीं इतिहासकार संजय शर्मा कहते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन की विरासत के मूल्यांकन में यह एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है. भारतीय राष्ट्रवादी विमर्श में चौरी चौरा जैसी स्थानीय घटनाओं की अहम भूमिका पर दुर्लभ दस्तावेज प्रस्तुत करके यह पुस्तक लोकस्मृति और इतिहास लेखन के बीच संवाद स्थापित करती है. दिलचस्प और पठनीय! ■

mahendra.awdhesh@gmail.com

मेटल फ्रेम में स्लिम स्मार्ट फोन

चीनी कंपनी जियोनी ने भारत में अपना फोन ईलाइफ-एस 5.5 लॉन्च किया है, जिसकी क़ीमत है 22,999 रुपये. यह दुनिया का सबसे पतला फोन है. जियोनी ईलाइफ-एस 5.5 बेहद पतले मेटल फ्रेम में बना है. इसकी मोटाई 5.5 मिमी, वजन 130 ग्राम और स्क्रीन 5 इंच की है. यह फोन फुल एचडी है. इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन है. यह 1.7 जीएचजेड मीडिया टेक एमटी 6592 ओक्टा कोर प्रोसेसर से चलता है. इसमें 16 जीबी इंटरनल स्टोरेज क्षमता है, लेकिन माइक्रो एसडी कार्ड केलिए कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं है. इसमें 13 एमपी का रियर कैमरा है, जिसमें एलईडी फ्लैश भी है. फ्रंट में एक 5 एमपी 95 डिग्री अल्ट्रावाइड एंगल कैमरा है. यह सिंगल सिम फोन है, जो एंड्रॉयड 4.2 जेली बीन पर आधारित है. इसकी बैटरी 2,300 एमएएच की है. इसमें 3जी, वाई-फाई, ब्लूटुथ 4.0 और जीपीएस भी है. यह फोन सफेद, काले, गुलाबी, नीले एवं बैंगनी रंग में उपलब्ध है.■

> वजन में हल्का और दिखने में आकर्षक इस स्कूटर में 125 सीसी और 4 स्ट्रोक इंजन का इस्तेमाल किया गया है. कंपनी के अनुसार, वह इसे एक ऐसे वर्ग के लिए लेकर आई है, जो आम तौर पर राइडिंग नहीं करता.

म्यूजिक सुनना होगा मजेदार

हर शख्स को म्यूजिक सुनना पसंद है, चाहे वह किसी भी उम्र का हो. म्यूजिक सिस्टम शानदार हो, तो आनंद ही कुछ और है. आजकल लोग मोबाइल से म्यूजिक सुनने के लिए ईयरफोन एवं हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं. विभिन्न कंपनियों ने इसी को ध्यान में रखते हुए कई स्टाइलिश ईयरफोन लॉन्च किए हैं, उनमें से निम्नलिखित ईयरफोन बाज़ार में मौजूद हैं:-

स्कलकैंडी अपरॉक हेडफोन

स्कलकैंडी हेडफोन अपनी स्टाइल के लिए जाना जाता है और फुटबॉल के प्रशंसकों को बेहद प्रिय है. इसलिए विभिन्न प्रकार के और विभिन्न रंगों में फुटबॉल क्लब आधारित डिजाइन में खूबसूरत हेडफोन बाज़ार में उतारे गए हैं, जो उपयोग करने में काफी आरामदायक होने के साथ-साथ बेहतरीन साउंड क्वालिटी वाले हैं. इस हेडफोन में सॉफ्ट ईयर पिलोस का उपयोग किया गया है. इसे फोन या कंप्यूटर से आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है. भारतीय बाज़ार में यह 2,899 रुपये में उपलब्ध है.

सेनहाइजर सीएक्स-275 एस

आप स्पार्ट फोन पास रहने के बावजूद ईयरफोन की क्वालिटी अच्छी न होने के कारण बेहतर म्यूजिक का एहसास नहीं कर पाते. यदि बेहतरीन म्यूजिक का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप सेनहाइजर सीएक्स-275 एस देख सकते हैं. देखने में तो यह साधारण है, लेकिन इससे आप बेहतर म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं. अच्छी बात यह कि इसमें कॉल बटन दिया गया है, जिससे आप मोबाइल पर आ रही कॉल रिसीव कर सकते हैं. अक्सर ऐसा होता है कि बाहरी हेडफोन स्मार्ट फोन केसाथ काम नहीं करते, लेकिन सीएक्स-275 एस एंड्रॉयड फोन के साथ आसानी से जुड़ जाता है. अच्छी बात यह है कि ईयरफोन विंडोज और ब्लैकबेरी डिवाइस के साथ भी जुड़ने में सक्षम है. डिजाइन ऐसा है कि आसानी से आपके कानों में आ जाता है. केबल की लंबाई 1.2 मीटर है और सेल्स पैक के साथ दो अतिरिक्त ईयर बड दिए गए हैं. बाज़ार में इसकी क़ीमत 2,999 रुपये है.

आईबॉल यूनीवो हैंडफ्री

आईबॉल ने मोबाइल और पीसी के लिए नया हैंडफ्री पेश किया है, जिसकी क़ीमत 599 रुपये है. यूनीवो हैंडफ्री की मदद से कॉल रिसीव करने के साथ-साथ आप म्यूजिक का भी आनंद ले सकते हैं.

एफ एंड डीएच-50

फेंडा आडियो ने अपना नया संस्करण एच-50 लॉन्च किया है, जो और भी बेहतर डिजाइन और बेहतर साउंड के साथ है. एच-50 की खासियत है इसकी बेहतर आवाज़ और इसका मुलायम एवं लचीला बैंड. कंपनी का कहना है कि आज के समय में हर संगीत प्रेमी चाहता है कि उसके बैग में एक अच्छा ऑडियो डिवाइस हो, ताकि वह साउंड को पूर्णता एवं स्वच्छता के साथ सुन सके. फेंडा ऑडियो अपनी डिवाइस में इन सभी बातों का ध्यान रखा है, इसीलिए हमारी एक्सपर्ट टीम ने स्टीरियो हेडफोन एच-50 पेश किया. भारतीय बाज़ार में इसकी क़ीमत 3,990 रुपये है.■

हीरो प्लेजर के फेसलिफ्ट मॉडल

बेस मॉडल की क़ीमत 53,120 रुपये और एलॉय व्हील मॉडल की क़ीमत 54,730 रुपये है. उक्त नए मॉडल कई नए रंगों में है.

हीरो मोटोकॉर्प ने प्लेजर फेसलिफ्ट के दो वैरिएंट्स पेश किए हैं. कंपनी ने इन्हें पिछले साल अक्टूबर में प्रदर्शित किया था. प्लेजर फेसलिफ्ट को बेस मॉडल और एलॉय व्हील्स वाले दो वैरिएंट में लॉन्च किया गया है. बेस मॉडल की क़ीमत 53,120 रुपये और एलॉय व्हील मॉडल की क़ीमत 54,730 रुपये है. उक्त नए मॉडल कई नए रंगों में हैं. सिंगल सिलेंडर, एयरकूल्ड, फोरस्ट्रोक 102 सीसी इंजन, 6.74 एचपी पावर, 7.85 एनएम का टॉर्क, मोबाइल फोन चार्जिंग सॉकेट, साइड स्टैंड इंडिकेटर, लॉकेबल ग्लवबॉक्स, स्टोरेज कंपार्टमेंट में लाइट बल्ब, बड़ी हेडलाइट्स, टर्न इंडिकेटर एवं शार्प टेल लाइट्स जैसे फीचर्स इनकी खासियत है.

होंडा का फ्यूचर स्कूटर वल्टस

होंडा ने ओसाका मोटरसाइकिल शो में अपने फ्यूचर स्कूटर का एक खूबसूरत नमूना पेश किया है, जिसका नाम है एनएम-4 वल्टस. वल्टस एक लैटिन शब्द है, जिसका मतलब अपीयरेंस, एक्सप्रेशन या फेस होता है. इसे देखकर कोई भी इसका दीवाना हो सकता है. लुक और स्टाइल के मामले में यह अभी तक पेश हुए ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स से अच्छा है. कंपनी के अनुसार, एनएम-4 वल्टस को उसकी यंग डिजायनर टीम ने डिजाइन किया है. टीम ने फ्यूचर स्कूटर का बेस्ट कॉन्सेप्ट पेश किया. डिजायनर्स ने एनएम-4 वल्टस के फ्रंट पर ज़्यादा फोकस किया है. इसकी हेडलाइट्स, टेल लाइट्स एवं इंडिकेटर्स एलईडी हैं. एनएम-4 वल्टस को जापान के एनिमेशन का असली उदाहरण कहा जा सकता है. एनएम-4 वल्टस में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल लगा हुआ है, जो इसके लुक को शानदार बनाता है. इसकी पिछली सीट को फोल्ड करके बैकरेस्ट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. एनएम-4 वल्टस में 745 सीसी ट्वीन सिलेंडर इंजन है, जो 6,250 आरपीएम पर 55 पीएस पावर और 4,750 आरपीएम पर 68 एनएम का टॉर्क देता है. सिक्स-स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन इसके रियर व्हील्स को पावर देता है. राइडर कंप्लीट ऑटोमैटिक मोड या मैनुअल एमटी मोड को सेलेक्ट कर सकता है.■

कैनन का मिड-रेंज डीएसएलआर कैमरा

कैनन ने अपना मिड-रेंज डीएसएलआर कैमरा भारतीय बाज़ार में उतारा है, जिसका नाम कैनन ईओएस-1200 डी है. यह कैमरा आ जाने के बाद पुराना ईओएस-1100 डी कैमरा रि-प्लेस कर दिया जाएगा. यह कैमरा पहले वेरिएंट से ज़्यादा स्टाइलिश है. इसमें लेटेस्ट फीचर्स हैं. कैनन का यह कैमरा बहुत कुछ हाई-रेंज कैनन ईओएस-600 डी से मिलता-जुलता है. इसमें 18 मेगा पिक्सल का सीएमओएस सेंसर है. नया ईओएस-1200 डी 1080 पिक्सल की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है. ये रेजोल्यूशन 30 फ्रेम्स प्रति सेकंड के हिसाब से रिकॉर्ड किए जाते हैं. इस कैमरे में डिजिक-4 प्रोसेसर है, जो बहुत अच्छे परिणाम के लिए जाना जाता है. हो सकता है, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के लिए यह उतना अच्छा कैमरा न साबित हो, लेकिन जिनका बजट काफी कम है, उन्हें कैनन का यह ईओएस-1200 डी कैमरा अच्छा लगेगा. कंपनी ने इसकी क़ीमत 30,995 रुपये रखी है. कैमरे में बेसिक लेंस है, लेकिन अगर आप अलग से लेंस किट लेना चाहते हैं, तो इसके साथ ईएफ-एस 18-55 आईएस-2 और ईएफ-एस 55-250 आईएस-2 लेंस आएंगे, तब इस कैमरे की क़ीमत होगी 39,995 रुपये.■

तिपहिया पर्सनल स्कूटर

थ्री व्हील्ड पर्सलन स्कूटर यूरोपियन मार्केट में खासी पहचान बना चुका है, लेकिन अभी तक यह भारतीय बाज़ार में उपलब्ध नहीं था. यामाहा ने अपने बहुप्रतीक्षित इनोवेटिव थ्री व्हीलर स्कूटर ट्रिसिटी को थाईलैंड बाज़ार में लॉन्च किया है. इस खास स्कूटर में आगे की तरफ़ दो पहिए और पीछे की तरफ़ एक पहिया है. वजन में हल्का और दिखने में आकर्षक इस स्कूटर में 125 सीसी और 4 स्ट्रोक इंजन का इस्तेमाल किया गया है. कंपनी के अनुसार, वह इसे एक ऐसे वर्ग के लिए लेकर आई है, जो आम तौर पर राइडिंग नहीं करता. इसके थ्री व्हील्ड होने की वजह से यदि उस वर्ग के लोग इसे राइड करेंगे, तो उन्हें ड्राइविंग में परेशानी नहीं होगी.■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

खिलाड़ी बने राजनीतिक खिलाड़ी

धर्मेन्द्र कुमार सिंह

feedback@chauthiduniya.com

लोकसभा चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियों में नए–नए लोगों का आना–जाना शुरू हो जाता है. खिलाड़ी भी इससे अछुते नहीं हैं. ऐसे माहौल में खिलाड़ी भी राजनीतिक मैदान में आने से नहीं चूकते. ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है कि खिलाड़ी लोकसभा चुनावों के समय में राजनीतिक पार्टियों में शामिल हो रहे हैं. इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो राजनीति में आए हैं. कई दिग्गज खिलाड़ियों ने राजनीति में अपनी शुरुआत लोकसभा या राज्यसभा से की है. राजनीति में आने वाले खिलाड़ियों की संख्या भी कम नहीं है. इनमें से कुछ खिलाड़ी पहले से ही राजनीति में हैं तो कई इस बार राजनीति में दांव आजमाएंगे. कीर्ति आजाद, मोहम्मद अजहरुद्दीन, नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई सारे खिलाड़ी शामिल हैं. कीर्ति आजाद बिहार के दरभंगा लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद हैं और इस बार भी यहीं से भाग्य आजमा रहे हैं. कीर्ति आजाद इसके पहले दिल्ली गोलमार्केट क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं. कीर्ति आजाद के पिता भागवत झा आजाद बिहार के मुख्यमंत्री थे और कीर्ति आजाद राजनीति में काफी लंबे समय से हैं. कीर्ति आजाद ने 1980 से लेकर 1986 तक क्रिकेट खेला और उन्होंने इस दौरान 7 टेस्ट और 25 एकदिवसीय मैच खेले हैं. भारतीय टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन उत्तरप्रदेश के मुरादाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद हैं और इस बार उनको कांग्रेस ने राजस्थान के सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है. मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 2009 में कांग्रेस में शामिल होकर राजनीति की शुरुआत की थी और मरादाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था. नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर लोकसभा सीट भाजपा के सांसद हैं, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया है. भाजपा ने अमृतसर से राज्यसभा सांसद व राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली को टिकट दिया है. क्रिकेटर से राजनीतिज्ञ बने चेतन चौहन अमरोहा लोकसभा सीट से दो बार भाजपा के सांसद रह चुके हैं और वह तीन बार लोकसभा चुनाव हार भी चुके हैं. सचिन तेंदुलकर के बालसखा रहे विनोद कांबली राजनीति में आए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली. कांबली ने 2009 में मुंबई के बिखरोली से लोकभारती पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव हार गए. पश्चिम बंगाल की एथलीट ज्योतिर्मयी सिकदर भी 2004 में सीपीआई(एम)की तरफ से पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी और उनको जीत मिली, लेकिन 2009 में भी उसी सीट लोकसभा चुनाव लड़ीं, जिसमें उनको हार मिली. ज्योतिर्मयी ने 1998 के बैंकाक एशियन गेम्स में 800 और 1500 मीटर में स्वर्ण पदक हासिल किया था. निशानेबाज जसपाल राणा ने भी 2009 में भाजपा के टिकट पर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से चुनाव लड़ा था और हार गए. राणा 2012 में कांग्रेस में शामिल हो गए. जसपाल राणा ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल किया है. केन्द्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने सचिन को राज्यसभा सांसद बनाया और सचिन को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया है. सचिन ने 24 साल के सर्वश्रेष्ठ अर्तराष्ट्रीय करियर को पिछले साल नवंबर में मुंबई में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट खेलकर अलविदा कहा था और उसके बाद क्रिकेट से सन्यास ले लिया. सचिन ने 200 टेस्ट मैच और 463 वनडे मैच खेले हैं. खिलाड़ी से नेता बनने की चाहत धीरे–धीरे बढ़ती ही जा रही है. निशानेबाज रहे राज्यवर्धन सिंह राठौर राजस्थान में भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह और भाजपा प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के उपस्थिति में भाजपा में शामिल होकर राजनीति की शुरुआत की है. भाजपा ने राज्यवर्धन को जयपुर देहात से लोकसभा सीट से चनाव मैदान में उतारा है. राज्यवर्धन एथेंस ओलंपिक में भारत के एकमात्र पदक जीतने वाले खिलाड़ी थे. वर्ष 2004 में उनको राजीवगांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. भारतीय हॉकी के पूर्व कप्तान और सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्लई आप मे शामिल होकर राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं. पिल्लई को 1999–2000 में सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया और 2000 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है. क्रिकेटर से नेता बनने चले मोहम्मद कैफ कांग्रेस में शामिल हुए है. कैफ कांग्रेस के टिकट पर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की फूलपूर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं. कैफ ने आखिरी मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2006 में एक दिवसीय मैच खेला था. कैफ अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट से खराब प्रदर्शन के कारण बाहर चल रहे हैं. भारतीय फुटबाल टीम के स्टार खिलाड़ी रहे बाइचंग भूटिया और प्रसून बनर्जी ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल होकर राजनीति की शुरुआत की है. दोनों ही फुटबाल खिलाड़ी रहे हैं इस बार दोनों ही टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. बाइचुंग भूटिया दार्जिलिंग लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में है, तो प्रसून बनर्जी हावड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं.■

जोकोविक ने चौथा मायामी खिताब जीता

जोकोविक ने कहा कि मैंने अच्छा मैच खेला, सब कुछ ठीक हुआ. मैंने नडाल को मैच में वापसी का कोई मौका नहीं दिया. मैं ट्रॉफी जीतकर उत्साहित हूं.

दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी राफेल नडाल को नोवाक जोकोविक ने सीधे सेटों में हराकर अपना चौथा मायामी मास्टर्स टेनिस खिताब हासिल किया. दूसरी रैंक खिलाड़ी जोकोविच ने पुरुष वर्ग के फाइनल में नडाल पर 6–3,6–3 से सीधे सेटों में जीत हासिल की. मैच जीतने के बाद जोकोविक ने कहा कि मैंने अच्छा मैच खेला, सब कुछ ठीक हुआ. मैंने उसे मैच में वापसी का कोई मौका नहीं दिया. मैं ट्रॉफी जीतकर उत्साहित हूं. जोकोविक ने इससे पहले 2007, 2011, 2012 में मायामी खिताब जीता था. उन्होंने चार साल में तीसरी मायामी ट्रॉफी जीतने के लिये एक भी सेट नहीं गंवाया और यह उनका चौथा खिताब है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

अरविंद, चेतन और ज्वाला हारे

प्रत्येक वर्ग से मुख्य ड्रा में प्रवेश के लिए चार स्थान दांव पर लगे थे. भारत ने पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल और महिला युगल चारों वर्ग में तीन–तीन जबकि मिश्रित युगल में एक स्थान पर कब्जा जमाया.

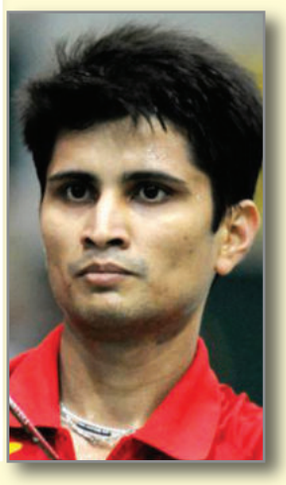

भारत को इंडिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट मे मिश्रित सफलता मिली. पुरुष एकल में पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन अरविंद भट और चेतन आनंद जबकि मिश्रित युगल में स्टार खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा को हार का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद भारत क्वालीफायर में दांव पर लगे 20 स्थानों में से 13 पर कब्जा जमाने सफल रहा. प्रत्येक वर्ग से मुख्य ड्रा में प्रवेश के लिए चार स्थान दांव पर लगे थे. भारत ने पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल और महिला युगल चारों वर्ग में तीन–तीन जबकि मिश्रित युगल में एक स्थान पर कब्जा जमाया. पुरुष एकल से अनूप श्रीधर, अजय कुमार और श्रेयांश जायसवाल जबकि महिला एकल में श्रुति मुंदादा, मुद्रा धान्ये और सयाली गोखले मुख्य टूर्नामेंट में जगह बनाने में सफल रहे.■

21 खिलाड़ियों को हॉकी इंडिया ने किया सस्पेंड

आचार संहिता उल्लंघन और खेल की प्रतिष्ठा गिराने के आरोप में हॉकी इंडिया की अनुशासन समिति ने एनसी रेलवे महिला टीम की सभी 16 खिलाड़ियों और पांच पुरुष खिलाड़ियों को तीन से नौ महीने तक के लिए सस्पेंड कर दिया है. यह खिलाड़ी हॉकी इंडिया की विवाद एवं शिकायत निपटारा समिति के पास 30 दिन के अंदर इस फैसले खिलाफ अपील कर सकते हैं. अनुशासन समिति ने पंजाब एंड सिंध बैंक के श्रवनजीत सिंह और कर्मजीत, एयर इंडिया के गुरप्रीत सिंह, सेना के बच्छितर और नामधारी एकादश के हरप्रीत सिंह के अलावा एनसी रेलवे महिला टीम की सभी 16 खिलाड़ियों को उनके मैनेजर और कोच के साथ सस्पेंड कर दिया. हॉकी इंडिया ने यह प्रतिबंध सदस्यों के सामने पेश किए गए तथ्यों और खिलाड़ियों तथा कोचों की सुनवाई करने के बाद लगाया है. अनुशासन समिति के सदस्यों का मानना था कि इस तरह के कदम से अन्य खिलाड़ियों को भविष्य में अनुशासन में रहने का सबक मिलेगा. ■

आईएबीएफ की मान्यता हुई रद्द

आईएबीएफ को दिसंबर 2012 में मंत्रालय ने अस्थाई तौर पर सस्पेंड किया था. उसने आईएबीएफ को नए सिरे से चुनाव कराने और उसके संविधान को राष्ट्रीय खेल आचार संहिता के मुताबिक बनाने के लिए कहा था. मंत्रालय ने कहा कि आईएबीएफ के 23 मार्च 2013 को हुए चुनाव रद्द करने और स्वतंत्र निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में भारत की राष्ट्रीय खेल विकास आचार संहिता 2011 के प्रावधानों के तहत नए सिरे से चुनाव कराने के निर्देश दिए गए थे.

आईएबीएफ का नए सिरे से चुनाव कराने से इन्कार के बाद खेल मंत्रालय ने इंडियन ऐमेचर बॉक्सिंग फेडरेशन(आईएबीएफ) की मान्यता कर दी है. इससे पहले इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन(एआईबीए) पहले ही बर्खास्त कर चुका है, यह आईएबीएफ को दूसरा झटका लगा है. मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस मसले पर गंभीरता से विचार किया गया और सभी जरूरी तथ्यों को ध्यान में रखकर यह तय किया गया कि आईएबीएफ को सरकार से मिली मान्यता वापस ले ली जाए. आईएबीएफ को दिसंबर 2012 में मंत्रालय ने अस्थाई तौर पर सस्पेंड किया था. उसने आईएबीएफ को नए सिरे से चुनाव कराने और उसके संविधान को राष्ट्रीय खेल आचार संहिता के मुताबिक बनाने के लिए कहा था. मंत्रालय ने कहा कि आईएबीएफ के 23 मार्च 2013 को हुए चुनाव रद्द करने और स्वतंत्र निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में भारत की राष्ट्रीय खेल विकास आचार संहिता 2011 के प्रावधानों के तहत नए सिरे से चुनाव कराने के निर्देश दिए गए थे. इंटरनैशनल बॉक्सिंग फेडरेशन एआईबीए ने समय–समय पर आईएबीएफ को चुनाव कराने की सलाह दी, लेकिन उसने न तो खेल मंत्रालय के निर्देशों पर अमल किया और न ही एआईबीए की सलाह पर. अभी तक नए सिरे से चुनाव नहीं कराए गए. मंत्रालय ने कहा कि किसी भी नैशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को मान्यता उसकी मौजूदा कानूनी स्थिति, इंटरनेशनल फेडरेशन, एशियाई फेडरेशन और ओलंपिक खेल होने पर आईओए से मान्यता पर निर्भर करेगी.■

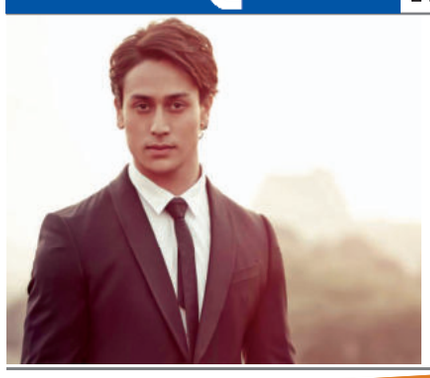

इस फिल्म में आलिया एक साउथ इंडियन बिजनेस प्लानर अनन्या स्वामीनाथन के किरदार में हैं, जबकि अर्जुन एक पंजाबी लड़के कृष मल्होत्रा के किरदार में. रोनित रॉय, अमृता सिंह, रेवती एवं अंकित चित्राल भी फिल्म में मुख्य किरदारों में हैं.

प्यार में यकीन है, शादी में नहीं

वर्ष 2012 में इलियाना डी क्रूज़ ने फ़िल्म बर्फी से हिंदी सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत की थी. अब उनकी तीसरी फिल्म मैं तेरा हीरो भी रिलीज हो गई है. वह बेहद खूबसूरत हैं और बॉलीवुड में उनकी छवि एक ग्लैमरस नायिका की है. शर्मिली स्वभाव की इलियाना को फिल्मों में बिकनी पहनने से परहेज है. फिल्म के कुछ सीन्स में उन्हें बिकनी पहननी थी, लेकिन वह सहज नहीं हो पाईं. इसलिए बिकनी की जगह उन्होंने शॉर्ट्स पहना. फिल्म की शूटिंग के दौरान वरुण से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई. वह कहती हैं कि उन्होंने रणबीर और शाहिद के साथ भी काम किया है, लेकिन सेट पर उनसे ज़्यादा बात नहीं होती थी, जबकि वरुण काफी मज़ाकिया हैं. इलियाना अपनी अगली फिल्मों में सैफ़ अली खान और गोविंदा के साथ पर्दे पर नज़र आएंगी. इलियाना कहती हैं कि वह किसी छवि में नहीं बंधना चाहतीं. इलियाना अपने अभिनय को निखारने के लिए खूब मेहनत कर रही हैं. अन्य स्टारों की तरह वह सोशल साइट्स पर ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं. वह लोगों से कम घुल-मिल पाती हैं. इंडस्ट्री में उनकी प्रिय मित्र करीना कपूर हैं. इलियाना कहती हैं कि करीना से उनकी मुलाकात फिल्म हैपी एंडिंग के सेट पर हुई. दोनों अक्सर साथ में मस्ती करती हैं और मूवी एवं डिनर के लिए जाती हैं. करीना और उनकी बॉन्डिंग दो बिछड़ी हुई बहनों जैसी है. वह अपने रिश्ते के बारे में बात करना पसंद नहीं करतीं, लेकिन ऐसी चर्चा है कि उनका एक ऑस्ट्रेलियन ब्वॉयफ्रेंड है, जिसका नाम एंड्र्यू है. वह एक फोटोग्राफर है और उसके तीन बच्चे भी हैं. इलियाना कहती हैं, हो सकता है कि मैं किसी के प्यार में हूं, लेकिन प्राइवेट लाइफ प्राइवेट ही रहेगी. मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करती, क्योंकि मेरे लिए शादी इतनी ज़रूरी नहीं है. मैं ऐसे लोगों को पसंद करती हूं, जो मेरे लिए कमिटेड हैं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

बड़े बैनर्स के साथ काम करने की ख्वाहिश

मॉडल से अभिनेत्री बनीं वाणी कपूर को पहली ही फिल्म बैंड बाजा बारात से पहचाना जाने लगा, लेकिन इस फिल्म के बाद अभी तक उन्हें कोई दूसरी हिंदी फिल्म नहीं मिली. वह इन दिनों दक्षिण की एक फिल्म अहा कल्यणम की शूटिंग में व्यस्त हैं. इस फिल्म को लेकर वाणी काफी उत्साहित हैं, लेकिन उनके सामने भाषा की समस्या आ रही है. उन्हें तमिल एवं तेलुगु बिल्कुल नहीं आती. इसलिए उनके डायलॉग किसी अन्य की आवाज़ में रिकॉर्ड किए गए हैं, जिन्हें वाणी को रटना पड़ा, ताकि लिपसिंक मैच हो. उसी हिसाब से उन्हें चेहरे के एक्सप्रेशन भी देने पड़े. शुरू में उन्हें यह थोड़ा मुश्किलों भरा लगा, लेकिन अब वह इसे इंज्वॉय कर रही हैं. बैंड बाजा बारात में अनुष्का शर्मा थीं, पर वाणी कहती हैं कि उन्होंने अनुष्का की नकल नहीं की. वह चाहती हैं कि लोग उन्हें देखें और पसंद करें, क्योंकि एक न्यू कमर होने के नाते उन्हें काफी कुछ सीखना है. डायरेक्टर मनीष शर्मा ने उनकी काफी हौसला अफजाई की, काफी कुछ सिखाया और उनकी बातों पर वाणी ने अमल किया. वह कहती हैं कि उनकी पहली ही फिल्म यशराज बैनर्स की थी, वह आगे भी बड़े बैनर्स के साथ काम करना चाहती हैं. अभी यशराज की ही दो फिल्मों को लेकर बात चल रही है. इसके अलावा उन्हें दक्षिण से भी ऑफर मिल रहे हैं. वह मानती हैं कि शुद्ध देशी रोमांस में उनके किरदार को पसंद किया गया, पर उन्हें मलाल है कि उन्हें ऐसा रोल मिला, जो उनकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल मैच नहीं करता था. स्लिम ट्रीम और फिट दिखने वाली वाणी कहती हैं कि पहले वह काफी मोटी थीं. वह नॉर्थ इंडियन हैं और उन्हें खाने-पीने का काफी शौक है. वह जंक फूड की दीवानी हैं, पर अब उन्होंने जंक फूड से तौबा कर ली है. अपनी फिगर को लेकर वह काफी कांसस हैं और रेगुलर एक्सर साइज करती हैं. साथ ही खाने-पीने में भी काफी एहतियात बरतती हैं. ■

फिल्म निर्माण में उतरीं शिल्पा

शिल्पा शेट्टी को सही मायने में सुपर वुमन कहा जा सकता है. हर काम को बखूबी अंजाम देना उन्हें आता है. वह खूबसूरत एवं प्रतिभाशाली अभिनेत्री, ग्लैमरस मॉम, आदर्श पत्नी और आईपीएल टीम की मालकिन भी हैं. अब तो वह फिल्म निर्मात्री भी बन गई हैं. जी हां, उन्होंने ढिशकियाऊ नामक फिल्म का निर्माण किया है. इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं सन्नी देओल एवं हरमन बावेजा. शिल्पा ने खुद भी इस फिल्म में आइटम सॉन्ग किया है. आज भी जब वह परफॉर्म करती हैं, तो लोग दिल थामकर बैठ जाते हैं. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर सकी. वह कहती हैं कि यह उनका पहला अनुभव था, आगे भी वह कुछ बेहतरीन फिल्में बनाना चाहती हैं. वह मानती हैं कि निर्माता बनना काफी जोखिम भरा काम है. जब उन्होंने फिल्म निर्माण का फ़ैसला लिया, तो दर्शकों की पसंद को भी ध्यान में रखा. उन्होंने एक्शन फिल्म बनाने की सोची, लेकिन स्क्रिप्ट का भी ध्यान रखा. इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में मरीन ड्राइव, बैलार्ड पियर, सी लिंक, चीएम विलेज और सड़कों पर भीड़ के बीच की गई. हरमन को फिल्म में लेने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि अब तक हरमन ने मात्र तीन फिल्में की हैं. ऐसे में उन्हें फ्लॉप नहीं कहा जा सकता. शिल्पा को हरमन पर काफी भरोसा है. वह कहती हैं कि अच्छी स्क्रिप्ट मिले, तो वह बेहतरीन अभिनय कर सकते हैं. शिल्पा बताती हैं कि सन्नी एक्शन के अवतार माने जाते हैं और उनकी फिल्म भी एक्शन फिल्म थी. वह खुद भी सन्नी के होम प्रोडक्शन की कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं. आयशा को चुनने के पीछे भी दिलचस्प वाक्या है. दरअसल, आयशा उनके पास ड्रेस डिजाइनिंग के लिए आई थीं और शिल्पा तब तक 98 ऑडिशन ले चुकी थीं. आयशा का भी उन्होंने ऑडिशन लिया और वह रोल में फिट हो गई. शिल्पा अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी सजग रहती हैं. वह कहती हैं कि हर शख्स को अपने लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए. शिल्पा हफ्ते में सिर्फ़ तीन दिन वर्कआउट करती हैं. उन्हें स्विमिंग नहीं आती. वह जिम और योग रेगुलर करती हैं. वह कहती हैं कि उन्होंने मिक्स्ड वर्कआउट किया, क्योंकि मां बनने के बाद जो वजन बढ़ता है, उसे सिर्फ़ योग से घटाया नहीं जा सकता. वह कहती हैं कि फिटनेस के लिए कोई वक्त नहीं होता, आप किसी भी दिन व्यायाम शुरू कर सकते हैं. आप हफ्ते में दो बार भी कर सकते हैं. ■

प्यार में पड़े आलिया और अर्जुन

खूबसूरत आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर की 2 स्टेट्स जल्द ही रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में दोनों ने काफी इंटिमेट सींस दिए हैं. कहा यह भी जा रहा है कि दोनों के बीच इन दिनों प्यार परवान चढ़ रहा है. हालांकि, दोनों अपने रिश्ते के बारे में खुलेआम कुछ भी कहने से बच रहे हैं. अर्जुन कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं, हमेशा एक्टिंग नहीं करते. हम सिर्फ़ दोस्त हैं और इसके आगे क्या हो सकते हैं, यह तो समय आने पर ही पता चलेगा. आलिया भी इसी तरह के गोल-मोल जवाब देती हैं. अपनी फिल्म में बोल्ड सींस के बारे में वह कहती हैं कि यह फिल्म की डिमांड है और पापा की फिल्में तो इससे भी ज़्यादा बोल्ड होती हैं. उनकी फिल्मों से तो काफी कम बोल्ड है मेरी फिल्म. आपको बता दें कि अर्जुन आलिया से पहले सलमान खान की बहन अर्पिता के साथ डेट कर रहे थे और आलिया का नाम वरुण धवन एवं सिद्धार्थ मल्होत्रा से जोड़ा जा रहा था. फिलहाल दोनों अपने रिश्ते को कभी दोस्ती, तो कभी को-स्टार बता रहे हैं. 2 स्टेट्स एक रोमांटिक फिल्म है. फिल्म की कहानी कुछ साल पहले आए चेतन भगत के उपन्यास 2 स्टेट्स पर आधारित है. इस किताब को भी खूब पसंद किया गया था.

इस फिल्म में आलिया एक साउथ इंडियन बिजनेस प्लानर अनन्या स्वामीनाथन के किरदार में हैं, जबकि अर्जुन एक पंजाबी लड़के कृष मल्होत्रा के किरदार में. रोनित रॉय, अमृता सिंह, रेवती एवं अंकित चित्राल भी फिल्म में मुख्य किरदारों में हैं. फिल्म के निर्देशक अभिषेक वर्मन हैं. फिल्म को प्रोड्यूस किया है साजिद नाडियाडवाला और करन जौहर ने. ■

आमिर के नाम का सहारा

स्टार्स संस की डेब्यू सीरीज में एक और स्टार जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर की डेब्यू फिल्म हीरोपंती से हो रही है. 23 मई को रिलीज होने वाली इस फिल्म का फर्स्ट लुक अप्रैल के प्रथम सप्ताह में लॉन्च होगा. टाइगर के साथ परफेक्शनिस्ट आमिर का नाम भी जुड़ने वाला है. जी हां, यह लॉन्च आमिर खान करेंगे. दरअसल, फिल्म निर्माता फर्स्ट लुक बड़े स्तर पर लॉन्च करना चाहते थे. जब इस पर चर्चा हुई, तो फिल्म निर्माता के साथ-साथ खुद जैकी श्रॉफ ने भी आमिर का नाम चुना. जैकी के साथ आमिर के अच्छे ताल्लुकात हैं. इसलिए आमिर खान ने भी यह ऑफर तुरंत स्वीकार कर लिया. आमिर टाइगर को काफी पसंद करते हैं. ट्रेलर लॉन्चिंग के इवेंट में आमिर न केवल फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करेंगे, बल्कि पहली बार ऑडियंस और मीडिया से टाइगर की मुलाकात भी कराएंगे. टाइगर इससे पहले कभी भी मीडिया के सामने औपचारिक तौर पर नहीं आए हैं. दरअसल, टाइगर होनहार हैं. वह मिक्स ब्रिड हैं. उनकी मां आयशा इंडो फ्रेंच मूल की हैं. इसलिए उनका लुक भी काफी अलग और आकर्षक है. टाइगर ने अपनी बॉडी पर भी काफी मेहनत की है. अब देखते हैं कि अपनी इस फिल्म से टाइगर क्या धमाल करते हैं. आपको बता दें कि सुनील शेट्टी की बेटी अतिया और आदित्य पंचोली के बेटे सूरज भी इस साल बॉलीवुड में डेब्यू होने वाले हैं. सूरज को सलमान लांच कर रहे हैं, जबकि टाइगर को आमिर खान. सूरज और टाइगर के बीच मुकाबले में कौन विनर होता है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा. ■

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

14 अप्रैल–20 अप्रैल 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

बिहार–झारखंड

हाथ तो मिले मगर दिल नहीं

राहुल गांधी किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि यूपीए के लिए वोट मांग रहे हैं. उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद कांग्रेस के छह प्रत्याशियों के लिए वोट मांग चुके हैं, इसलिए यह कैसे कहा जा सकता है कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा कि राहुल व सोनिया गांधी के साथ लालू प्रसाद की रैली का अभी कोई कार्यक्रम नहीं है. उनका दावा है कि चुनावी रणनीति के तहत हर नेता को चुनावी रैलियों का दायित्व दिया गया है इसलिए इसका कोई दूसरा मायना नहीं निकाला जाना चाहिए. प्रेमचंद्र मिश्र की बात को ही अगर आगे बढ़ाया जाए तो कहा जा सकता है कि यह कैसा गठबंधन है कि सहयोगी दल के बड़े नेता साथ नहीं आ रहे हैं. एनडीए के नए-नए दोस्त रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा कर रहे हैं.

सरोज सिंह

लाख जतन के बाद कांग्रेस और राजद ने लोकसभा चुनाव के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया और चुनावी गठबंधन का ऐलान किया. कांग्रेस से दोस्ती लालू के लिए पहला और अंतिम विकल्प था इसलिए वह कोई भी कुर्बानी देकर इस मंजिल तक पहुंचना चाहते थे और अपनों की नाराजगी लेकर भी वह यहां तक पहुंचने में कामयाब रहे. कांग्रेस भी हां और न करते लालू के खेमे में आ गई. लेकिन दोस्ती गांठने की जद्दोजहद में इतनी उठापटक हुई कि यह सभी जान गए कि यह दोस्ती दिल से नहीं बल्कि मजबूरी का फल है. लिहाजा जो संदेश जाना था वह नहीं गया, उल्टे यह बात मतदाताओं के बीच पहुंची की लालू प्रसाद ने तालमेल भले कर लिया हो पर जमीनी लड़ाई में एक दूसरे को गले लगाना मुश्किल होगा. तालमेल के तहत जिन 12 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी जंग में हैं, उन जगहों पर राजद के परम्परागत वोटर उहापोह में हैं. करें तो क्या करें? कांग्रेस के लोग फिलहाल खुलकर तो नहीं पर दबी जुबान से कहने लगे हैं कि कहीं इस बार हाल लोजपा वाला न हो जाए. गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव के बाद लोजपा ने यह आरोप लगाया था कि राजद के वोटरों ने लोजपा प्रत्याशियों का दिल से साथ नहीं दिया. इस बार भी जब लोजपा, राजद और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात चल रही थी तो लोजपा वालों ने यह कहकर दूरी बनानी शुरू कर दी कि यादवों ने पिछले चुनाव में साथ नहीं दिया जिस वजह से पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा. लोजपा ने तो अपना वोट राजद को दिलवा दिया पर राजद का वोट लोजपा के हाथ नहीं आया. यही कहानी अभी से ही कांग्रेस के कुछ नेता ऑफ द रिकार्ड सुना रहे हैं. इस कहानी को तब और बल मिला जब राहुल गांधी की सभा से लालू प्रसाद नदारद रहे. लालू यादव ने इस सम्बंध में कहा कि मेरा कार्यक्रम पहले से तय था लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्र दूसरी बात कहते हैं. वह कहते हैं कि ऐसी कोई परम्परा नहीं रही है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्रोग्राम में गठबंधन दलों के नेताओं को शामिल किया जाए. राहुल गांधी किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि यूपीए के लिए वोट मांग रहे हैं. उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद कांग्रेस के छह प्रत्याशियों के लिए वोट मांग चुके हैं, इसलिए यह कैसे कहा जा सकता है कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा कि राहुल व सोनिया गांधी के साथ लालू प्रसाद की रैली का अभी कोई कार्यक्रम नहीं है. उनका दावा है कि चुनावी रणनीति के तहत हर नेता को चुनावी रैलियों का दायित्व दिया गया है इसलिए इसका कोई दूसरा मायना नहीं निकाला जाना चाहिए. प्रेमचंद्र मिश्र की बात को ही अगर आगे बढ़ाया जाए तो कहा जा सकता है कि यह कैसा गठबंधन है कि सहयोगी दल के बड़े नेता साथ नहीं आ रहे हैं. एनडीए के नए–नए दोस्त रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा कर रहे हैं. साथी दलों के नेताओं के नामांकन में भाजपा के बड़े नेता जा रहे हैं. सीट की जरूरत के हिसाब से एनडीए अपने नेताओं का कार्यक्रम तय कर रहा है. यह सब पूरे समन्वय के साथ तब हो रहा है जबकि ये लोग दो महीने पहले ही भाजपा के साथ जुड़े हैं लेकिन लालू प्रसाद और कांग्रेस का रिश्ता तो काफी पुराना है. इसके बावजूद कांग्रेस ने तालमेल में पूरी कीमत वसूली और अब रैलियों में लालू प्रसाद के साथ मंच साझा करने में आनाकानी कर रही है. सूत्र बताते हैं कि राहुल या फिर सोनिया गांधी के साथ लालू की रैली की संभावना बहुत ही कम है. राहुल गांधी ने बड़े नेताओं के दबाव में लालू प्रसाद से गठबंधन करना स्वीकार तो कर लिया पर वे नहीं चाहते हैं कि किसी ऐसे नेता के साथ मंच साझा करें जिसे अदालत ने दोषी ठहरा दिया है. शायद यही मजबूरी सोनिया गांधी के साथ भी है. राहुल और सोनिया की यही मजबूरी राजद के वोटरों को उलझन में डाल कर रखा हुआ है. राजद के वोटर कह रहे हैं कि जब बड़े नेता साथ नहीं दिख रहे हैं तो हम क्या समझें? राहुल गांधी और सोनिया गांधी वहीं सभा कर रहे हैं जहां कांग्रेस के प्रत्याशी हैं. राजद प्रत्याशी को जिताने के लिए उनके निर्वाचन क्षेत्र में जाकर कांग्रेस के बड़े नेता वोट मांगें तभी तो दोस्ती का संदेश जाएगा. ऐसे तो लग रहा है कि गठबंधन केवल टिकट को बांटने के लिए हुआ है न कि चुनाव जीतने के लिए. बताया जा रहा है लालू प्रसाद भी इस गठबंधन के चुनावी फायदे की संभावना से अच्छी तरह वाकिफ हैं. लालू प्रसाद को अच्छी तरह पता है कि बिहार में कांग्रेस की जमीनी ताकत कितनी है लेकिन इसके बावजूद भी अगर गठबंधन के लिए लालू प्रसाद ने रात दिन एक कर दिया तो इसकी एक मात्र वजह यह रही कि राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए उन्हें एक सीढ़ी की जरूरत थी और कांग्रेस उनके सामने एक मात्र विकल्प था. लालू तो अपने मकसद में कामयाब रहे पर नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है. उदाहरण के तौर पर देखें तो हाजीपुर में कांग्रेस प्रत्याशी संजीव कुमार टोनी के लिए यादवों में कोई खास उत्साह नहीं है. यही हाल नालंदा का भी है. ऐसे में राजद और कांग्रेस गठबंधन को लेकर विरोधी भी काफी आक्रामक हो गए है. जदयू प्रवक्ता नवल शर्मा कहते हैं कि राजद और कांग्रेस के बीच बेमेल गठबंधन हुआ है इसलिए देर–सबेर इसका टूटना तय है. एक–दूसरे की सभाओं में बड़े नेता नहीं जा रहे हैं. इसका मतलब तो यही है कि यह गठबंधन केवल कागजों पर ही है. नवल शर्मा कहते है कि दो भ्रष्टाचारी दलों का यह तालमेल है जिसे इस चुनाव में जनता पूरी तरह नकार देगी. न राहुल गांधी को लालू प्रसाद पर भरोसा है न लालू प्रसाद को कांग्रेस की ताकत पर भरोसा है. ऐसे में इस कपटी गठबंधन का खाता खुल जाए यही बड़ी बात होगी. नवल शर्मा ने कहा कि गठबंधन का एक धर्म होता है जिसे हमारे नेता नीतीश कुमार निभाते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और राजद के बीच दोस्ती किसी ठोस बुनियाद पर नहीं बल्कि टिकट के बंटवारे के लिए हुई है. इसलिए इस दोस्ती को जनता चुनाव में पूरी तरह खारिज कर देगी. लोजपा प्रवक्ता ललन चंद्रवंशी कहते हैं कि विधानसभा में कांग्रेस नीतीश कुमार को समर्थन देती है और चुनाव में लालू यादव से हाथ मिलाती है. कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र को जनता पूरी तरह समझ चुकी है और चुनाव में राजद और कांग्रेस के प्रत्याशी पूरी तरह मात खाएंगे. ललन चंद्रवंशी कहते हैं कि तालमेल हमलोगों ने भी किया और जनता देख रही है कि पूरे दिल से इस धर्म को निभा रहे हैं. राजद और कांग्रेस तो बस गठबंधन का दिखावा कर रहे हैं. लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्र कहते हैं कि नीतीश सरकार को हमलोगों ने कोई लिखित समर्थन नहीं दिया है. केवल साम्प्रदायिक दलों को रोकने के लिए विधानसभा में समर्थन दिया गया और इसमें इससे आगे कोई बात नहीं हैं. राहुल गांधी भी नीतीश कुमार के विकास के दावे को खोखला बता चुके हैं. कांग्रेस पूरी तरह जदयू के खिलाफ है. अब प्रेमचंद्र मिश्र जो दावा करें पर बिहार की जमीन पर उन्हें इस बात को साबित करना होगा कि जदयू को समर्थन बस मौके की नजाकत थी और लालू से दोस्ती वक्त की मांग. यह काम आसान नहीं है क्योंकि वोटरों के मन में यह बात बैठने लगी है कि कांग्रेस और राजद की दोस्ती दिल की गहराई से नहीं है. अगर जल्द से जल्द इस धारणा को नहीं तोड़ा गया तो फिर इसका चुनावी नुकसान कांग्रेस को होना तय है.■

feedback@chauthiduniya.com

नीतीश की सभा में पत्थर और चप्पल के मायने

नीतीश की सभाओं में पत्थरबाजी क्या हुई विरोधियों को एक बार फिर इस चुनावी मौसम में उनपर बरसने का मौका मिल गया. कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से गिर रहा है, इसलिए जिंदाबाद के नारे कम और मुर्दाबाद के नारे ज्यादा लग रहे हैं लेकिन जदयू प्रवक्ता नवल शर्मा कहते हैं कि पत्थरबाजी की जो एक–दो घटनाएं हुईं हैं वह प्रायोजित हैं और भाजपा ने एक साजिश के तहत यह करवाया है. चुनावी मैदान में चूंकि भाजपा के पैर उखड़ रहे हैं इसलिए वह इस तरह की ओछी हरकतों पर उतर आई है. नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि चुनाव परिणाम चाहे जो हो वह अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे. मिट्टी में मिल जाएंगे पर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे. यही बात भाजपा के गले नहीं

उतर रही है और वह इस तरह की गिरी हुई हरकत पर उतर आई है. जबकि दूसरी तरफ भाजपा नेता राकेश सिंह कहते हैं कि किसी पर भी पत्थर फेंकने का संस्कार भाजपाईयों का नहीं हो सकता. दरअसल नीतीश कुमार ने जो फसल बोई है अब वह उसी को काट रहे हैं. बिहार के लोग उनसे नाराज हैं, उन्होंने जो वायदे किए थे वे पूरे नहीं हुए. उसी का गुस्सा बिहार के लोगों में हैं. हालांकि वह कहते हैं कि किसी पर पत्थर फेंकनाअच्छी बात नहीं है. बेहतर होगा लोग वोट के माध्यम से अपने गुस्से का प्रकटीकरण करें और नीतीश कुमार को चुनावी मैदान में बुरी तरह परास्त कर दें. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह की घटना कभी–कभी हो जाती है लेकिन चूंकि नीतीश कुमार पर पत्थर फेंकने की घटना उनके गृहक्षेत्र नालंदा में हुई है इसलिए इसका राजनीतिक महत्व ज्यादा दिखाई पड़ रहा है. इसलिए यह जदयू व नीतीश कुमार के लिए चिंता की बात तो है ही. ■

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

एक नज़र

झारक्राफ्ट सम्मानित

देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कार्य करने वाले संस्थान इंडियन इकोनॉमिक स्टडी ने राष्ट्रीय स्तर बेहतर प्रदर्शन के लिए झारक्राप्ट को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस तथा झारक्राप्ट के प्रबंध निदेशक व विशेष उद्योग सचिव धीरेंद्र कुमार को उद्योग रत्न अवार्ड से नवाजा है. पिछले दिनों बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में यह सम्मान पांडिचेरी के उपराज्यपाल वीरेंद्र कटारिया ने प्रदान किया. मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एमवी राजशेखरन राव मौजूद थे. राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस कार्यशाला में देश भर से विख्यात अर्थशास्त्री, उद्योग जगत के अलावा अन्य क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल थे. झारक्राफ्ट को यह सम्मान झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सिल्क उत्पादन, हैंडलूम, हैंडिक्राफ्ट के माध्यम से लाखों रोजगार सृजन करने के लिए दिया गया है. जहां झारक्राफ्ट ने रोजगार के साथ-साथ बेहतर उत्पादन कर लाखों लोगों को घर में रोजगार उपलब्ध कराया है. प्रबंध निदेशक धीरेंद्र कुमार ने यह पुरस्कार ग्रहण किया. मौके पर उपराज्यपाल ने झारक्राफ्ट के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि अन्य राज्यों को झारक्राफ्ट योजना मॉडल को अपनाना चाहिए. *– किशोर मिश्रा*

बैठक आयोजित

खगड़िया सदर अस्पताल के यक्ष्मा भवन में टीबी फोरम की बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ. एस. पी. मंडल ने कहा कि टीबी एक संक्रामक रोग है. इसलिए लोगों को टीबी रोग के प्रति जागरूक बनाना, रोगों की रोक-थाम करना तथा इसके फैलाव को रोकना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि दो सप्ताह या इससे ज्यादा दिनों से लगातार खांसी होना, सीने में दर्द होना, संध्या के समय बुखार आना, भूख कम लगना एवं बलगम में खून आना इसके लक्षण हैं. बैठक में जिला के संभावित यक्ष्मा रोगी एवं यक्ष्मा पीड़ित व्यक्ति को अरएनटीसीपी के द्वारा सुविधाओं की जानकारी विस्तृत रूप से दी गई. जिसमें ममता हेल्थ इन्स्टीट्यूट फॉर मदर एण्ड चाइल्ड एवं सहयोगी संस्था संपूर्ण जागृति के सचिव विकास रंजन के द्वारा भी जानकारी दी गई. इस अवसर पर ममता के जिला समन्वयक दीपक कुमार, नन्दकिशोर कुमार, रौशन कुमार, सूर्य कुमार भारती, लाल मणी, चन्द्रशेखर प्रसाद, शेखर कुमार, मोहन कुमार सहित दर्जनों अन्य स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे. *– नन्दकिशोर शर्मा*

छात्र नेता रालोसपा में

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रदेश कार्यालय मंत्री जयनारायण कुमार ने लोकसभा चुनाव के अहम मौके पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समता पार्टी में शामिल हो गए. इस मिलन समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अरुण कुमार सहित दर्जनों नेता उपस्थित थे. इस मिलन समारोह में कई वरीय नेता भी रालोसपा का दामन थामा. इस मौके पर जयनारायण कुमार ने कहा कि उपेन्द्र कुशवाहा के नेतृत्व में मोदी की सरकार बनेगी. वहीं बिहार में भी एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी.■ *– मनेन्द्र कुमार*

जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाएगी जनता

इन्तेजारुल हक

लोकसभा चुनावों की दस्तक के साथ ही एक बार फिर नेता और उनके कार्यकर्ता जनता के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं लेकिन चम्पारण की जनता इस बार हिसाब-किताब चूकता करने के मूड में है. इस संसदीय क्षेत्र के माहौल को देखकर लगता है कि इस बार चम्पारण के बदहाल ऐतिहासिक धरोहरों की उपेक्षा का मामला आगामी लोकसभा चुनाव में राजनीतिक मुद्दा बनकर उभरेगा और जनता इस मुद्दे पर राजनेताओं व स्थानीय जनप्रतिनिधियों को घेरने का प्रयास करेगी. पूर्वी व पश्चिमी चम्पारण में सदियों से स्थापित करीब एक सौ से अधिक ऐतिहासिक धरोहरों को विकसित करने के लिए राजनेताओं व स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने की चर्चा इन दिनों राजनीतिक गलियारों में होने लगी है. यहां की बदहाल ऐतिहासिक धरोहरों को विकसित करने के लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं राजनेताओं व जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न मौकों पर की तो गई हैं किन्तु इन पर दस फीसदी भी अमल नहीं हुआ है. यही वजह है कि जनता में काफी आक्रोश है. जानकार बताते हैं कि पूर्वी चम्पारण जिले में 66 व पश्चिमी चम्पारण में करीब 30 ऐसे पुरातत्विक एवं ऐतिहासिक धरोहर हैं जो सरकारी योजनाओं से काफी दूर हैं और इसे विकसित करने के लिए की गई अब तक की तमाम कार्रवाई हवा-हवाई साबित हुई है. केसरिया का बौद्ध स्तूप हो या फिर कस्बा मेहसी में साढ़े सात बीघे में फैला गुरु नानक मठ या फिर चकिया प्रखण्ड का बेदीबनगढ़ व सीताकुंड. तमाम ऐतिहासिक धरोहरें आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है. प्रत्येक वर्ष केसरिया में लाखों रुपये के खर्च पर केसरिया महोत्सव होता है और घोषणाओं की बौछार होती है किन्तु महोत्सव की समाप्ति के बाद तमाम घोषणाएं हवा में रह जाती है. केसरिया का बौद्ध स्तूप दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है. यहां पर्यटकों का आगमन सालों भर होता है. इसकी ऊंचाई एक सौ पांच फिट है और यह स्तूप छह तलों का है. प्राकृतिक आपदाओं के कारण यह छोटा हो गया है.

बेदीबनगढ़ भी बदहाल स्थिति में ही है और इसकी भी चिन्ता किसी को नहीं है. सीताकुंड धाम करीब अठारह एकड़ में पन्द्रह फिट ऊंचे टीलेनुमा क्षेत्र में स्थित है, जो किसी प्राचीन किले का अवशेष है. जानकार बताते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम और सीता यहां आए थे. नवविवाहिता सीता के स्नान के लिए बना सीताकुंड, गिरीराज महादेव का प्रचीन मंदिर, पुरातत्विक महत्व के शिलालेख समेत कई प्राचीन देवी-देवताओं की तस्वीरें जीर्ण-शीर्ण हो गई हैं. चैत्र रामनवमी पर यहां मेला भी लगता है. कस्बा मेहसी में मिर्जा हलीम साह की चार सौ साल पुरानी दरगाह

वर्तमान में तिरहुत प्रमण्डल के आयुक्त नर्मदेश्वर लाल ने इन 66 ऐतिहासिक धरोहरों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग को प्रस्ताव भेजा था. कुल मिलाकर चम्पारण की ऐतिहासिक धरोहरें हाशिए पर हैं और इनकी उपेक्षा का मामला इसबार के चुनाव में राजनेताओं को महंगा साबित हो सकता है.

का भी अबतक विकास नहीं हो पाया है. अकबरनामा भी यहीं है. यहां की ऐतिहासिक धरोहरों में बेलवतिया का मठ भी काफी चर्चित है. 1895 में केशव बाबा द्वारा स्थापित कबीर पंथ की पारखा शाखा का कबीरा आश्रम तथा साहेब की गद्दी भी है. महात्मा गांधी का बुनियादी विद्यालय बड़हरवा लखनसेन भी है जो अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है. सत्याग्रह आन्दोलन के दौरान 15 अप्रैल 1917 को धर्म समाज चौक स्थित गोरखबाबू अधिवक्ता के जिस मकान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ठहरे थे, उसकी भी हालत ठीक नहीं है. अंग्रेजी के उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल की जन्म स्थली व इसाईयों का प्राचीन कब्रिस्तान भी हाशिए पर है. जॉर्ज ऑरवेल का जन्म 25 जून 1903 को मोतिहारी स्थित गोपाल साह विद्यालय के छात्रावास में हुआ था. हालांकि तत्कालीन जिलाधिकारी व वर्तमान में तिरहुत प्रमण्डल के आयुक्त नर्मदेश्वर लाल ने इन 66 ऐतिहासिक धरोहरों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग को प्रस्ताव भेजा था. कुल मिलाकर चम्पारण की ऐतिहासिक धरोहरें हाशिए पर हैं और इनकी उपेक्षा का मामला इसबार के चुनाव में राजनेताओं को महंगा साबित हो सकता है. इधर भाकपा नेता अतीक अहमद खां इस बदहाली के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहराते हैं और कहते हैं कि केवल गलत बयानबाजी कर जनता की भावना के साथ खिलवाड़ किया गया है. वे जनता को ठगने का आरोप स्थानीय सांसद व विधायक पर लगाते हैं और कहते हैं कि जितनी घोषणाएं पूर्व में हुई हैं इसका दस फिसदी भी अमल नहीं हुआ है. दूसरी तरफ केसरिया के पूर्व प्रमुख सुमित्रा कुमारी यादव, डॉ. बीके राय, राजद नेता बब्लू गप्ता, नसीमा खातून आदि भाजपा के सासदों पर सीधा निशाना साधते हुए कहते हैं कि ऐतिहासिक धरोहरों को विकसित करने की चिंता न तो सरकार को रही है और न ही यहां के सांसदों को. विभिन्न समारोहों व अवसरों पर केवल बड़ी-बड़ी घोषणाएं की गई हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

किसी के अस्तित्व का सवाल, तो कहीं भितरघात का डर

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सीतामढ़ी व शिवहर जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का काफिला गांव की गलियों में दस्तक दे रहा है. चुनाव आयोग की सख्ती के कारण लोगों को लाउडस्पीकर की कानफाडू आवाज से मुक्ति तो मिल गई है लेकिन नेताओं के दल-बल का सामना अब भी उनकी मजबूरी का अहम हिस्सा बना हुआ है. सुबह से लेकर देर रात तक चकाचक पायजामा व धोती-कुर्ता, बंडी और चश्मा लगाए नेता और कार्यकर्ताओं का दर्शन करना लोगों की फिलहाल दिनचर्या है. इतने के बाद भी इस चुनाव में मतदाता कुछ भी खुलकर बोलने से परहेज कर रहे है. पार्टी कैडर को छोड़ दिया जाए तो आम मतदाताओं में चुनाव के प्रति विशेष रुचि फिलहाल नजर नहीं आ रही है. वैसे चुनाव को लेकर नामांकन होना अभी बाकी है. संभव है नामांकन के साथ ही लोगों पर चुनावी रंग का असर दिखने लगे. जहां तक सीतामढ़ी लोकसभा सीट का सवाल है तो इसको लेकर राजद, भाजपा व लोजपा गठबंधन के अलावा कुछ अन्य दल के प्रत्याशी भी अब चुनावी दंगल में कसरत शुरू कर चुके हैं. राजद व जदयू से यादव जाति के प्रत्याशी होने की वजह से इस बार चुनावी लहर में ठहराव सा दिख रहा है. सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर सर्वाधिक बार कब्जा जमाने वाली यादव बिरादरी को सोचना पड़ रहा है. राजद नेतृत्व से नाराज खेमा भी अपनी नाराजगी में नरमी का संकेत दे रहा है. बताया जाता है कि बात स्थानीय प्रत्याशी सीताराम यादव की नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक अस्तित्व की रक्षा का सवाल है. जहां तक जदयू का सवाल है तो पिछली बार बाजी मार चुके सांसद डॉ. अर्जुन राय को इस बार अपने दल के कई राजनीतिक धुरंधरों के चक्रव्यूह को तोड़ने की सीधी चुनौती है. विधान पार्षद देवेश चंद्र ठाकुर ने ऐन मौके पर जदयू को अलविदा कहते हुए निर्दलीय चुनावी समर मे किला फतह कर जदयू नेतृत्व को एक तरह से धूल चटाने में सफलता पाई है. संभव है कि देवेश के समर्थक लोकसभा चुनाव में जदयू को सबक सिखाने से परहेज नहीं करेंगे. इधर भाजपा-रालोसपा-लोजपा गठबंधन में भी बवाल मचा है. गठबंधन के तहत उपेंद्र कुशवाहा ने कुशवाहा बिरादरी के राम कुमार शर्मा को सीतामढ़ी के समर में उतार दिया है. परंतु उनको रालोसपा के अलावा लोजपा व भाजपा के कार्यकर्ता भी मन से स्वीकार करने से परहेज कर रहे हैं. कयास यह भी लगाया जा रहा है कि भाजपा से बेटिकट पार्टी नेताओं का चुनाव में सहयोग महज एक खानापूर्ति हो सकती है. हालांकि राम कुमार शर्मा ने लगातार क्षेत्र में लोगों के बीच दस्तक देना शुरू कर दिया है. उनके अलावा आम आदमी पार्टी से सामाजिक कार्यकर्ता किशोरी दास तो टीएमसी से डॉ. राजीव रंजन व बसपा से डॉ. महेश कुमार भी चुनावी अखाड़े में कूद चुके हैं. इस बीच राजद के लालू प्रसाद की दूसरी चुनावी सभा पिछले दिनों सीतामढ़ी जिले के परिहार गांधी उच्च विद्यालय के मैदान में हुई. कार्यक्रम में राजद सुप्रीमो ने भाजपा व जदयू को देश बांटने वाला बताया. प्रदेश राजद अध्यक्ष डॉ रामचंद्र पूर्वे, राकांपा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री नवल किशोर शाही, पूर्व मंत्री सूर्यदेव राय, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विमल शुक्ला, उपाध्यक्ष सत्येंद्र तिवारी, सीमा गुप्ता, राजद के मो. शफीक खां, पूर्व विधान पार्षद दिलीप कुमार यादव, मनोज कुमार, तारकेश्वर प्रसाद यादव, दिलीप राय, चंद्रजीत प्रसाद यादव व सन्नी श्रीवास्तव समेत हजारों की मौजूदगी में लालू प्रसाद ने कहा कि यह चुनाव लालटेन व लालू के लिए अहम है. इसके साथ ही राजनीतिक दिशाएं भी बदलने का संकेत आने लगा है. जानकारों की माने तो अब सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर जाति बनाम पार्टी की लडाई तय लगने लगी है. एक ओर सीट के स्वामी रहे यादव जातिगत आधार पर राजद व जदयू में से कोई एक विकल्प पर जीत के लिए विचार कर सकता है, तो दूसरी ओर मतदाता भाजपा-रालोसपा प्रत्याशी को नमो मिशन 2014 का दूत मान कर समर्थन दे सकती है. वैसे अभी तक स्थिति पूर्णत: साफ नहीं हो सकी है. इधर शिवहर लोकसभा सीट पर भी शेर पर सवा शेर वाली कहावत चरितार्थ होती नजर आने लगी है. शिवहर से बतौर राजद-कांग्रेस-राकांपा गठबंधन प्रत्याशी व पूर्व सांसद मो. अनवारुल हक चुनावी अखाड़े में जमे हुए हैं, तो दूसरी ओर रणछोड़ साबित हुए साबिर अली की जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री शाहिद अली खान को जदयू की टिकट पर चुनावी अखाड़ा में भेजा है. दो अल्पसंख्यक सूरमाओं के बीच भाजपा की सांसद रमा देवी चुनाव परिणाम अपने पक्ष में करने को लेकर प्रयासरत हैं. इनके अलावा सपा से पूर्व सांसद लवली आनंद, बसपा से अंगेश कुमार सिंह तो आम आदमी पार्टी से शत्रुघ्न साहू चुनावी वैतरणी पार करने की जुगत कर रहे है. कुल मिला कर सीतामढ़ी एवं शिवहर लोकसभा सीट से प्रत्याशियों ने अपनी राजनीतिक गतिविधि बढ़ा दी है. अभी नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया से लेकर चुनाव के अंतिम क्षण तक परिवर्तन की बयार से इन्कार नहीं किया जा सकता है. हर पल, हर दिन चुनावी फिजां में कुछ न कुछ अदला-बदली का संकेत आम है. वैसे चुनाव की तिथि आगामी 7 मई को निर्धारित की गई है. इस बीच किस दल का कौन प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में कर पाने में सफल होता है, आने वाला समय ही बताएगा.■

सभा को संबोधित करते राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद

अररिया में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार

अजातशत्रु अग्रवाल/संतोष झा

सोलहवीं लोकसभा के लिए अररिया संसदीय क्षेत्र में मतदान 24 अप्रैल को होना है. हर प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में डटा हुआ है. यूपीए, एनडीए और जदयू-भाकपा के प्रत्याशी के अलावा भी कई मैदान में हैं. राजद-कांग्रेस गठबंधन ने अपने प्रत्याशी के रूप में इस सीमावर्ती क्षेत्र के कद्दावर नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री मो. तस्लीमुद्दीन को उतारा है. वहीं जदयू ने मंडल जाति के पूर्व मंत्री विजय कुमार मंडल को तथा भारतीय जनता पार्टी ने अपने निर्वतमान सांसद प्रदीप कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है. जदयू ने बीते लोकसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे जाकिर अनवर वैराग का टिकट अंतिम समय में काटकर विजय मंडल को प्रत्याशी बनाया. इस वजह से मंडल के समर्थक तो उत्साहित हैं लेकिन अनवर के नाराज समर्थकों से प्रत्याशी को नुकसान हो सकता है.

विजय मंडल

तस्लीमुद्दीन

प्रदीप सिंह

जाकिर अनवर

पिछले लोकसभा चुनाव में यहां से तकरीबन दो दर्जन प्रत्याशी मैदान में थे. संभावना है कि इस चुनाव में भी प्रत्याशियों का आंकड़ा इसी के आसपास रहेगा. बहरहाल उम्मीदवारों की संख्या भले ही कितनी भी हो लेकिन मुख्य चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय होने की प्रबल संभावना है. पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एवं लोक जनशक्ति पार्टी के बीच सीधा-सीधा मुकाबला हुआ था जिसमें भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह ने लोजपा के जाकिर अनवर वैराग को करीबन 22 हजार वोटों से शिकस्त दी थी. लेकिन इस चुनाव में जाकिर अनवर के टिकट पर जदयू के विजय मंडल के आने से यह मुकाबला त्रिकाणीय मुकाबले में बदल चुका है. प्रक्षकों की माने तो राजद-कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी की स्थिति काफी मजबूत रहेगी. पिछले पांच लोकसभा चुनावों में विजयी होने वाले पूर्व सांसद सुकदेव पासवान इस बार कांग्रेस-राजद गठबंधन के तहत अपने प्रत्याशी मो. तस्लीमुद्दीन की जीत के लिए एड़ी-चोटी एक किए हुए हैं. पासवान एवं राजद व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अरविंद गोयल के अनुसार पूरे सूबे में अगर राजद की कोई सीट चुनाव से पूर्व पक्की मानी जा सकती है तो वह नाम अररिया संसदीय सीट का ही है. इन नेताओं के अनुसार सीमांचल की सीट में यादव एवं मुस्लिम के वोट थोक में राजद प्रत्याशी को प्राप्त होंगें. वहीं बहुसंख्यक समाज के वोट भाजपा एवं जदयू प्रत्याशियों के बीच में अवश्य रूप से बंटेगें जिसका सीधा-सीधा लाभ राजद प्रत्याशी को प्राप्त होगा.

दूसरी ओर भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर उर्फ बब्बन सिंह, युवा नेता सतीश श्रीवास्तव का कहना है कि पूरे देश में नरेन्द्र मोदी की लहर चल रही है जिससे अररिया संसदीय क्षेत्र भी अछूता नहीं है. भाजपा के पास वोटों की कमी नहीं है जिस कारण भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह दूसरी बार भी भाजपा का परचम इस संसदीय सीट पर लहराएंगे. अररिया के मतदाता नरेन्द्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं. इसके इतर जदयू भी जीत का दावा कर रही है. जदयू के लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे सूबे में अल्पसंख्यकों के लिए इतना कार्य किया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के मत अवश्य रूप से जदयू प्रत्याशी विजय कुमार मंडल को ही प्राप्त होगें. इसके साथ ही मंडल जाति के मतदाताओं की संख्या अररिया संसदीय क्षेत्र में अच्छी खासी है. इस संसदीय क्षेत्र में मंडल और मुसलमान जाति के साथ इस बार पिछड़ी जातियों के मत भी जदयू के पाले में आने वाला है. इसी संभावना के सहारे जीत का दावा कर रहे हैं लोजपा का दामन छोड़ जदयू में आए अररिया विधायक जाकिर अनवर वैराग, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मूलचंद गोलछा व उनके समर्थक. किसका दावा कितना असरदार है यह तो आने वाला वक्त ही बतायेगा. बहरहाल प्रशासन ने भी निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव कराने के लिए अपनी ओर से भरपूर तैयारियां शुरू कर दी हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

अररिया संसदीय क्षेत्र के विजयी सासंदों का ब्योरा

वर्ष	विजयी प्रत्याशी	दल
1962	तुलमोहन राम	कांग्रेस
1967	तुलमोहन राम	कांग्रेस
1971	तुलमोहन राम	कांग्रेस आर
1977	महेन्द्र नारायण सरदार	जनता पार्टी
1980	डुमरलाल बैठा	कांग्रेस
1984	डुमरलाल बैठा	कांग्रेस
1989	सुकदेव पासवान	जनता दल
1991	सुकदेव पासवान	जनता दल
1996	सुकदेव पासवान	जनता दल
1998	रामजीदास ऋषिदेव	भारतीय जनता पार्टी
1999	सुकदेव पासवान	राष्ट्रीय जनता दल
2004	सुकदेव पासवान	भारतीय जनता पार्टी
2009	प्रदीप कुमार सिंह	भारतीय जनता पार्टी

एक नज़र

रिश्वत की मांग

अनुसंधान के नाम पर खानापूर्ति करना और रिश्वत लेना साथ ही फरियादियों को परेशान करना बिहार पुलिस की नियती बन गई है. ऐसा ही एक मामला पूर्वी चम्पारण जिला के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र में देखने को मिला है. प्राप्त जानकारी के अनुसार डुमरिया घाट थाना में दर्ज काण्ड संख्या 128/11 में काण्ड के अभियुक्त व हुसैनी निवासी शत्रुघ्न प्रसाद से थाना के तत्कालीन जमादार उदय शंकर झा ने 30 हजार रुपये रिश्वत मांगी और नहीं देने पर विरोध में डायरी लिख कर डीएसपी को भेज दिया. जब इस की शिकायत शत्रुघ्न प्रसाद ने आईजी से की तो उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए चम्पारण परिक्षेत्र के डीआई को जांच के लिए लिखा. फिर डीआईजी ने मोतिहारी पुलिस निरीक्षक को जांच करने का आदेश दिया. इसके बाद पुलिस निरीक्षक ने इस मामले को डुमरिया घाट थाना प्रभारी को सौंप दिया. थाना प्रभारी ने न्यायालय से इस मामले की पुन: जांच के लिए अनुमति मांगी और न्यायालय ने 18 नवम्बर 2012 को आदेश भी दे दिया किन्तु हैरानी की बात यह है कि आज तक इसकी जांच नही हो सकी. यह मामला सड़क दुर्घटना से जुडा हुआ बताया जाता है. *– मुकुल पाण्डेय*

प्रदेश महासचिव मनोनित

गोगरी अनुमंडल में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा परबत्ता प्रखंड के अध्यक्ष अखिलेश दास को पंचायती राज प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव मनोनित किया है. मनोनयन पर हर्ष व्यक्त करते हुए दूनबहादुर दास ने कहा कि धरती से जुड़े कार्यकर्ता को प्रदेश महासचिव बनाये जाने से पार्टी का विकास संभव होगा. साथ ही साथ विकास में क्रांति आएगी. दास को प्रदेश महासचिव बनाये जाने पर रिंकी देवी, मांगो पंडित, प्रभूनारायण पंडित, सुनील पंडित, मो. मुबारक, मो. सुलेमान, मो. ग्यासइद्दीन, पंकज पासवान, विकास कुमार, नारद यादव, मुखिया प्रतिनिधि मो. आसिफ इकबाल, अनिरूद्ध दास, सिकन्दर दास, मो. कैलाश भारती, विवेकानंद यादव सहित दर्जनों लोगों ने हर्ष व्यक्त किया.

प्रकोष्ठ की बैठक

गोगरी अनुमंडल अन्तर्गत परबत्ता में कांग्रेस अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सह मंत्री मत्स्यजीवी सहयोग समिति सदस्य प्रभुदयाल सहनी ने बताया कि इस लोकसभा चुनाव में गठबंधन के उम्मीदवार कृष्णा कुमारी यादव को अपार बहुमत से विजयी बनाने के लिए कार्य करने का संकल्प लेना होगा. उन्होंने कहा कि नामांकन के बाद पार्टी कार्यकर्ता घर-घर जाकर नरेन्द्र मोदी के लोक लुभावन भाषण के पीछे की सच्चाई बताएंगे. बैठक धनेश्वर चौधरी, नंदलाल मंडल, पंकज कुमार, प्रमोद साह, गुड्डू मंडल, श्रवण साह, पप्पु कुमार निशाद, रघूनंदन सिंह, नीतीश कुमार, राजेन्द्र सहनी, रविन्द्र सिंह, प्रमोद रजक, फिरोज खान सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे.

बिहार दिवस मना

गोगरी अनुमंडल क्षेत्राधीन बिहार दिवस हर्ष और उल्लास पूर्वक मनाया गया. गोगरी अनुमंडल के कई विद्यालय के स्कूली बच्चों ने शहर का भ्रमण किया. मध्य विद्यालय मड़ैया बाजार के छात्राओं ने भी प्रभातफरी निकाली. बच्चे लोकसभा के चुनाव के लिए नारा लगा कर मतदाताओं को जागरूक कर रहे थे. रैली मुख्य मार्ग मड़ैया बाजार, आलम बाजार, से मध्य विद्यालय तक पहुंच कर समाप्त हो गई. मध्य विद्यालय वैसा से भी रैली निकाली गई. रैली में छात्रा की अधिक भीड़ देखी गई. वहीं आदर्श मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक दूनबहादुर दास, प्रधानाध्यापक अमरेन्द्र कुमार सिंह, अमरेन्द्र कुमार अमल, कृष्ण मुरारी, दिलीप कुमार भगत, किरण कुमारी, गीता देवी एवं रियाज अली सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे.

प्रशासन की बैठक

गोगरी अनुमंडल क्षेत्राधीन प्रखंड के ट्रायसेम भवन में एसडीओ जर्नादन कुमार व एसडीपीओ राजेश कुमार ने वहां मौजूद थानाध्यक्षों एवं कर्मियों को आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत पालन करने का निर्देश दिया. एसडीओ ने थाना अध्यक्ष व अन्य अधिकारियों से कहा कि चुनाव का समय है. क्षेत्र में कोई भी प्रत्याशी या इसके समर्थक द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जाए. इस पर सख्त ध्यान देने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. एसडीओ ने थानाध्यक्षों एवं अन्य पुलिस पदाधिकारियों से क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया. साथ ही चुनाव के दौरान इपद्रव फैलाने वालों पर भी कड़ी निगाह रखने की बात कही. मौके पर बीडीओ सुधीर कुमार, सीओ सुनील कुमार सिंह, गोगरी थाना अध्यक्ष दुर्गेश राम, परबत्ता थानाध्यक्ष मुकेश कुमार समेत दर्जनों अधिकारी मौजूद थे.■ *– गीता कुमार*

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE MOULDED FURNITURE
1 YEAR GUARANTY
WINNER OF NATIONAL AWARD
Contact : 9386595926, 9334115955

कैसे हो हड्डियों की सुरक्षा
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
AROFIT
Levohon
ARILINE
MUSTAL
ONDANOK
Ondanesetron 2 mg
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से
विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें 9304291051
किसी भी रोग संबंधी निदान के लिए Dr. Advice पुस्तिका (होमियोपैथिक) निकटतम स्टॉकिस्ट से मुफ्त प्राप्त करें।
REPL द्वारा जनहित में प्रकाशित

Admission Going On For The Session 2014-2015
IQRA INTERNATIONAL SCHOOL (RESIDENTIAL)
C.B.S.E. English Medium
Mathia Zeerat, Motihari - 845401
Nursery to Class X
Silent Features :-
• A successful operation of more than two decades • 15th batches of ClaSs Xth (CBSE) Passed with flying colours • Hostel facility for boys only • Separate classes for boys and girls from class VI onwards • Well-equipped and stocked Science Lab, Computer Lab, Labirary and Sports Library. • Dinyat & Quran are the integral part of school syllabus.
Contact No. : 0625-2230224, 900667015, 8235462345, 8084938676 M. Salam (Principal)

आपका शानदार घर बर्बाद ना हो !
घर बनाने से पहले आइये कुछ महत्वपूर्ण बातें जानें
* क्या आप जानतें हैं बिल्डिंग मेटेरियल्स पर करीब 28 से 30 परसेन्ट टैक्स लगा रहता है। सभी अच्छी कम्पनी का सामान का वैट बिल लेने पर आपको कोई टैक्स देना नही पड़ता है। सभी अच्छी कम्पनियां सभी टैक्स पेड माल अपने डीलर या रिटेलर को सप्लाई करती है।
* आप अपना घर बनाने में अगर 25 लाख खर्च करते हैं तो उस पर करीब 7 लाख टैक्स भारत सरकार एवं राज्य सरकार को मिलता है। जो वापस आपके लिए ही सरकार खर्च करती है।
* आप बिल्डिंग मेटेरियल्स खरीदते समय वैट बिल नही लेते हैं तो आपका रुपया तो जाता ही है, आपको नकली सामान भी मिलता है, जैसे आप 20 किलो का वॉल पुटटी जिस पर कीमत रु0. 800 लिखा है उस पर कम्पनी रु0.69 एक्साईज डयूटी एवं वैट 96 रुपया टोटल 165 रु0 टैक्स कम्पनी लिए हुए रहती है। परन्तु आपके छोटी सी भूल से आप बिना वैट बिल का नकली सामान खरीद लेते हैं। जिससे जिस सामान की लाईफ 10 साल होनी चाहिए वह सामान साल भर में ही खराब होने लगता है। अपने शानदार घर को बर्बादी से बचाने के लिए सभी सामान का वैट बिल अवश्य ले लें। आपकी सावधानी से आपके घर की लाईफ कई गुणा बढ़ जायेगी।
वॉल पुटटी के बारे में जानिए
वॉल पुटटी के बोरी में अधिकतर कम्पनियां रुपये का कूपन डालती है जांच करें बिना वैट बिल का वॉल पुटटी नकली हो सकता है, जिसमें केमिकल की सही मात्रा नही होती है, जबकि असली वॉलपुटटी में केमिकल 200 से 450 रुपये किलो का लगता है, एक बोरी ऑरिजीनल वाल पुटटी पर करीबन 200 रुपये टैक्स लगा रहता है जो सभी कम्पनी को देना होता है लेकिन नकली माल बनाने बाले टैक्स बचा लेते हैं, लेकिन आपसे पूरा कीमत वसूल लेते हैं। आपकी जरा सी सावधानी से वैट बिल के साथ खरीदारी पर आप हमेशा असली सामान ही खरीदेगें।
राजस्थान के चुनिन्दा जिप्सम से बना बेहतरीन क्वालिटी का
ईटालियन व्हाईट प्लास्टर ऑफ पेरिस
प्लास्टर ऑफ पेरिस
* प्लास्टर ऑफ पेरिस खरीदते समय बोरी का वजन जरुर चेक करें, क्योंकि साधरण प्लास्टर ऑफ पेरिस 20 किलो के बोरी में 16 किलो ही आता है, बिना वैट बिल का प्लास्टर ऑफ पेरिस में मिटटी मिला हो सकता है। जिससे आपके फाल्स सिलींग या पी0 ओ0 पी0 का काम साधारण क्वालिटी का होगा।।।।।
* प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपके पूरे घर की सुन्दर पेन्टिंग का बेस होता है, अगर वही साधारण क्वालिटी का होगा तो आपके कीमती पेन्टिंग का भविश्य क्या होगा आप खुद सोचिये ।।।।
ईटालियन ईन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड का ईटालियन व्हाईट प्लास्टर ऑफ पेरिस साधारण पेरिस की अपेक्षा आपके दीवारों एवं मकानों को ज्यादा सुन्दर बनाता है ईटालियन व्हाईट प्लास्टर ऑफ पेरिस ज्यादा बारीक होने के कारण यह ज्यादा फैलता है, कड़े क्वालिटी कन्ट्रोल में बना हुआ सुपर स्ट्रौंग, सुपर स्ट्रैंथ एवं सुपर कवरेज वाला भारत का सबसे बेहतरीन ईटालियन व्हाईट प्लास्टर ऑफ पेरिस।
Made from Imported Chemicals
ITALIAN Beauty Wall Putty
ईम्पोंटेड केमिकल से तैयार क्वालिटी एवं पैकिंग में भारत का नं0 1 वॉल पुटटी
सबसे किफायती 40 किलो पैक
डीलरशिप/ डिस्ट्रीब्यूटरशिप
अपने फर्म का नाम पूरा पता एवं वैट नं० के साथ एस.एम.एस या मेल करें
Mob·09549663640 E-mail· shalimarpop@gmail·com *शर्तें लागू
प्रिय ग्राहक कृपया ध्यान दें
हमारी कम्पनी सभी सामान टैक्स पेड देती है, आपको अलग से कोई टैक्स नही देना है, ऑरिजीनल सामान के लिए वैट बिल अवश्य ले लें तभी आप 1 किलो सोना के लक्की ड्रा स्कीम में शामिल हो सकते हैं।
लक्की ड्रॉ में 1 किलो 24 कैरेट सोना
24 कैरेट 10 ग्राम सोने का 100 सिक्का
www.iiplindia.com
अपने देश हित में, अपने राज्य हित में वैट बिल अवश्य लें
वैट बिल लेना आपका अधिकार है, ओरिजीनल सामान की पहचान है।

कुछ महीने पूर्व गया जिले के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से दो लोगों को अगवा कर माओवादियों ने हत्या कर दी थी. दोनों पर पुलिस मुखबिरी का आरोप था. बाराचट्टी विस क्षेत्र से भी संजय यादव का अपहरण कर माओवादियों ने इसकी हत्या कर दी थी.

अपनों की नाराजगी पड़ेगी भारी

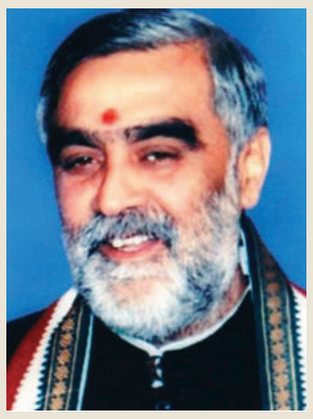

भाजपा इस बार टिकट के लिए अंतर्कलह से जूझ रही थी. इस कारण भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने पिछले चुनाव में लगभग दो हजार मतों से चुनाव हारने वाले लालमुनि चौबे का टिकट काटकर कद्दावर नेता अश्विनी चौबे को टिकट दे दिया. पार्टी नेतृत्व ने यह निर्णय लेकर भले ही अंदरूनी खींचतान को कम करने की कोशिश की हो लेकिन स्थानीय और बाहरी का विवाद अभी भी कम नहीं हुआ है. पार्टी के पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विशेश्वर ओझा ने शाहाबाद प्रखंड की चार में से तीन सीटों पर सिर्फ बाहरी प्रत्याशियों को थोपने का आरोप लगाया है.

जयमंगल पांडेय

बक्सर का लोकसभा चुनाव इस बार कई मायने में दिलचस्प होने वाला है. दल बदलकर कुछ नए रंगरूट मैदान में आ गए हैं तो कुछ पुराने खिलाड़ियों को ही मैदान में उतारा गया है. विभिन्न दलों के प्रत्याशियों को लेकर कहीं नाराजगी है तो कहीं प्रत्याशी खुद आवंटित उम्मीदवारी से खुश नहीं हैं.

बहरहाल, आपसी गुटबंदी तथा खींचतान के बाद भाजपा ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे को अपना प्रत्याशी बनाकर एक साथ कई लोगों को साधने का काम किया है. राजद प्रत्याशी जगदानंद सिंह को छोड़ बसपा तथा जदयू के प्रत्याशी इस बार नए अवतार में ताल ठोंक रहे हैं. वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में चतुष्कोणीय मुकाबले में राजद की जीत हुई थी. इस बार की जंग भी उसी तर्ज पर होगी लेकिन सामाजिक तथा राजनीतिक जैसे सभी कारणों को नए सिरे से बनाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है. पिछले चुनाव में भाजपा के लाल मुनी चौबे, राजद के जगदानंद सिंह, बसपा से श्यामलाल कुशवाहा तथा निर्दलिय ददन यादव के बीच चतुष्कोणीय लड़ाई हुई थी और मात्र एक प्रतिशत के मतों के अंतर पर जीत हार का फैसला हुआ था. भाजपा इस बार टिकट के लिए अंतर्कलह से जूझ रही थी. इस कारण भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने पिछले चुनाव में लगभग दो हजार मतों से चुनाव हारने वाले लालमुनि चौबे का टिकट काटकर कद्दावर नेता अश्विनी चौबे को टिकट दे दिया. पार्टी नेतृत्व ने यह निर्णय लेकर भले ही अंदरूनी खींचतान को कम करने की कोशिश की हो लेकिन स्थानीय और बाहरी का विवाद अभी भी कम नहीं हुआ है. पार्टी के पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विशेश्वर ओझा ने शाहाबाद प्रखंड की चार में से तीन सीटों पर सिर्फ बाहरी प्रत्याशियों को थोपने का आरोप लगाया है. टिकट के प्रबल दावेदार ओझा ने पार्टी के पद से त्याग पत्र भी दे दिया. दूसरी ओर शिवानंद तिवारी के इन्कार के बाद जदयू को कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं मिला. क्षेत्र में लंबे अरसे से सक्रिय विधान पार्षद हुलास पांडेय की भी उम्मीदों पर पानी फिर जाने से नाराज चल रहे हैं. पिछले चुनाव में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले श्यामलाल कुशवाहा को भाजपा से बुलाकर बक्सर से जदयू का टिकट थमा दिया गया. कुशवाहा हर चुनाव में दलबदल के लिए खासे चर्चित रहे हैं. राजद के टिकट पर विधानसभा में भी हार का स्वाद चख चुके हैं. वहीं पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ कर 122975 मत लाने वाले ददन पहलवान इस बार बक्सर से हाथी की सवारी कर रहे हैं. बसपा द्वारा एक साल पूर्व प्रत्याशी घोषित कर दिए जाने के बाद से वे लगातार अपनी मुहिम में सक्रिय हैं. राजद प्रत्याशी व वर्तमान सांसद जगदानंद सिंह के लिए सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है. ददन अकेले दम पर बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं और इस बार बसपा के वोट भी उनके साथ रहेंगे. साथ ही यह तो माना ही जा रहा है कि ददन के मैदान में होने की वजह से यादव वोटों का बंटवारा भी तय है और कभी उनके चहेते तथा ब्रह्मपुर के पूर्व राजद विधायक अजीत चौधरी व वर्तमान सांसद जगदानंद सिंह के बीच कटु रिश्ते जगजाहिर हो गए हैं. इस माहौल को भांप कर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने बक्सर के सिकरौल में पहली चुनावी सभा कर दोनों नेताओं को एक मंच पर लाकर मतभेदों को पाटने की कोशिश तो काफी की लेकिन सबकुछ ठीकठाक हो गया है, फिलहाल ऐसा दिख नहीं रहा है. पहली बार ऐसा हुआ है कि दो पार्टियों ने बक्सर में महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है. भाकपा (माले) ने इंदू देवी तथा आम आदमी पार्टी ने श्वेता पाठक को प्रत्याशी बनाया है. सपा के टिकट पर राज रौशन यादव मैदान में हैं. छह विधानसभा वाले बक्सर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में इस बार कुल 159347 मतदाता हैं, जिसमें 849562 पुरुष तथा 743444 महिलाएं हैं. कुल 1542 बूथों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा.■

नक्सलियों के निशाने पर मगध

सुनील सौरभ

feedback@chauthiduniya.com

सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाली मगध की धरती चुनाव आते ही खौफजदा हो जाती है. कब, कौन और कहां गोलियों का शिकार बन जाये, कहा नहीं जा सकता. ग्रामीण क्षेत्र, जो नक्सलियों का सेफ जोन माना जाता है, की जनता की जान सांसत में रहती है. एक ओर नक्सलियों का खौफ, तो दूसरी ओर पुलिस कार्रवाई का डर. अमूमन, चुनाव में पुलिस और नक्सलियों के बीच चूहे-बिल्ली का खेल चलते रहता है, क्योंकि बंदूक की नली से सत्ता की राह बताने के सिद्धांत पर चलने वाले अधिकतर नक्सली संगठन अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र में वोट बहिष्कार की घोषणा कर प्रत्याशियों एवं मतदाताओं में खौफ पैदा करने का प्रयास करते हैं, तो वहीं पुलिस शांतिपूर्ण मतदान कराने की जुगत में रहती है. ऐसे में लाजमी है दोनों में टकराहट। टकराहट की आग में क्षेत्र का जलना स्वभाविक है.

झारखंड की सीमा से लगे बिहार के मगध का ग्रामीण क्षेत्र नक्सली संगठनों का सेफजोन है. पिछले कई चुनावों में चुनाव प्रचार, मतदान तथा मतदान के बाद नक्सली संगठनों ने कई हिंसक वारदातों को अंजाम देकर अपने मंसूबों में कामयाब हुआ है. 2005 के विधानसभा चुनाव में इमामगंज विस के लोजपा प्रत्याशी व पूर्व सांसद राजेश कुमार की हत्या नक्सलियों ने चुनाव प्रचार के दौरान कर दी थी. पूर्व सांसद के साथ इनके समर्थक भी मारे गये थे. जीप जला डाला गया था. यह तो हाल की घटना है. वर्ष 1991 में निवर्तमान सांसद ईश्वर चौधरी भी नक्सलियों की गोलियों के शिकार बने थे. इस बार भी भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व पर नक्सली अपने प्रभाव क्षेत्र में अपनी धमक से प्रत्याशियों, मतदाताओं तथा सुरक्षा बलों में दहशत पैदा करने का प्रयास निश्चित तौर पर करेंगे. नक्सलियों ने बिहार झारखंड के दो दर्जन से अधिक राजनीतिक दल के नेताओं को टारगेट में लिया है. खुफिया रिपोर्ट के अनुसार नक्सली चुनाव के दौरान इन नेताओं पर कार्रवाई कर हिंसक घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं. ऐसा खुफिया विभाग का मानना है.

गत दिनों मगध प्रमंडल के औरंगाबाद जिले में बड़े पैमाने पर विस्फोटक, केन बम बनाने के सामान तथा सीरियल ब्लास्ट करने की सामग्री की बरामदगी के बाद पुलिस ने खुलासा किया कि चुनाव में नक्सली संगठन द्वारा इन विस्फोटक सामग्री का इपयोग किया जा सकता था। कुछ महीने पूर्व गया जिले के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से दो लोगों को अगवा कर माओवादियों ने हत्या कर दी थी. दोनों पर पुलिस मुखबिरी का आरोप था. बाराचट्टी विस क्षेत्र से भी संजय यादव का अपहरण कर माओवादियों ने इसकी हत्या कर दी थी. आरोप था पुलिस के लिए खुफियागिरी कर चतरा में दर्जन भर माओवादी नेताओं को मरवाने का. हाल ही में औरंगाबाद के दबंग और माओवादियों के विरोधी माने जाने वाले सुशील पांडेय समेत आधे दर्जन लोगों की हत्या माओवादियों ने इनके गांव के निकट लैंडमाइंस लगाकर कर दी थी. इन सबके अलावा झारखंड की सीमा से लगे गया जिले के जंगली क्षेत्रों में माओवादियों और पुलिस मुठभेड़ में गत एक साल में कई सुरक्षाकर्मियों की जानें जा चुकी हैं. ये सब तो रही हाल की घटनाएं, लेकिन चुनाव के समय माओवादियों की सक्रियता इसी तरह बढ़ जाती है, जिस प्रकार सुरक्षा बल हिंसा को रोकने के लिए सक्रिय रहते हैं. मगध प्रमंडल में 26 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो पांच लोकसभा क्षेत्र. गया (अजा), औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा और काराकाट संसदीय क्षेत्र की अधिकतर विधानसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित हैं. मगध प्रमंडल के पांच लोकसभा के अंतर्गत आने वाले 26 विधानसभा क्षेत्रों में से गया के इमामगंज, बाराचट्टी, शेरघाटी, गुरुआ, टिकारी, बोधगया व अतरी, नवादा के गोविंदपुर व रजौली, जहानाबाद के मखदुमपुर, अरवल के अरवल व कुर्था तथा औरंगाबाद के गोह, रफीगंज, नवीनगर व कुटुम्बा विधानसभा क्षेत्र नक्सलियों की जद में है.

चुनाव घोषणा के बाद खुफिया विभाग ने राज्य सरकार को सतर्क करते हुए कहा है कि नक्सली अपने आधार क्षेत्र में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी में है. चुनाव में हिंसक घटनाओं को अंजाम देने के लिए प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा (माओवादी) के केंद्रीय कमेटी एवं केंद्रीय मिलिट्री कमिशन के सदस्य अरविंद कुमार सिंह इर्फ देव, बिहार झारखंड इत्तरी छतीसगढ़ स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य विजय यादव इर्फ संदीप, माओवादी मिलिट्री ऑपरेशन का सदस्य शिवशंकर धोबी इर्फ त्यागी इर्फ बाबा, झारखंड रिजनल कमेटी सह स्पेशल एरिया मिलिट्री कमिशन सदस्य प्रवेश दा इर्फ अनुज दा उर्फ अमलेश दा, मगध जोन का सचिव सह चाल्हो सब जोनल प्रभारी कैल प्रजापति इर्फ सत्य नारायण प्रजापति, बिहार रिजनल कमेटी के मध्य जोन के सचिव विनय यादव इर्फ मुराद जी इर्फ गुरु जी का दस्ता लगा है.

खुफिया विभाग ने राज्य सरकार के संबंधित विभाग को रिपोर्ट सौंपकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान व चुनाव के दरम्यान सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की सलाह दी है. खुफिया विभाग की रिपोर्ट पर ही निर्वाचन आयोग ने नक्सली क्षेत्रों के संबंध में मगध प्रमंडल के सभी पांच जिलों के जिलाधिकारियों से मतदान तथा पोलिंग पार्टी को मतदान कराकर सुरक्षित लौट आने के लिए सुझाव की मांग की थी. जिला प्रशासन की सलाह पर नक्सली क्षेत्रों में अपराहन चार बजे तक ही मतदान कराने का निर्देश चुनाव आयोग ने सभी नक्सल प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को दिया है.■

सुशासन के विधायक की दादागिरी

बेगूसराय जिले के केशावे गांव निवासी मटिहानी विधायक नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह एवं कांग्रेस यादव के बीच वर्षों से जमीनी विवाद चल रहा है. उक्त विवादित जमीन मुफस्सिल थाना के सहायक थाना सिंघौल के क्षेत्राधिकार में राष्ट्रीय राजमार्ग-31 के किनारे केशावे-अमरौर-सुशील नगर के अंग्रेजी ढाला के पास स्थित है. विधायक बोगो सिंह अपने आदमियों के साथ इस जमीन पर घेराबंदी करा रहे थे.

सुरेश चौहान/रघुवीर झा

एक ओर देशवासी लोकतंत्र के महापर्व को सम्पन्न कराने में जुटे हैं. वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ दल जदयू के मटिहानी विधायक नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह नियम-कानून की अवहेलना करने पर तुले हैं. जनहित के प्रश्न पर अपनी ही सरकार के प्रशासनिक तंत्र के खिलाफ धरना, प्रदर्शन, अनशन कर आवाज उठानेवाले विधायक अचानक जनविरोधी कदम उठाने के कारण चर्चा का विषय बन गए हैं. यदि जनहित के सवाल पर नियम-कानून की अनदेखी करते तो एक बात होती. लेकिन यहां तो निजी स्वार्थ के वशीभूत होकर उन्होनें यह कदम उठाया जिसके कारण जेल की हवा भी खानी पड़ी. मटिहानी विधायक बोगो सिंह के लिए यह कोई नई बात नहीं है. पूर्व में भी इसी मुद्दे को लेकर बोगो ऐसी हरकत कर चुके हैं. प्रशासन ने कानून की रक्षा के लिए जो कदम अभी उठाया है यदि पूर्व की घटना के समय ही उठाता तो आज पुलिस थाने पर पथराव, पुलिस द्वारा हवा में फायरिंग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-31 कुरुक्षेत्र का मैदान बनने से बच जाता और सामाजिक सौहार्द कायम रहता.

बेगूसराय जिले के केशावे गांव निवासी मटिहानी विधायक नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह एवं कांग्रेस यादव के बीच वर्षों से जमीनी विवाद चल रहा है. उक्त विवादित जमीन मुफस्सिल थाना के सहायक थाना सिंघौल के क्षेत्राधिकार में राष्ट्रीय राजमार्ग-31 के किनारे के शावे-अमरौर-सुशील नगर के अंग्रेजी ढाला के पास स्थित है. विधायक बोगो सिंह अपने आदमियों के साथ इस जमीन पर घेराबंदी करा रहे थे. इसी समय कांग्रेस यादव ने अपने परिजन एवं समर्थकों के साथ आकर घेराबंदी का विरोध किया. दोनों पक्षों में तकरार हुई, विवाद बढ़ा और पत्थरबाजी की नौबत आ गई. सूचना पाकर सिंघौल प्रभारी राघवेन्द्र प्रताप पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे. उग्र भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव कर उसे भगा दिया और राष्ट्रीय राज मार्ग पर जाम लगाकर विधायक के खिलाफ नारेबाजी करने लगी. पुलिस ने घटना की सूचना डीएम, एसपी को दी. डीएम मनोज कुमार, एसपी हरप्रीत कौर, सदर डीएसपी राजकिशोर सिंह काफी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे. लेकिन उग्र भीड़ नियंत्रण से बाहर थी. अंतत: पुलिस ने हवाई फायरिंग कर भीड़ को तितर-बितर किया. विधायक नरेन्द्र कुमार सिंह तथा कांग्रेस यादव को गिरफ्तार कर लिया. इस घटना में कई लोग घायल हुए. सदर अंचलाधिकारी निरंजन कुमार द्वारा इस घटना की प्राथमिकी मुफसिल थाना में दर्ज कराई गई. वहीं दोनों पक्षों की ओर से भी एक दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर दोनों पक्षों के नामजद के विरूद्ध आगे की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

14 अप्रैल–20 अप्रैल 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश– उत्तराखंड

पूर्वांचल में मतदाताओं का मिजाज पढ़ना आसान नहीं

डॉ. दशरथ प्रसाद यादव

यह चुनाव का समय है. इसमें मीडिया बोलता है, अखबार बोलते हैं, सरकार बोलती है, लेकिन जनता नहीं बोलती है. वह अपने वोटों से ऐसी चोट करती है कि नेताओं के सारे कयास–पूर्वानुमान धरे के धरे रह जाते हैं. देश के उत्तर–पश्चिम राज्यों में मोदी लहर के बीच पूर्वांचल का इलाके की जनता की चुप्पी ने नेताओं की पेशानी पर बल ला दिया है.

आज का मतदाता बोलता भले ही न हो, लेकिन पहले की अपेक्षा राजनीतिक रूप से अधिक जागरूक है.यही वजह है कि यह चुनाव उनके लिए आसान नहीं रहने वाला है. जनता काम न करने वाले नेताओं पर सवाल उठा रही है. उनसे पिछले पांच वर्षों का लेखाजोखा मांग रही है. मौजूदा चुनावी माहौल में विभिन्न दलों के नेता जिस तरह से विचार के साथ–साथ पाला बदल रहे हैं, उस पर भी जनता की नजर है. किसी ऐसे नेता का नाम नहीं आ रहा है, जिसे गोरखपुर, बस्ती मंडल के लोग सीधे जीतने वाला प्रत्याशी मानकर वोट दें. पूर्वांचल में यही परिदृश्य है. राजनीतिक माहौल में यदि देखा जाए, तो बलिया से बस्ती तक गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ सबसे प्रबल दिखते हैं, जबकि बलिया में पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर, पडरौना में पूर्व मंत्री राजा पडरौना सीपीएन सिंह के पुत्र आरपीएन सिंह इसमें दूसरे विजेता के रूप में जनता के बीच उभर रहे हैं.

वहीं, सलेमपुर से कांटे की टक्कर में बसपा के पप्पू, बस्ती में बसपा के राम प्रसाद चौधरी, सपा के बृज किशोर सिंह डिम्पल का कद विजेताओं के क्रम में तीसरे चयन के रूप में उभर रहा है. अन्य क्षेत्रों में किसी की बढ़त सीधी दिख नहीं रही है. किसी को अपने क्षेत्रीय मतदाताओं पर, तो किसी को जातीय मतदाताओं पर भरोसा है. किसी को लहर की जरूरत महसूस हो रही है. लेकिन, इन सब बातों से अलग मतदाता के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, इसे पढ़ पाना आसान नहीं है. आम मतदाता बहस में न पड़कर अपने मन के नेता को चुनने का विकल्प देता नजर आ रहा है. बस्ती मण्डल के डुमरियागंज में तो सपा को छोड़ अन्य दलों में दूसरे दल से आए नेताओं पर ही भरोसा बना रखा है. जगदम्बिका पाल कांग्रेस से भाजपा में आए, तो भाजपा विधायक जयप्रताप सिंह (बॉसी) की पत्नी वसुन्धरा कुमारी को कांग्रेस ने उतार दिया और पूर्व में घोषित पटेल बिरादरी के प्रत्याशी को चन्दौली भेज दिया. वहीं, पूर्व में कांग्रेसी रहे मो मुकीम को बसपा ने फिर पार्टी में शामिल कर कमान थमा दी है. यहां विधानसभा अध्यक्ष माताप्रसाद पाण्डेय सपा प्रत्याशी हैं. इनके प्रचार के लिए बलराम यादव सहित अन्य सपा नेता सक्रिय हैं. वहीं, जिप्पी तिवारी, रामपाल सिंह सहित राजा जयप्रताप सिंह का विरोध प्रबल है. बसपा प्रत्याशी को आप एवं पीस पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशियों के मैदान में होने से नुकसान होता दिख रहा है.

सन्तकबीर नगर संसदीय क्षेत्र में बसपा के कुशल तिवारी की स्थिति कम नहीं आंकी जा सकती, लेकिन भालचन्द्र सपा को यादव–मुस्लिम एवं अन्य पिछड़ी जातियों का वोट मिलने से लाभ होगा. कांग्रेस एवं भाजपा के प्रत्याशी ब्राह्मण होने के नाते भी एक दूसरे का वोट बांटते नजर आ सकते हैं. वैसे भाजपा ने अभी खबर लिखने तक अपने प्रत्याशी का फैसला नहीं किया था, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी के पुत्र इस बार भी प्रत्याशी हो सकते हैं. पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉ अयूब के डुमरियागंज चले जाने से मुस्लिम मतदाता का ध्रुवीकरण हो सकता है, लेकिन आप पार्टी ने भी यहां मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा किया है. हालांकि, इनका यहां खास प्रभाव नहीं दिखता है.

बस्ती, कांग्रेस प्रत्याशी विधायक संजय जयसवाल पर अब तो 376 का मामला बन जाने पर इनकी छवि थोड़ी खराब ही हो रही है. वैसे जयसवाल का मानना है कि उन्हें बदनाम करने की राजनीतिक साजिश की गई है. भाजपा को युवा प्रत्याशी हरीश द्विवेदी पर भरोसा है. द्विवेदी भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं. अगर भीतरघात न हो तो इनको परम्परागत वोट अवश्य मिलेगें. शहरी क्षेत्रों में व्यापारी वर्ग इस बार एक होकर वोट देने की स्थिति में नहीं दिखता है. भाजपा के प्रति रूझान, जातीय समीकरण भाजपा के पक्ष में हैं, वहीं इसका लाभ कांग्रेस प्रत्याशी को भी मिलेगा. यही नहीं सपा के प्रत्याशी डिम्पल के भाई कबीना मंत्री राज किशोर सिंह के व्यापारियों से अच्छे सम्बन्ध होने का लाभ भी सपा को मिल सकता है. बसपा के लिए यहां चुनौती काफी बड़ी है. बहन जी का नाम लेकर अनुसूचित जाति के लोग यह कहते हुए गुरेज नहीं कर रहे हैं कि मुलायम सिंह को नहीं जितना है और यह मामला केन्द्र का है. यदि बसपा नहीं जीतने की स्थिति में हो तो भाजपा के प्रति स्थानीय स्तर पर सहयोग किया जा सकता है. सच्चाई यह है कि बसपाई, सपाई एवं भाजपाई वोट भले न करें, लेकिन दूसरी पार्टी को वोट कर दे यह सम्भव नहीं दिखता है. बसपा प्रत्याशी राम प्रसाद चौधरी निवर्तमान सांसद अरविन्द चौधरी के चाचा हैं और अरविन्द चौधरी पिछले चुनाव में एक लाख से अधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशियों सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव जैसे तेरह प्रत्याशियों में एक रहे हैं. यह भारी अन्तर यहां बस्ती में सब पर भारी पड़ सकता है.

गोरखपुर मण्डल में देवरिया में जिस तरह भाजपा का अन्त:कलह कलराज मिश्र को घेरे हुए है, इससे निकल पाना काफी मुश्किल लग रहा है. वहीं, सपा प्रत्याशी को बेहतर स्थिति में होने के बावजूद मोहन सिंह जैसे जुझारू नेता के न होने का दु:ख तो झेलना ही पड़ रहा है. कांग्रेस एवं बसपा परम्परागत ढंग से मैदान में हैं. सलेमपुर में कुशवाहा, क्षत्रिय की लड़ाई में बसपा के रविशंकर सिंह पप्पू मजबूत हैं, क्योंकि भोला पाण्डेय कांग्रेस सहित सपा के मास्टर जी के ख़िलाफ़ रवीन्द्र कुशवाहा ने भी बिगुल बजाकर भाजपा की ओर से चुनौती दी हैं. वैसे भी बलिया का क्षेत्र सलेमपुर में होने के नाते पप्पू को लाभ हो सकता है.

पड़रौना में कांग्रेस अपनी छवि के अनुरूप संघर्ष में है, लेकिन राधेश्याम सिंह सहित अन्य नेताओं को यहां काफी मशक्कत करने की जरूरत है. महराजगंज में अखिलेश सिंह सपा, पंकज चौधरी भाजपा, के बीच बसपा एवं कांग्रेस के प्रत्याशी दौड़ में भागते नजर आ रहे हैं. यहां अन्तिम दौर में 12 मई को मतदान होगा. गोरखपुर एवं बांसगांव में सीधी लड़ाई में योगी आदित्यनाथ आगे नजर आ रहे हैं. क्षेत्रीय नेताओं में भाजपा नेतृत्व को सीधे चुनौती न दे पाने के कारण कांग्रेस बसपा और सपा को परम्परागत वोटों पर भरोसा करना पड़ रहा है.

आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव की उम्मीदवारी को लेकर इन क्षेत्रों में भी हलचल एवं सुगबुगाहट बढ़ी है और अयोध्या को छोड़कर जिस भाजपा ने नरेन्द्र मोदी को वाराणसी से उतारा इनके इस दांव को रोकने के लिए सपा का यह प्रयास काफी कारगर लगने लगा है. क्योंकि जो लोग लहर एवं मीडिया हाइप के नाम पर मोदी के पक्षधर दिख रहे थे, उन्हें भी दोबारा सोचने पर बाध्य होना पड़ रहा है. वैसे अभी भी बस्ती एवं महराजगंज में प्रत्याशियों के बदले जाने की खबरे मिल रही हैं.

प्रशासनिक फेरबदल में जहां सिद्धार्थनगर के एसपी को फिर लाया गया. वहीं महराजगंज एवं देवरिया में भी पुराने जिलाधिकारियों को चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है. ■

feedback@chauthiduniya.com

मोदी की हसरतों को अमेठी में उड़ान देंगी स्मृति

अजय कुमार

कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के अघोषित दावेदार राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में लगातार घिरते जा रहे हैं. आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास पहले ही यहां ताल ठोक चुके हैं. भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी से अपनी तेजतर्रार नेता और टीवी कलाकार स्मृति ईरानी को मैदान में उतार कर राहुल की मुश्किलें और भी बढ़ा दी है. भाजपा ने मैराथन मंथन के बाद स्मृति को अमेठी का टिकट थमाया, तो चर्चा इस बात की भी शुरू हो गई कि क्या राहुल को मोदी के इशारे पर घेरा जा रहा है. राहुल गांधी लगातार मोदी को निशाने पर ले रहे थे. इनकी छवि छूमिल करने का कोई भी मौका छोड़ नहीं रहे थे. यह बात मोदी की टीम को अच्छी नहीं लग रही थी. इसीलिए राहुल को इनके ही घर में घेरने की रणनीति बनाई गई. भाजपा के भीतर स्मृति ईरानी की गिनती मोदी की करीबी नेताओं में होती है.

बहरहाल, स्मृति को मैदान में उतारने से भाजपा को दो फायदे हुए. एक तो आम आदमी पार्टी के मुंह पर ताला लग गया, जो भाजपा–कांग्रेस की मिलीभगत की बात लगातार कह रहे थे. दूसरे, राहुल के खिलाफ कुमार विश्वास को जो मीडिया कवरेज मिल रही थी, इस पर अर्धविराम लग गया. आप नेता अमेठी की लड़ाई को पूरे प्रदेश में प्रचारित–प्रसारित कर रहे थे.

राहुल के खिलाफ अन्य कोई मजबूत दावेदार नहीं होने के कारण विश्वास मीडिया के भी चहेते बन गए थे, लेकिन जैसे ही स्मृति ईरानी मैदान में कूदीं 'आप' नेताओं के साथ–साथ कुमार

विश्वास का भी विश्वास हिल गया. इनकी तत्काल प्रतिक्रिया यही थी कि भाजपा ने स्मृति को मैदान में उतार कर राहुल की जीत सुनिश्चित कर दी है. दोनों दल मिले हुए हैं.विश्वास का इशारा यही था कि स्मृति के आने से राहुल के खिलाफ वोट बंट जाएंगे. लेकिन, इस वजह को आधार बनाया जाए, तो फिर तो कोई कहीं से चुनाव ही नहीं लड़ेगा. भाजपा नेत्री अपने प्रयासों से अमेठी में युवा व महिला मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हैं. स्मृति ईरानी ने टीवी धारावाहिक 'क्यों की सास भी कभी बहू थी' में आर्दश बहू तुलसी का किरदार निभाया था. कहना गलत न होगा कि एकता कपूर का उक्त सीरियल टीवी के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था. बात स्मृति की अगर करें, तो वह मोदी की करीबी हैं. हो सकता है अमेठी में चुनाव प्रचार के लिऐ मोदी भी आएं, अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही यह सियासत की नई इबारत लिखने जैसा होगा. स्मृति ईरानी पिछले दो लोकसभा दिल्ली से लड़ चुकी हैं, लेकिन इन्हें जीत नहीं हासिल हुई. वर्तमान में स्मृति राज्यसभा की सदस्य हैं. अमेठी में स्मृति जीत जाती हैं, तो इनका कद एकदम से बढ़ जाएगा और हारेंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वैसी भी अमेठी नेहरू–गांधी परिवार का अभेद्य दुर्ग है.पंडित जवाहर लाल नेहरू, संजय गांधी, सोनिया गांधी के हाथों से होते हुए अमेठी की कमान आजकल राहुल गांधी के हाथों में है. राहुल के खिलाफ भाजपा ने दिग्गज नेत्री को मैदान में उतार कर कांग्रेस को भी चुनौती दे दी है.अब कांग्रेस को वाराणसी में मोदी के खिलाफ अपना प्रत्याशी तय करने के बारे में नए सिरे से सोचना पड़ सकता है.

अमेठी में तो भाजपा राहुल गांधी को घेरने में सफल रही, लेकिन पार्टी रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिये साध्वी उमा भारती को नहीं मना पाई. बीजेपी राहुल के साथ–साथ सोनिया गांधी को भी इनके संसदीय क्षेत्र में घेरे रखना चाहती थी. उमा भारती ने सोनिया की बजाय झांसी से कांग्रेस सांसद और केन्द्रीय ग्रामीण राज्य विकास राज्य मंत्री प्रदीप कुमार जैन 'आदित्य' जैन को ही टक्कर देने का फैसला लिया है. रायबरेली से उमा की इंकार के बाद भाजपा आलाकमान ने किसी बड़े नेता पर दांव लगाने की बजाय स्थानीय नेता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय अग्रवाल को उम्मीदवार बना दिया.अजय की छवि सोनिया की तरह चमकदार भले नहीं हो, लेकिन पिछले कुछ समय में इन्होंने अपने लिए राजनैतिक जमीन जरूर तैयार की है.भाजपा रायबरेली की सीट अटल काल में 1996 और 1998 में जीत चुकी है.यह और बात थी कि इस समय गांधी परिवार का कोई सदस्य यहां से मैदान में नहीं था. अब बीजेपी में मोदी युग है. देखना है क्या रायबरेली एक बार फिर इतिहास दोहराएगा.रायबरेली से 1977 में इंदिरा गांधी को हार का मुंह देखना पड़ा था. 1980 में यहां राजमाता विजयराजे सिंधिया को बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ा था. यहां उमा भारती की बात एक अन्य संदर्भ में करना जरूरी है. उमा रायबरेली तो नहीं आईं, लेकिन रायबरेली से चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच साध्वी ने झांसी कार्ड खूब खेला. उमा भारती ने कहा, 'चाहें कुछ हो जाये झांसी नहीं छोड़ूंगी' ने झांसी के मतदाताओं का मन मोह लिया.

अब बात एक अन्य वीआईपी सीट लखनऊ की जहां से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह चुनाव मैदान में हैं. यहां आम आदमी पार्टी ने अपना मुस्लिम प्रत्याशी उतार कर राजनाथ को जीवनदान दे दिया.'आप' ने फिल्म अभिनेता जावेद जाफरी को प्रत्याशी बनाया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन और प्रसार प्रतिनिधियों की. पारिश्रमिक योग्यता अनुसार. शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
ajaiup@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा
(गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश–201301,
PH : 120-6450888, 6451999

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

फैजाबाद

जनसूचना अधिकार अदालतें नौकरशाही पर लगाएगी लगाम

राकेश कुमार यादव

राज्य सूचना आयोग सूबे में नौकरशाही पर लगाम कसने के लिए जनसूचना अधिकार अदालतें लगाएगी. प्रदेश की पहली जनसूचना अदालत लोकसभा चुनाव 2014 के बाद फैजाबाद में लगाई जाएगी. यहां लंबित मामलों का निस्तारण मौके पर ही किया जाएगा. आयोग ने यह भी फैसला लिया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से राज्य सूचना आयुक्त सीधे जनपद मुख्यालय पर स्थित वादकारी और जनसूचना अधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे. राज्य सूचना आयुक्त स्वदेश कुमार ने 29 मार्च को फैजाबाद के अपने पहले दौरे के दौरान इस योजना के बारे में बताया. उन्होंने स्पष्ट किया कि विभिन्न विभागों के जनसूचना अधिकारी आरटीआई कानून के तहत मांगी गई सूचनाओं को न तो समय से देते हैं और न ही पूरी सूचनाएं दे रहे हैं. इसकी शिकायतें राज्य सूचना आयोग को मिली हैं. यही वजह है कि विभागीय जनसूचना अधिकारियों के मनमाने रवैये और लापरवाही पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सूचना आयोग गंभीर है. इन व्यवस्थाओं के बावजूद भी यदि जनसूचना अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, तो उन पर जुर्माना लगेगा और जुर्माने की राशि की कटौती उनके वेतन से की जाएगी.

राज्य सूचना आयुक्त ने बताया है कि अकेले फैजाबाद जनपद में सूचना संबंधी 765 आवेदन लंबित है, जो सूबे में सर्वाधिक है. अधिकांश लंबित मामले बेसिक शिक्षा अधिकारी, उच्च शिक्षा अधिकारी और ग्राम्य विकास विभाग से संबंधित हैं. उन्होंने यह माना कि जनसूचना अधिकार लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का सीधा अधिकार राज्य सूचना आयोग के पास नहीं है. अपीलों की सुनवाई में रिकवरी संबंधित अधिकारियों द्वारा ही की जा सकती है. फैजाबाद में 77 मामलों में अधिकारियों के खिलाफ राज्य सूचना आयोग ने जुर्माना किया है. संबंधित अधिकारियों को जुर्माना वसूली का आदेश दिया तो गया है, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी से जुर्माना की वसूली नहीं की गई है. यही नहीं यह भी मामला सामने में आया है कि जनसूचना अधिकारी आवेदनकर्ता को यह भी नहीं बताते कि अपीलीय अधिकारी कौन है. यही वजह है कि अधूरी सूचना से असंतुष्ट आवेदनकर्ता सीधे राज्य सूचना आयोग के पास अपील कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि मंडल और जिले के सभी प्रमुख अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि प्रत्येक विभाग में जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पद, मोबाइल नंबर या फोन नंबर सूचना पट लगाया जाए. साथ ही सूचना देते समय आवेदनकर्ता को भी इसकी जानकारी लिखित रूप से दी जाए. इसके बारे में सभी सूचनाएं विभाग की वेबसाइट पर भी डालने का निर्देश दिया गया. जिले में अपीलीय पीठ की स्थापना संभव नहीं है, लेकिन मंडल फैजाबाद में ही अदालत लगाकर अपीलों की सुनवाई करने का निर्णय ले लिया गया है, जिससे आस-पास के जनपद के लोगों को राजधानी लखनऊ का चक्कर न लगाना पड़े. इससे आवेदक का खर्च और समय बचेगा.

राज्य सूचना आयुक्त ने बताया है कि अकेले फैजाबाद जनपद में सूचना संबंधी 765 आवेदन लंबित है, जो सूबे में सर्वाधिक है. अधिकांश लंबित मामले बेसिक शिक्षा अधिकारी, उच्च शिक्षा अधिकारी और ग्राम्य विकास विभाग से संबंधित हैं. उन्होंने यह माना कि जनसूचना अधिकार लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का सीधा अधिकार राज्य सूचना आयोग के पास नहीं है. अपीलों की सुनवाई में रिकवरी संबंधित अधिकारियों द्वारा ही की जा सकती है. फैजाबाद में 77 मामलों में अधिकारियों के खिलाफ राज्य सूचना आयोग ने जुर्माना किया है.

राज्य सूचना आयुक्त स्वदेश कुमार ने जनसूचना अधिकारियों को उच्चाधिकारियों की उपस्थिति में स्पष्ट निर्देश दिया कि मांगी गई सूचना की तिथि से 30 दिन के अन्दर वांछित सूचना हर हाल में आवेदनकर्ता को दे दिया जाए. यदि 30 दिन के भीतर सूचना नहीं दी जाती, तो सभी सूचनाएं नि:शुल्क देने का प्रावधान जनसूचना अधिकार अधिनियम में है. आयोग की मंशा है कि शासन और प्रशासन में पारदर्शिता लाने के साथ पीड़ित पक्ष को समय से सूचना अवश्य उपलब्ध करा दिया जाए. जो सूचना अभिलेख में है, वही दी जानी चाहिए. कोई सूचना जेनरेट नहीं की जानी है तथा सूचना प्रोफार्मा में नहीं दिया जाना है. राज्य सूचना आयुक्त ने बताया कि जनसूचना अधिकार पूरी तरह जनता के लिए है. सन् 2005 से लागू इस कानून के क्रियान्वयन में कुछ कमी है, लेकिन इस अधिकार के प्रति बड़ी तेजी से जन जागरूकता बढ़ी है. यही वजह है कि प्रतिवर्ष राज्य आयोग के पास 70 हजार से अधिक मुकदमें आ चुके है. फैजाबाद में सन् 2009-10 के करीब 3 मामले लंबित हैं. ज्यादातर लंबित प्रकरण सन् 2012-13 के हैं. ■

परायों को अपना बनाती रही हैं लखनऊ की जनता

अजय कुमार

पूरे देश में नरेन्द्र मोदी भले ही भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर मैन बने हों, लेकिन लखनऊ में आज भी जीत के लिए बीजेपी को अपने पूर्व प्रधानमंत्री और पांच बार लखनऊ से सांसद रहे अटल बिहारी वाजपेयी का ही सहारा है. करीब दस वर्षों से सक्रिय राजनीति से दूर चल रहे अटल का लखनऊ में आज तक भाजपा विकल्प तैयार नहीं कर पाई है. अटल बिहारी वाजपेयी के सहारे 1991 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सिर जीत का सेहरा बंधा था. इसके बाद हुए सभी छह चुनावों में भाजपा का ही परचम लहराता रहा. अटल ने राजनीति से दूरी बनाई तो 2009 में उनकी खड़ाऊ पकड़ कर लालजी टंडन ने लखनऊ का प्रतिनिधित्व किया. मौजूदा भाजपा सांसद लालजी टंडन की जगह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह मैदान में ताल ठोंक रहे हैं. लालजी टंडन की तरह राजनाथ भी अटल के सहारे अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं, शायद यही वजह है कि उनको मीडिया के सामने बताना पड़ रहा है कि वह आज भी महीने में चार बार अटल जी के पैर छूते हैं. लखनऊ की जनता जिसे एक बार अपना बना लेती है, उसे आसानी से नहीं छोड़ते. इतना ही नहीं लखनऊ के मतदाताओं ने कभी भी यह सोच कर अपना नुमाइंदा नहीं चुना कि वह कहां का रहने वाला है. लखनऊ का सांसद बनने वालों में बाहर के नेताओं की फेहरिस्त लंबी है. हाल के वर्षों में मौजूदा सांसद लालजी टंडन को छोड़कर पिछले कई लोकसभा चुनावों में बाहर से आए नेताओं को ही यहां की जनता ने प्रतिनिधि के तौर पर लोकसभा भेजना ज्यादा पसंद किया. पांच बार लखनऊ से चुनाव जीते भाजपा नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, तीन बार कांग्रेस के टिकट से संसद पहुंचने वाली शीला कौल, विजय लक्ष्मी पंडित, पुलिन बनर्जी, मांधाता सिंह, हेमवती नंदन बहुगुणा, आनंद नारायण मुल्ला सभी बाहर के थे.

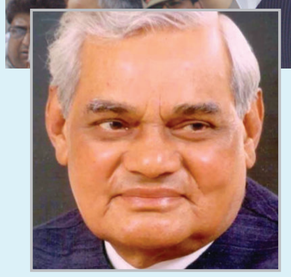

15 बार हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर यहां के मतदाताओं ने सिर्फ दो बार अन्य दलों (जनता पार्टी और जनता दल) के प्रत्याशी को एवं एक बार निर्दलीय उम्मीदवार को अपना प्रतिनिधि चुना. लखनऊ कभी नेहरू-गांधी खानदान का मजबूत गढ़ हुआ करता था, जैसे आज अमेठी और रायबरेली है. 1952 में हुए पहले चुनाव में जवाहर लाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित यहां से जीतीं. बाद में विजय लक्ष्मी राजदूत बनकर रूस चली गईं. इसके बाद हुए उप-चुनाव में नेहरू की ही बहन राजवती नेहरू विजयी हुईं. 1957 में कांग्रेस के पुलिन बनर्जी और 1962 में बीके धवन के सिर जीत का सेहरा बंधा. इसके बाद 1971-1980 और 1984 में यह सीट एक बार फिर नेहरू खानदान की शीला कौल के पास रही. कांग्रेस को आपातकाल के बाद यहां बड़ा झटका लगा और 1977 में जनता पार्टी के टिकट से हेमवती नंदन बहुगुणा चुनाव जीत गए. वहीं 89 में जनता दल के टिकट से मांधाता सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे. यह इत्तेफाक ही है कि भले ही लखनऊ के किसी भी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की साइकिल अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाई हो, लेकिन 1967 में यहां निर्दलीय उम्मीदवार और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज पंडित आनंद नारायण मुल्ला की साइकिल (मुल्ला का चुनाव चिन्ह) खूब दौड़ी थी. आनंद नारायण मुल्ला के बाद लखनऊ से कभी कोई निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाया. फिल्म अभिनेता राज बब्बर, डॉ. कर्ण सिंह, राम जेठमलानी, भगवती सिंह, दाऊ जी गुप्त जैसे नेताओं ने भी लखनऊ से भाग्य अजमाया, लेकिन उन्हें जीत नसीब नहीं हुई.

बात लखनऊ के सियासी मिजाज की करें, तो यहां कभी किसी प्रत्याशी के पक्ष में धुव्रीकरण जैसे हालात नहीं बने. 2004 और 1999 के लोकसभा चुनाव में यहां से बसपा सुप्रीमो मायावती ने और 1998 तथा 2009 में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतार कर वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश जरूर की थी, लेकिन इन दलों का यह पैतरा चल नहीं पाया. 1998 में मुंबई की चकाचौंध से आए सपा प्रत्याशी मुजफ्फरअली जरूर भाजपा प्रत्याशी अटल बिहारी वाजपेयी को टक्कर देते नजर आए और दूसरे स्थान पर रहे. इसके अलावा, कभी कोई मुस्लिम प्रत्याशी मजबूती के साथ मुकाबले में खड़ा नहीं दिखा. यही वजह है अबकी से यहां कांग्रेस - बसपा और समाजवादी पार्टी किसी ने मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है. 1998 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, जब मैदान में कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है. समाजवादी पार्टी को लेकर काफी अटकलें लगी थी कि वह मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतार सकती है, लेकिन जब उसने भी चुनावी संध्या में करीब डेढ़ वर्ष पूर्व घोषित प्रत्याशी अशोक वाजपेयी का टिकट काट कर दूसरे ब्राहमण प्रत्याशी अभिषेक मिश्र (अखिलेश सरकार में मंत्री और लखनऊ, उत्तर प्रदेश से विधायक) को मैदान में उतारा तो सपा के मुस्लिम प्रत्याशी वाले कयासों पर विराम लग गया.

बात 16 वीं लोकसभा चुनाव के लिए लखनऊ में सजी सियासी बिसात की करें, तो अबकी से हवा का रुख काफी बदला-बदला लग रहा है. लखनऊ का सांसद बनने के लिए दो विधायक (कांग्रेस की लखनऊ कैंट से विधायक डॉ. रीता बहुगुणा जोशी और सपा के अभिषेक मिश्रा) के अलावा गाजियाबाद संसदीय सीट छोड़कर लखनऊ में किस्मत अजमाने आए राजनाथ सिंह और पिछली बार भी बसपा के टिकट से ताल ठोंकने वाले नकुल दुबे प्रमुख रूप से इस बार भी मैदान में हैं. ऐसा लगता है कि लखनऊ में जो भी लड़ेगा, वह भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह के खिलाफ ही लड़ेगा. ऐसा अटल के नाम और राजनाथ के व्यक्तित्व और मोदी लहर के कारण होता दिख रहा है. राजनाथ ने टिकट काटे जाने से नाराज चल रहे मौजूदा सांसद और बुजुर्ग नेता लाल जी टंडन के हाथों में अपने चुनाव की कमान सौंप कर उनकी नाराजगी पर पानी डालने का पूरा काम कर दिया है. पिछली बार कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. रीता बहुगुणा जोशी ने भाजपा के लाल जी टंडन को कड़ी टक्कर दी थी. इस बार भी ऐसा ही होता दिख रहा है. हाल में ही लखनऊ में समाजवादी पार्टी को अगर अपने सोलह महीने पहले से घोषित प्रत्याशी अशोक वाजपेयी को बदल कर राज्य मंत्री अभिषेक मिश्र को प्रत्याशी बनाकर नया दांव चला है. अभिषेक मिश्र युवा हैं, पढ़े-लिखे हैं और सबसे बड़ी बात सीएम अखिलेश यादव के करीबी हैं. यही नहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत भी दर्ज करा चुके हैं. दो वर्षों के समाजवादी सरकार के कार्यकाल पर भले ही उंगली उठ रही हो, लेकिन अभिषेक मिश्र के कार्यकाल से स्थानीय जनता संतुष्ट नजर आती है. अभिषेक पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे.

जातीय गणित पर नजर डाली जाए तो लखनऊ में करीब साढ़े चार लाख मुस्लिम, तीन लाख से ऊपर ब्राह्मण, डेढ़ लाख के करीब पहाड़ी, दो लाख कायस्थ, एक लाख से ऊपर पिछड़ा वर्ग और ढाई लाख दलित वोटर है. 2009 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों के मद्देनजर सपा ने नफीसा अली को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्हें सिर्फ साठ हजार वोट मिल पाया और जमानत तक जब्त हो गई थी. कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी की ब्राह्मणों में स्वीकार्यता देख मुस्लिम उनके पाले में खड़े हो गए. नतीजा यह हुआ जो लालजी

15 बार हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर यहां के मतदाताओं ने सिर्फ दो बार अन्य दलों(जनता पार्टी और जनता दल) के प्रत्याशी को एवं एक बार निर्दलीय उम्मीदवार को अपना प्रतिनिधि चुना. लखनऊ कभी नेहरू-गांधी खानदान का मजबूत गढ़ हुआ करता था, जैसे आज अमेठी और रायबरेली है. 1952 में हुए पहले चुनाव में जवाहर लाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित यहां से जीतीं. बाद में विजय लक्ष्मी राजदूत बनकर रूस चली गईं. इसके बाद हुए उप-चुनाव में नेहरू की ही बहन राजवती नेहरू विजयी हुईं. 1957 में कांग्रेस के पुलिन बनर्जी और 1962 में बीके धवन के सिर जीत का सेहरा बंधा. इसके बाद 1971-1980 और 1984 में यह सीट एक बार फिर नेहरू खानदान की शीला कौल के पास रही.

टंडन आसानी से जीतते हुए दिख रहे थे, वह सिर्फ 40 हजार वोटों से जीत हासिल कर पाए. सपा ने 2009 में मुस्लिम कार्ड खेला था तो 2004 में बीएसपी यह दांव चल चुकी थी, लेकिन मुसलमानों को जब लगा कि लखनऊ में बसपा का आधार दलित वोट बहुत ज्यादा नहीं है और दूसरी जातियां बसपा को वोट नहीं करेगीं तो अल्पसंख्यक मतदाताओं ने इस चुनाव में सपा की डॉ. मधु गुप्ता का समर्थन कर दिया. नतीजा यह हुआ कि बसपा का मुस्लिम उम्मीदवार सिर्फ 50 हजार वोट पा सका था और जमानत जब्त हो गई थी.

खैर राजनीतिक पंडितों का मानना है कि कांग्रेस-बसपा और सपा प्रत्याशी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़े तो इसका फायदा उनसे अधिक बीजेपी के राजनाथ सिंह को मिलेगा. फिलहाल, मुस्लिम मतदाताओं में भ्रम की स्थिति नजर आ रही है, लेकिन मतदान वाले दिन वह जरूर तय कर लेंगे की भाजपा प्रत्याशी को कौन गैर भाजपाई टक्कर दे सकता है. उसी के अनुसार वह मतदान कर देंगे. इससे सपा, बसपा और कांग्रेस किसी को भी फायदा हो सकता है. आम आदमी पार्टी ने अभी तक यहां से प्रत्याशी नहीं तय किया है. वहीं तृणमूल कांग्रेस ने मो. सरवर मलिक को मैदान में उतारा है. लखनऊ संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों में यहां की पांच सीटों पर कभी भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहता था, लेकिन परिसीमन के बाद हुए विधान सभा चुनाव में पांच में से तीन सीटों पर सपा ने कब्जा कर लिया और कांग्रेस और भाजपा के खाते में एक-एक ही सीट आई. ■

रायबरेली

किसी भी दल के लिए राह आसान नहीं है

दर्शन शर्मा

लोकसभा चुनाव में रायबरेली काफी अहमियत रखता है. यह सियासी जमीन कांग्रेस को विरासत में मिली है. यहां से अधिकांशत: गांधी परिवार के सदस्य ही जीतते रहे हैं. यही कारण है कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी, भाजपा और आप ने अपने-अपने प्रत्याशी उतारने में काफी देर लगाई. बसपा ने अपना कमजोर प्रत्याशी यहां उतारकर इतिश्री समझ ली. आमतौर पर सियासी पार्टियों में इस बात को लेकर होड़ मची रहती है कि कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ प्रत्याशी उतारने की पहल कौन करे. दरअसल, कांग्रेस आलाकमान के किले में घुस पाना बहुत कठिन है. यहां से बहाने बनाकर प्रत्याशी चुनाव

लड़ने से बचते हैं. शायद यही कारण रहा होगा कि झांसी से टिकट पाई साध्वी उमा भारती का नाम जब सोनिया के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए चर्चा में आया, तो उन्होंने दो टूक जवाब देते हुए कह दिया कि मैं झांसी नहीं छोड़ूंगी. इसी असमंजस में भाजपा प्रत्याशी उतारने में आगे पीछे होती देखी गई. हालांकि, रायबरेली के लिए भाजपा में कई दावेदार है. भितरघात को बचाने और सशक्त उम्मीदवार खोजने के चक्कर में भाजपा बहुत पीछे हो गई है. वह कभी सुब्रहमण्यम स्वामी की, तो कभी उमा भारती या स्मृति ईरानी को लड़ाने की बात कर चर्चा में आती रही. इसी टालमटोल में मार्च चला गया, लेकिन भाजपा, सपा और आप अपने-अपने प्रत्याशी नहीं उतार सके. यहां तक कि कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ प्रबल प्रत्याशी उतारने की हुंकार भरने वाली आम आदमी पार्टी की हवा तब निकल गई, जब शाजिया इल्मी ने कई बहाने बनाकर रायबरेली से लड़ने से साफ मना कर दिया. बसपा ने काफी पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी. बसपा के उम्मीदवार प्रवेश सिंह का स्थानीय जनाधार नकारात्मक है. बसपा की ओर से कमजोर प्रत्याशी उतारा गया है.

केन्द्र में कांग्रेस का समर्थन करने वाली सपा की बात करें तो वह भला ऐसा बचकाना काम क्यों करेगी. केन्द्र में तीसरे मोर्चे की बात करने वाली समाजवादी पार्टी ने रायबरेली से चुनाव न लड़ने का फैसला किया है. ऐसा इसलिए माना जा रहा है, क्योंकि अब तक न तो यहां से प्रत्याशी घोषित हुआ और न ही यहां से लड़ने की कोई चर्चा ही सपा की ओर से हो रही है. कहा जा रहा है कि कन्नौज को लेकर यहां सपा अपना राजनीतिक धर्म निभाएगी. इसीलिए अब तक एम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई.

बहरहाल, रायबरेली में कांग्रेस अपनी जीत पक्की मान रही है. 1951 से लेकर अब तक के कांग्रेस के इतिहास को देखें तो गांधी परिवार इस सीट पर अपना कब्जा करती आई है. 1977 में जनता पार्टी के राजनारायण तथा 1996 और 1998 में भाजपा के अशोक सिंह यहां से जीते थे. ■

उत्तराखंड में 'उक्रांद' फिर कायाकल्प करने को आतुर

राजकुमार शर्मा

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में महती भूमिका निभाने वाला उत्तराखण्ड क्रान्ति दल आम चुनाव के पूर्व कायाकल्प करने की तैयारी में दिख रही है. नेताओं की आपसी टकराहट के चलते बिखरा उक्रांद एक बार फिर से एक छत के नीचे आने का प्रयास कर रहा है. इसमें इसे काफी हद तक सफलता मिल चुकी है, टूट के लिए जिम्मेदार नेताओं ने मन का मैल साफ करने की इच्छा जता दी है. एका के लिए फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है, बावजूद इसके एक बार फिर से उक्रांद में एका की राजनीति उक्रांद (ऐरी) के अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी के इर्द-गिर्द घूमती दिखायी दे रही है. एका के लिए तैयार फॉर्मूले को भले ही सभी ने सैद्धांतिक सहमति दे दी हो, लेकिन ऐरी व अन्य नेताओं के लिए इस पर अमल करना आसान नहीं दिखायी दे रहा है. ऐसे में आशंका जतायी जा रही है कि एकता का फॉर्मूला ही कहीं इसके आड़े न आ जाए. उक्रांद के टूटने का इतिहास कोई नया नहीं है. राज्य गठन के बाद जिस तरह से उक्रांद में बिखराव शुरू हुआ, इसने थमने का नाम नहीं लिया है. आलम यह है कि अब उक्रांद का अस्तित्व ही खतरे में है. वर्तमान में उक्रांद के कई घटक दल हैं. इनमें उक्रांद (पी) की कमान त्रिवेंद्र सिंह पंवार के हाथों में है, तो उक्रांद(ऐरी) के नेता काशी सिंह ऐरी हैं. इसके अतिरिक्त उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक, जनतांत्रिक उत्तराखंड क्रांति दल व यूकेडी यूनाइटेड भी है. कभी उक्रांद के नेता रहे, अब इन दलों की कमान संभाले हुए हैं. उक्रांद के टूटने से भले ही इन नेताओं की महत्वाकांक्षाएं पूरी हो गई हों, राजनीतिक दृष्टिकोण से आज ये पहचान के लिए तरस रहे हैं. जनता की रुसवाई के बाद अब इन नेताओं को लगने लगा है कि एकता के बिना इनकी स्वीकार्यता संभव नहीं है. ऐसे में महत्वाकांक्षा की टकराहट अब राजनैतिक पहचान को तलाशने लगी है. इसी पहचान ने अब उक्रांद नेताओं को एक छत के नीच आने को मजबूर कर दिया है. उक्रांद (पी) अपने को इस मुहिम से अलग किए हुए है. वह अभी भी एकला चलो की रणनीति अपनाए हुए है. विगत दिनों एका के लिए उक्रांद(पी) को छोड़ सभी घटक दलों ने एक साथ बैठ कर एक मंच पर आने के संकेत दिए. दल के नेताओं की ओर से एकता के लिए स्थाई फॉर्मूला अख्तियार करने की बात कही गई. सभी ने माना कि दल में बिखराव से उक्रांद की पहचान संकट में आ गई है. इस पहचान को कायम रखने व जनता का विश्वास हासिल करने के लिए अब महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना होगा. इस बार को उक्रांद के विभिन्न घटक दलों के नेताओं ने स्वीकार भले ही कर लिया हो, इससे बाहर निकल पाना आसान नहीं है. इसी को देखते हुए अब दल के संविधान में संशोधन कर कई बदलाव किए जाने की बात कही गई है. दल में टूट के लिए हमेशा अध्यक्ष का सर्वाधिकार होना पाया गया है. इसलिए नए संविधान में अध्यक्ष की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किए जाने की बात कही जा रही है. यही नहीं घटक दलों के अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों को त्यागपत्र देकर नए संविधान के तहत उक्रांद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी. जिस फॉमूले में सभी घटक दलों के नेताओं ने सैद्धांतिक सहमति दी है. इसके तहत दल के वरिष्ठ नेताओं को पदों से दूर रख नया नेतृत्व चुने जाने की बात कही गई है. वतर्मान में उक्रांद के नाम पर उक्रांद (पी) व उक्रांद(ऐरी) ही अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो पाए है. उक्रांद(पी) ने एका के लिए खुद को इन घटक दलों से अलग किया हुआ है. ऐसे मे उक्रांद (ऐरी) की घटक दलों में सबसे सशक्त है. एकता के लिए जो फॉर्मूला निकाला गया है. इसमें ऐरी सहित सभी घटक दलों के अध्यक्षों को पद का मोह त्यागना पड़ेगा. राजनैतिक विशेषज्ञों की माने तो कुर्सी के लिए कभी जिस महत्वाकांक्षा के चलते इन नेताओं ने उक्रांद में टूट को स्वीकार किया, एकता के लिए अब ये नेता अपनी महत्वकांक्षा को छोड़ पाएंगे, इसमें संदेह है. एकता के लिए मैंने प्रयास कर सभी को एक साथ बैठाया. उक्रांद के सभी घटक दलों के कार्यकर्ताओं ने इस प्रयास की सराहना की है. एकता के लिए फॉर्मूला तैयार करने का दायित्व मुझे सौंपा गया है. इसके तहत संविधान में संशोधन करना है. सभी घटक दलों के पदाधिकारियों को पद से इस्तीफा सौंपकर नई कार्यकारिणी का गठन किया जाना है. सभी वरिष्ठ साथियों को संरक्षक की भूमिका में रहना होगा. दल को नया नेतृत्व दिए जाने की बात कही जा रही है. ■

मंत्रिमंडल में फेरबदल से रावत सुलझाएंगे संकट

राजकुमार शर्मा

सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री को अपनी सरकार बचा लेने की धमकी दे कर हरीश रावत के माथे पर पसीना उकेर दिया है. सतपाल महाराज के कांग्रेस छोड़ भाजपा में चले जाने और विजय बहुगुणा की नाराजगी से प्रदेश की हरीश रावत सरकार के सामने सियासी संकट खड़ा हो गया है. उत्तराखण्ड की बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपना सियासी गणित ठीक करने और आसन्न संकट के निजात के लिए मंत्रिमंडल में फेरबदल करने के मूड में है. फिर भी एक रणनीति के तहत मुख्यंत्री रावत ने किसी भी सदस्य को बाहर करने की किसी भी सम्भावना से इन्कार किया है. विजय बहुगुणा के साथ संकट को हल करने के लिए नए फॉर्मूला पर सहमति बन रही है. विजय बहुगुणा ने कांग्रेस नेतृत्व के सामने जो फॉर्मूला रखा है. इसके मुताबिक वह टिहरी से खुद लड़ने या अपने पुत्र साकेत को लड़ाने के लिए तभी तैयार होंगे, जब इनकी कुछ शर्तों को मान लिया जाए. जानकार सूत्रों की मानें तो बहुगुणा ने कांग्रेस नेतृत्व और मुख्यमंत्री हरीश रावत के सामने जो फॉर्मूला पेश किया है, इसके मुताबिक मंत्रिमंडल में टिहरी के निर्दलीय विधायक दिनेश धनै और बदरीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी को जगह दी जा सकती है. दिनेश धनै विजय बहुगुणा के करीबी माने जाते हैं तो राजेंद्र भंडारी सतपाल महाराज के. सूत्रों की मानें तो इस फेरबदल की गाज दो मंत्रियों सतपाल महाराज की धर्मपत्नी अमृता रावत और मंत्री प्रसाद नैथानी पर गिर सकती है.

संभावना जताई जा रही है कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करती है तो महाराज समर्थक इन विधायकों को प्रदेश सरकार एडजस्ट करने की कोशिश करेगी जो महाराज के निर्देशों को न मानने की क्षमता रखते हैं. सूत्रों की मानें तो सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस के हरीश रावत गुट के विधायक कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं.

माना जा रहा है कि यह बदलाव लोकसभा चुनाव के बाद भी संभव हो सकता है और बहुत जरूरी हुआ तो इसके पहले भी. इतना ही नहीं विजय बहुगुणा गुट ने अपने और महाराज गुट के चार विधायकों को संसदीय सचिव का पद देने की भी मांग की है. कांग्रेस आलाकमान के सामने बहुगुणा गुट ने नरेंद्रनगर विधायक सुबोध उनियाल को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने या इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा है. उनियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर ही हरीश रावत गुट कुछ सहमत नजर आ रहा है. सुबोध उनियाल विजय बहुगुणा के दाएं हाथ माने जाते हैं. कांग्रेस की राजनीति पर नजर रखने वालों का कहना है कि महाराज के भाजपा में जाने के बाद महाराज समर्थक विधायक कांग्रेस आलाकमान के राडार पर हैं. संभावना जताई जा रही है कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करती है तो महाराज समर्थक इन विधायकों को प्रदेश सरकार एडजस्ट करने की कोशिश करेगी जो महाराज के निर्देशों को न मानने की क्षमता रखते हैं. सूत्रों की मानें तो सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस के हरीश रावत गुट के विधायक कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं. इसी को देखते हुए महाराज गुट के एक और विधायक व डिप्टी स्पीकर डॉ. अनुसूया प्रसाद मैखुरी को विधानसभा अध्यक्ष बनाने का दांव भी खेला जा सकता है. मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल हरीश रावत के निकटस्थों में से एक माने जाते हैं. सूत्रों की मानें तो डॉ. मैखुरी के पिछले कुछ दिनों में गैरसैण में विधानभवन को लेकर दिए जा रहे बयानों को इस नई परिस्थिति से ही जोड़ा जा रहा है. ■

हिमालय, आपदा और जलनीति चुनावी घोषणा पत्र में शामिल हो

रेनु शर्मा

देश के पर्यावरणविद् चाहते हैं कि हिमालय, आपदा और जलनीति चुनावी घोषणा पत्र में शामिल हो. देश में हो रहा आम चुनाव राजनीतिक दलों पर दबाव डालने का सबसे बेहतर मौका होते हैं. इसी को देखते हुए प्रदेश के पर्यावरणविदों, नीति विशेषज्ञों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सभी राजनीतिक दलों से मांग की है कि हिमालय, आपदा और जलनीति को अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करें. इनका कहना है कि उत्तराखंड और अन्य हिमालयी राज्यों का भला तभी हो सकता है जब ये मुद्दे राजनीति के केंद्र में आएं. हिमालय नीति का मुद्दा उत्तराखंड में 16-17 जून 2013 को आई आपदा के बाद कई संगठनों ने प्रभावी रूप से उठाया था. कई जनघोषणा पत्रों में अलग हिमालय नीति की बात कही गई है. नदी, पर्यावरण संरक्षण अभियान के सक्रिय सदस्य एवं उत्तराखण्ड सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष सुरेश भाई का कहना है कि पिछले पांच वर्षों में उत्तराखण्ड समेत तमाम हिमालयी राज्यों के साथ देश भर में हिमालय के लिए अलग नीति बनाने और हिमालयी नदियों को बचाने के सवाल पर कई तरह के आंदोलन हुए हैं. केंद्र ने हिमालयी नदियों के सिरहानों पर प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन सुरंग बांधों को रोकने की पहल भी की है. इसके साथ ही उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री हरीश रावत, सांसद प्रदीप टम्टा, केन्द्र के कैबिनेट मंत्री जयराम रमेश, भाजपा की नेता सुषमा स्वराज, पूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद्र खंडूड़ी, उमा भारती आदि कई नेताओं ने हिमालय बचाने के विषय पर गंभीरता दिखाई थी. उन्होंने हिमालय नीति बनाने और हिमालय क्षेत्र में ईको फ्रेंडली विकास की अवधारणा को स्वीकारा है, दु:खद बात है कि चुनाव में भाजपा मोदी, कांग्रेस राहुल और बाकी दल तीसरे विकल्प पर ही जोर दे रहे हैं और जनता के मुद्दों से पीछे हट रहे हैं. पर्यावरणविद् डॉ. अनिल जोशी का कहना है कि हिमालय देश को 50 प्रतिशत से भी अधिक पानी देता है. हिमालय एशिया के बड़े भू-भाग की जलवायु को प्रभावित करता है. यहां अलग-अलग क्षेत्रों में रहन-सहन, संस्कृति, आवास की स्थितियों में भी विविधता दिखाई देती है. इसके रहते भी क्या हिमालय बचाने का मुद्दा राजनैतिक दलों के घोषणा पत्रों में नहीं होना चाहिए. प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव डॉ. आरएस टोलिया का कहना है हिमालय का पारिस्थिकीय तंत्र अत्यंत संवेदनशील है. इस नए पर्वत पर प्राकृतिक संसाधनों का बेहिसाब दोहन और इससे सम्बन्धित कई चुनौतियों से प्रभावित भी दिखाई दे रहा है. जलवायु परिवर्तन भी हिमालय पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है. बाढ़, भूकम्प, सूखा, वनाग्नि जैसी घटनाओं की बार-बार पुनरावृत्ति हो रही है. लम्बी अवधि की बारिश, लम्बी अवधि का सूखा, अनियमित और बेमौसमी बारिश ने हिमालय में कहर बरपाना प्रारम्भ कर दिया है. इससे अधिकतर छोटे किसान प्रभावित हो रहे हैं. यह केवल ऊपरी हिस्सों में रहने वाले समुदायों को ही नहीं देशभर में इसके बहाव क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों का जीवन एवं जीविका प्रभावित हो रही है. इनका कहना है कि इसके लिए सरकारों को अपनी नीतियों में पर्वतों की जरूरतों के हिसाब से बदलाव लाना होगा. ■